II आर्थिक समीक्षा

विकट भू-आर्थिक विखंडन, खाद्य, ऊर्जा और वस्तुओं की ऊंची वैश्विक कीमतों, आक्रामक मौद्रिक नीति सख्ती और प्रभाव-विस्तार के माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में आघात-सहनीयता प्रदर्शित की है। अतिव्यापी आपूर्ति आघातों के कारण, वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति कई महीनों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी स्वीकार्य स्तर से ऊपर बनी रही। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ, मौद्रिक और ऋण की स्थिति नीतिगत रुख के अनुरूप विकसित हुई, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए लक्षित राजकोषीय उपायों ने समष्टिआर्थिक स्थिरता को मजबूत किया। भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा धारणीय बना रहा और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ जिससे ऋण वृद्धि में फिर से तेजी आई।

II.1.1 भू-राजनीतिक वैर भाव में तेजी आने के बाद, दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के कारण वित्तीय स्थितियों में आई सख्ती ने, 2022 के दौरान उच्चतर अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक समष्टिआर्थिक परिणामों को मंद कर दिया। अल्पकालिक ओमीक्रॉन लहर और 31 मार्च 2023 तक दुनिया की 64.20 प्रतिशत आबादी का पूर्ण टीकाकरण करते हुए, विश्वव्यापी स्तर पर सफल टीकाकरण अभियान के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता और सुदृढ़ हुई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 के लिए वैश्विक संवृद्धि अनुमान को अक्टूबर 2022 में रहे 3.2 प्रतिशत से संशोधित कर अप्रैल 2023 में 3.4 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, 2022 के लिए वैश्विक व्यापार (वस्तुएँ और सेवा) संवृद्धि को जनवरी 2023 में रहे 5.4 प्रतिशत से घटाकर अप्रैल 2023 में 5.1 प्रतिशत कर दिया गया था। 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति जो एक साल पहले 4.7 प्रतिशत थी, 8.7 प्रतिशत पर अस्वाभाविक रूप से उच्च रही, साथ ही मुद्रास्फीति अधिकांश देशों में लक्ष्य से अधिक थी। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह सुस्त और अस्थिर बना रहा।

II.1.2 दुनिया भर में वित्तीय स्थितियों के समकालिक रूप से सख्ती, राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफल में तेज वृद्धि में परिलक्षित हुई। वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों में भी तेज उतार-चढ़ाव देखा गया जो व्यापक जोखिम-विमुख रुझानों के बीच वैश्विक प्रभाव-विस्तार के प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिकी डॉलर की निरंतर मूल्यवृद्धि ने अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्राओं पर निरंतर मूल्यह्रास दबाव डाला जिससे मूल्यांकन नुकसान के कारण इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार बफर का एक उल्लेखनीय हिस्सा घट गया।

II.1.3 घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान सुधार को गति मिली क्योंकि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला सामान्य हो गई और संपर्क-गहन क्षेत्रों में गतिविधि में फिर से तेजी आई। कॉर्पोरेट क्षेत्र और बैंकों के सुदृढ़ तुलनपत्रों से ऋण मांग में फिर से तेजी आई, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि ने भी सुगम बनाया। 2022-23 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक जीडीपी में 7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई।

II.1.4 यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, 2022-23 में 4.5 प्रतिशत तक घट जाने की बजाय, बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई। मूल्य दबाव में वृद्धि व्यापक और अड़ियल बनी रही और वर्ष के कई महीनों में मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन स्तर से अधिक रही। रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की और समायोजन को वापस लेने हेतु मौद्रिक

नीति के रुख में बदलाव किया तथा संवृद्धि के प्रति सजग रहते हुए, मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी। सरकार ने मुद्रास्फीति को आकार देने में आपूर्ति पक्ष के कारकों के प्रभुत्व को देखते हुए, कई लक्षित मद-विशिष्ट मुद्रास्फीति-विरोधी उपाय शुरू किए। विकास-समर्थक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में बड़ी वृद्धि की दिशा में सार्वजनिक व्यय को निर्देशित करते हुए, राजकोषीय नीति ने, सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। पूंजी निर्माण 2022-23 के दौरान विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरा।

II.1.5 वर्ष के दौरान अधिशेष चलनिधि में कमी के चलते वित्तीय स्थिति सहायक बनी रही। मुद्रा बाजार ब्याज दरों में मोटे तौर पर नीति रेपो दर में बदलावों के अनुरूप वृद्धि हुई। वैश्विक प्रभाव-विस्तार के असर के कारण मध्यम से लंबी अवधि के राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई लेकिन मीयादी प्रीमियम कोविड-पूर्व स्तर से नीचे रहा। बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफलों में वृद्धि और उच्चतर ऋण स्प्रेड का अनुसरण करते हुए, 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई। इक्विटी बाजारों ने बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, साथ ही, कभी-कभी वैश्विक इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव से अलग भी हुए। निवल पोर्टफोलियो बहिर्वाह को प्रेरित करते जोखिम-विमुख रुझानों के बीच, 2022-23 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से, भारतीय रुपया प्रभावित हुआ।

II.1.6 इस पृष्ठभूमि में , शेष अध्याय को छह खंडों में बांटा गया है। वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद खंड 3 में वस्तु की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के चालकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। मौद्रिक समुच्चय और वित्तीय बाजारों में हुई प्रगति क्रमशः खंड 4 और 5 में प्रस्तुत की गई है। खंड 6 में सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) पर चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 7 में बाह्य क्षेत्र में हुई प्रगति का विश्लेषण किया गया है।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया और 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वर्ष 2022 की शुरुआत में ओमीक्रॉन लहर से उपजे भय को छोड़कर, वर्ष के अधिकांश भाग में कोविड-19 काफी हद तक निचले स्तर पर सिमटा रहा, जिससे उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद मिली। संपर्क-गहन गतिविधि धीरे-धीरे वर्ष के दौरान पुनर्जीवित हुई और दमित मांग के निर्मोचन ने घरेलू गतिविधि को बढ़ावा दिया। मजबूत समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संतुलित तुलनपत्रों में परिलक्षित एक आघात-सह वित्तीय प्रणाली, और एक डिलीवरेज्ड कॉर्पोरेट क्षेत्र ने प्रतिकूल वैश्विक प्रभाव-प्रसार का सामना करने के लिए आघात-सहनीयता प्रदान की।

II.2.2 इस खंड में, समग्र मांग का घटक-वार विश्लेषण उप-खंड 2 में दिया गया है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में समग्र आपूर्ति स्थिति में हुई प्रगति के आकलन की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। रोजगार और श्रम बाजार में हुई प्रगति का विश्लेषण (ड्रिल-डाउन) उप-खंड 4 में दिया गया है। अंतिम उप-खंड में नीतिगत दृष्टिकोण दिये गए हैं।

2. समग्र मांग

II.2.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) ने संकेत दिया कि वास्तविक जीडीपी द्वारा मापी गई समग्र मांग ने एक साल पहले 9.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1)। इसके साथ, स्तर के संदर्भ में वास्तविक जीडीपी ने 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तर को 9.9 प्रतिशत से पार कर लिया। पिछले तीन वर्षों के लिए जीडीपी वृद्धि को 20

आधार अंक (बीपीएस) [2019-20], 80 बीपीएस (2020-21) और 40 बीपीएस (2021-22) तक संशोधित किया गया था, जो दर्शाता है कि विकास की गति शुरुआती अनुमानों की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि उपभोग और निवेश मांग दोनों में तेजी आई लेकिन बाहरी मांग की प्रतिकूल स्थिति और इसके परिणामस्वरूप निवल निर्यात में बड़े घाटे ने 2022-23 में वृद्धि को नीचे खींच लिया। 2022-23 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक गति में बहुत तेजी के साथ, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 9.6 प्रतिशत पर रहते हुए सुदृढ़ बनी रही। हालांकि, 2022-23 की तीसरी तिमाही में, इसकी गति कम हो गई (चार्ट II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 2)।

II.2.4 2022-23 में समग्र मांग की स्थिति में उतार-चढ़ाव के पीछे इसके प्रमुख घटकों के बीच संरचनात्मक बदलाव थे (चार्ट II.2.2)। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7.3 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई, जो यात्रा और पर्यटन सहित संपर्क-गहन गतिविधि में वृद्धि और 2022-23 में त्योहारी समय में मांग में आई वृद्धि के कारण है। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत पर मंद रही क्योंकि सरकार ने वृद्धि और निवेश को समर्थन देने के लिए पूंजीगत व्यय

सारणी II.2.1. वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

घटक	वृद्धि (प्रतिशत में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
I. कुल उपभोग व्यय	**7.0**	**5.0**	**-4.6**	**10.5**	**6.4**
निजी	7.1	5.2	-5.2	11.2	7.3
सरकार	6.7	3.9	-0.9	6.6	1.2
II. सकल पूंजी निर्माण	**6.2**	**-6.0**	**-11.6**	**22.2**	**9.6**
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	11.2	1.1	-7.3	14.6	11.2
शेयरों में बदलाव	27.3	-58.7	-85.5	687.8	1.9
क़ीमती	-9.7	-14.2	26.4	34.0	-14.8
III. निवल निर्यात					
निर्यात	11.9	-3.4	-9.1	29.3	11.5
आयात	8.8	-0.8	-13.7	21.8	18.8
IV. जीडीपी	**6.5**	**3.9**	**-5.8**	**9.1**	**7.0**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

को बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए सुदृढ़ीकरण पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा। व्यय की गुणवत्ता में सुधार, आगे चलकर धारणीयता और संवृद्धि को जोखिम-रहित बनाने के लिए अच्छा संकेत है। 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी

चार्ट II.2.1: जीडीपी संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और एसएएआर

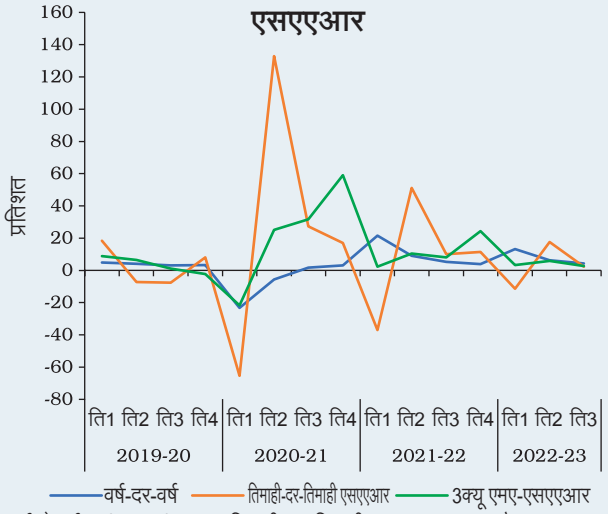

वाईओवाई: वर्ष-दर-वर्ष तिमाही-दर-तिमाही एमए: चल औसत
एसएएआर: मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.2.2: जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान

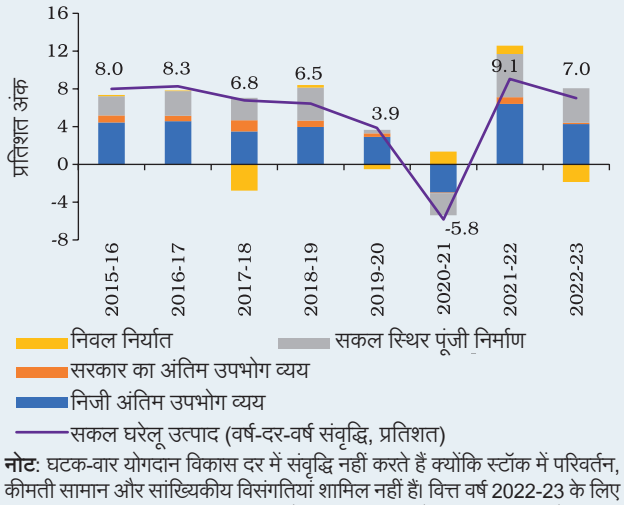

नोट: घटक-वार योगदान विकास दर में संवृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन, कीमती सामान और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफसीई, जीएफसीएफ, जीएफसीई और निवल निर्यात में जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान क्रमश: 4.3 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत और (-) 1.9 प्रतिशत रहा।
स्रोत: एनएसओ।

निर्माण (जीएफसीएफ) 11.2 प्रतिशत की द्विअंकी वृद्धि के साथ मजबूत रहा, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा दिये जा रहे जोर से समर्थित था। नतीजतन, जीडीपी में वास्तविक जीएफसीएफ का अनुपात पिछले वर्ष के 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 34.0 प्रतिशत हो गया। भारत का निर्यात, कोविड-19 महामारी के बाद 2021-22 में 29.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय सुधार के बाद, 2022-23 में घटकर 11.5 प्रतिशत रह गया। चूंकि आयात में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि ने निर्यात में हुई वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, इसलिए निवल निर्यात से कर्षण (ड्रैग) पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत से और बढ़कर 2022-23 में जीडीपी का 2.9 प्रतिशत हुआ।

उपभोग

II.2.5 पिछले दो वर्षों तक जारी कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों से मुक्त होकर, पीएफसीई - जो समग्र मांग का मुख्य घटक है- 2022-23 में फिर से मजबूत होकर महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर 13.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। संपर्क गहन गतिविधियों में अच्छी तरह से बहाली और विवेकाधीन खपत में दबी हुई मांग ने वर्ष की पहली छमाही में निजी खपत को बढ़ावा दिया। एक आघात-सह कृषि क्षेत्र और महामारी अवधि के सापेक्ष श्रम बाजार की स्थिति में सुधार ने खपत में पुनरुद्धार को सहारा दिया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं- दोनों का उत्पादन हाल के महीनों में काफी हद तक कमजोर हो गया है जो खपत में मंदी का संकेत देता है क्योंकि वर्ष की दूसरी छमाही में दबी हुई मांग धीरे-धीरे कमजोर होती गई।

II.2.6 उपभोग मांग के संकेतक 2022-23 में व्यापक आधार पर पुनरुद्धार के संकेत देते हैं। परिवहन से संबंधित संकेतक जैसे घरेलू हवाई यात्री यातायात, रेलवे यात्री यातायात, यात्री वाहन की बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य में फिर से शुरूआत की ओर इशारा करती है। शादी/छुट्टियों के मौसम के साथ-साथ घरेलू अवकाश गंतव्यों में प्रतिशोधात्मक पर्यटन (रिवेंज टूरिज्म) ने होटल, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को फिर से उठ खड़ा होने और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों – अखिल भारतीय बेरोजगारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात (डबल्यूपीआर) और श्रमबल प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) – ने 2022-23 की पहली तिमाही में अपने कोविड-पूर्व स्तरों को पार कर लिया। कॉर्पोरेट क्षेत्र में वेतन और मजदूरी ने 2022-23 में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। ये सभी कारक खपत की मांग को और बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के मार्च 2023 चरण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और घरेलू आय के बारे में बेहतर धारणा के कारण वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) में और सुधार हुआ है, और भविष्य प्रत्याशा सूचकांक (एफईआई), थोड़ी कमतर प्रत्याशा के बावजूद भी सकारात्मक बना हुआ है। अगले वर्ष में गैर-आवश्यक परिव्यय में वृद्धि की प्रत्याशा के साथ, आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों वस्तुओं के लिए घरेलू खर्च उत्साहजनक था।

II.2.7 एक साल पहले कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित ग्रामीण मांग में, शहरी मांग की तुलना में, धीमी गति से सुधार हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद, 2022-23 में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि लगभग स्थिर रही। हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत नौकरी की मांग में साल-दर-साल आधार पर गिरावट आई है, फिर भी यह 2022-23 में महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि सुधार, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में अभी तक पूरा नहीं हुआ है (बॉक्स II.2.1)।

निवेश और बचत

II.2.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, जो वर्तमान कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और जीडीपी के अनुपात से मापी जाती है, 2021-22 में बढ़कर 31.4 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष कोविड-जन्य मंदी के कारण घट कर 27.9 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि अभी तक 2022-23 के लिए जीसीएफ का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके घटकों में हुए उतार-चढ़ावों से पता चलता है कि मुख्य रूप से बुनियादी

बॉक्स II.2.1

महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र में सुधार

यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक नुकसान असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों पर भारी पड़ रहा है। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के इस खंड में सुधार की प्रकृति पर कोई आधिकारिक आकलन उपलब्ध नहीं है। असंगठित या अनौपचारिक उद्यमों के संचालन की प्रकृति को खातों के रखरखाव या किसी भी नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए, समय पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधि का उचित लेखा-जोखा रखना मुश्किल हो जाता है।

2011-12 की आधार वर्ष श्रृंखला में, घरेलू क्षेत्र[1] के भीतर सृजित सकल मूल्य वर्धन (जीवीए), मोटे तौर पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों को अपने दायरे में लेता है। असंगठित जीवीए का आधिकारिक अनुमान लगभग 10 महीने के अंतराल के साथ वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसलिए, वर्तमान में ये डेटा केवल 2021-22 तक उपलब्ध हैं। 2021-22 में वास्तविक रूप से घरेलू क्षेत्र का जीवीए[2] 2019-20 के महामारी से पहले के स्तर से 3.1 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

असंगठित क्षेत्र पर महामारी के विषम प्रभाव की पुष्टि आधिकारिक आंकड़ों के साथ-साथ सर्वेक्षण-आधारित अध्ययनों और उपाख्यानात्मक साक्ष्य (एस्टुपिनन और शर्मा, 2020) द्वारा की गई थी। घरेलू जीवीए में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि संगठित क्षेत्र के जीवीए में 2020-21 में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि होटल और रेस्तरां के संगठित और घरेलू दोनों क्षेत्रों; अन्य सेवाएं; परिवहन; व्यापार और मरम्मत; और निर्माण में संकुचन दर्ज किया गया था, लेकिन संकुचन घरेलू क्षेत्रों में अधिक व्याप्त था।

असंगठित क्षेत्र के प्रदर्शन को ट्रैक करने के प्रयास में एक संकेतक-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए मासिक आवृत्ति पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधि के लिए एक समग्र सूचकांक का गठन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र का समग्र संयोग सूचकांक (यूएनसीसीआई) एक संदर्भ माह के अंत से 45 दिनों के अंतराल के साथ उपलब्ध है।

यूएनसीसीआई के लिए जिस उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) की पहचान की गई है, वह मोटे तौर पर तीन श्रेणियों से संबंधित है जिनमें असंगठित क्षेत्र की अपेक्षाकृत बड़ी उपस्थिति है - (i) कृषि; (ii) निर्माण, व्यापार और परिवहन; और (iii) अन्य विविध गतिविधियां। 15 संकेतकों के व्यापक सेट में से घटक संकेतकों का चयन बेंचमार्क संकेतक - घरेलू क्षेत्र जीवीए वृद्धि के साथ उनके गतिशील सहसंबंध के आधार पर किया जाता है।

यूएनसीसीआईएस को स्टेट-स्पेस ढांचे (गेवेके, 1977) में गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो घटक संकेतकों से सामान्य प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कलमैन फिल्टर का उपयोग करता है। यूएनसीसीआई, कोविड-19 के प्रलयकारी प्रभाव और उसके बाद असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में सुधार को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करता है (चार्ट 1)। यूएनसीसीआई का हालिया प्रक्षेपवक्र नवंबर 2022 में तेजी की ओर इशारा करता है और बाद के महीनों में और सुधार दिखाता है। मार्च 2023 में यूएनसीसीआई 6.9 प्रतिशत पर सुदृढ़ रहा।

चार्ट 1: असंगठित समग्र संयोग सूचकांक (यूएनसीसीआई)

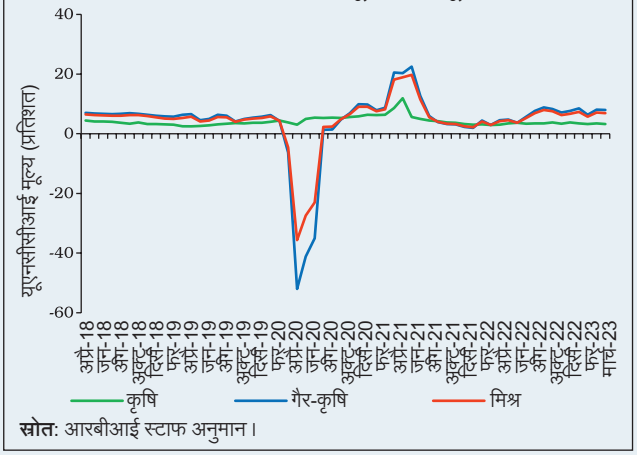

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. भौमिक, सी., गोयल, एस., दास, एस. और गौतम, (2022), 'ए कोम्पोजिट कोइंसिडेंट इंडेक्स फॉर अनओरगनाइजेड सैक्टर एक्टिविटी इन इंडिया', आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर 2022।
2. एस्टुपिनन, जेवियर और शर्मा, मोहित, (2020), 'जॉब एंड वेज लौस्सेज इन इन्फ़ारमल सैक्टर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन मेजर्स इन इंडिया', रोचेस्टर, न्यूयॉर्क।
3. गेवेके, जे (1977), आइंगर, डीजे और गोल्डबर्गर, एएस (एड), सामाजिक-आर्थिक मॉडल में अव्यक्त चर पीपी 365-383, नॉर्थ-हॉलैंड प्रकाशन, एम्स्टर्डम में 'द डाइनैमिक फैक्टर एनालिसिस ऑफ इकनॉमिक टाइम सीरीज़'।

[1] घरेलू क्षेत्र में कृषि जोतों पर की जाने वाली कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं - व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में, वृक्षारोपण और कॉर्पोरेट खेती को छोड़कर; व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाले सभी अनिगमित निजी उद्यमों के साथ - स्वयं का खाता या साझेदारी।

[2] एनएसओ घरेलू क्षेत्र के जीवीए आंकड़े मौजूदा कीमतों पर ही जारी करता है। घरेलू क्षेत्र के जीवीए डिफ्लेटर को 2021-22 के लिए समग्र जीवीए डिफ्लेटर के समान माना जाता है।

ढांचे पर सरकारी खर्च के कारण इसमें वृद्धि हुई है। 2022-23 में ऋण वृद्धि में आई तेजी और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों और विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) में परिलक्षित उत्साहपूर्ण निवेश धारणा से पता चलता है कि निवेश चक्र में सुधार जारी रहने की संभावना है (बॉक्स II.2.2)।

II.2.9 जीएफसीएफ के घटकों में, निर्माण क्षेत्र में गतिविधि, सरकार के बुनियादी ढांचे और अस्थिर आवास क्षेत्र पर ध्यान देने के कारण, रफ्तार पकड़ रही है। यह इसके निकटवर्ती संयोग संकेतकों - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन- में आई गति से स्पष्ट है (चार्ट II.2.3)। मशीनरी और उपकरणों में निवेश की तेज मांग, उनके निकटवर्ती संयोग संकेतकों- पूंजीगत वस्तुओं

बॉक्स II.2.2
निजी निवेश चक्र में बदलाव लाने में ऋण की भूमिका

भारत में बैंक ऋण, कॉर्पोरेट निवेश के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण में निरंतर वृद्धि से निवेश मांग में तेजी के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि कभी-कभी वृद्धि कार्यशील पूंजी की मांग का संकेत दे सकती है जो वर्तमान क्षमता के उपयोग के लिए हो सकती है। मार्च 2023 तक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 15.4 प्रतिशत पर सुदृढ़ रही जो 2022-23 के लिए नाममात्र जीडीपी के समान थी। बैंक ऋण में व्यापक आधार पर विस्तार को, बैंकों के बेहतर तुलनपत्रों द्वारा सुगम बनाया गया है (चार्ट 1)।

पण्य की कीमतों में और ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, हाल की अवधि में कॉर्पोरेट निवेश में तेजी आई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या बैंक ऋण में वृद्धि, निवेश चक्र को पुनर्जीवित कर सकती है, सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्मों के उधार और निश्चित निवेश के बीच संबंधों की जांच 2011-12 से 2020-21 (अरेलानो और बॉण्ड, 1991) की अवधि के लिए एक गतिशील पैनल मॉडल द्वारा की जाती है। परिणाम बताते हैं कि बैंक उधार में एक प्रतिशत अंक की उच्च वृद्धि नॉमिनल निवल अचल आस्ति (एनएफए) में लगभग 0.17 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करती है (सारणी 1)।

चार्ट 1: ऋण वृद्धि में योगदान (वर्ष-दर-वर्ष)

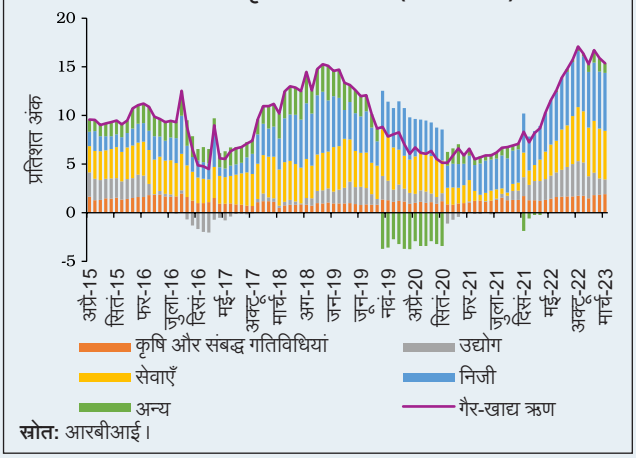

स्रोत: आरबीआई।

सारणी 1: बैंक उधार और निश्चित निवेश

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}
$\Delta NFA_{i,t-1}$	0.133***	0.859***	0.424**	0.0862*
	(0.0316)	(0.108)	(0.192)	(0.0515)
बैंक उधार वृद्धि $_{it}$	0.158**	0.174***	0.201*	0.0252
	(0.0630)	(0.0662)	(0.104)	(0.125)
आर एंड डी व्यय वृद्धि$_{it}$	0.121***	0.0440	0.115*	0.0474
	(0.0436)	(0.0450)	(0.0683)	(0.0600)
परिचालन व्यय में वृद्धि$_{it}$	-0.258***			-0.328**
	(0.0837)			(0.146)
मुद्रास्फीति $_{t}$		-0.535**	1.027***	
		(0.210)	(0.323)	
बैंक उधार वृद्धि$_{it}$ × मुद्रास्फीति			-0.0504***	
			(0.0116)	
बैंक उधार वृद्धि$_{it}$ × परिचालन व्यय में वृद्धि$_{it}$				0.0231
				(0.0184)
स्थिरांक	6.315***	1.588	-0.317	7.885***
	(0.769)	(2.078)	(2.474)	(1.664)
एन	117	117	117	117
एआर (1), पी-मान	0.0229	0.00760	0.00890	0.0232
एआर (2), पी-मान	0.264	0.180	0.133	0.243
हैनसेन टेस्ट, पी-मान	0.920	0.804	0.999	0.853

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्ता स्तर इंगित करता है।

नोट: कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियां हैं। उपरोक्त सारणी में *'i'* का अर्थ सेक्टर और *'t'* का अर्थ समय है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उच्च मुद्रास्फीति, परिचालन लागत को बढ़ाती है, जो बदले में, निश्चित निवेश को कम करती है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, बैंक उधारी के प्रति निश्चित निवेश की संवेदनशीलता कम हो जाती है। यह निवेश दृष्टिकोण के लिए निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

निवेश गतिविधि में पुनरूद्धार की पुन: पुष्टि करने के लिए, तिमाही मौसमी रूप से समायोजित निवेश दर और वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण

(जारी)

चार्ट 2: निवेश चक्र

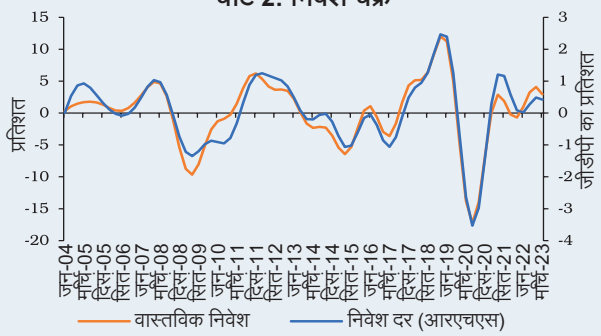

नोट: चक्रों की गणना वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) (नारंगी रेखा) और नॉमिनल जीएफसीएफ के विकास पर असममित बैंड-पास फिल्टर को नियोजित करके की जाती है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

डेटा पर एक असममित बैंड-पास फिल्टर को नियोजित करके, निवेश चक्रों का अनुमान लगाया जाता है। दोनों शृंखलाओं से निकाले गए चक्र महामारी की पहली लहर के दौरान आई मंदी से निवेश में चक्रीय पुनरुद्धार की पुष्टि करते हैं (चार्ट 2)। आने वाले समय में पुनरुद्धार की धारणीयता भारत में निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति, वैश्विक उत्पादन और व्यापार में मजबूत वृद्धि, वित्तीय स्थितियों में सुधार, कंपनियों द्वारा समय पर परियोजना को पूरा करने और अनुकूल पण्य मूल्य दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी।

संदर्भ:

अरेलानो, एम. और बॉण्ड, एस.(1991), 'टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर पैनल डेटा: मोंटे कार्लो एविडेंस एंड एन एप्लिकेशन टू इम्प्लॉइमेंट ईक्वेशंस', आर्थिक अध्ययन की समीक्षा, 58 (2), 277-297।

का आयात और उत्पादन- में आई गति से स्पष्ट है, जिनमें 2022-23 में मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है।

II.2.10 रिज़र्व बैंक के ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबिकस) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का कुल क्षमता उपयोग (सीयू) 2022-23 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 74.3 प्रतिशत हो गया, जो पिछली तिमाही में 74.0 प्रतिशत था। हालांकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू में 40 बीपीएस की गिरावट आई और यह 2022-23 की तीसरी तिमाही में 74.1 प्रतिशत पर रहा। विनिर्माण कंपनियों के लिए, 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान नए ऑर्डर वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़े। 2022-23 की तीसरी तिमाही में बिक्री के मुकाबले तैयार माल इन्वेंट्री (एफजीआई) और कच्चे माल की इन्वेंट्री (आरएमआई) का अनुपात सपाट रहा, जो कमजोर मांग की स्थिति को दर्शाता है। 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए, आईओएस के उत्तरदाताओं ने, विशेष रूप से वित्तीय स्थिति के बारे में आशावाद का प्रदर्शन किया।

चार्ट II.2.3: निवेश मांग के संकेतक

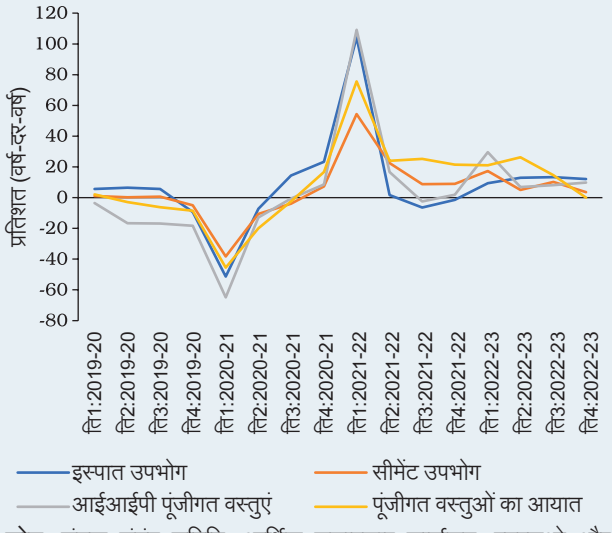

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, एनएसओ और डीजीसीआई एंड एस।

II.2.11 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत दर पिछले वर्ष के 28.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 30.0 प्रतिशत हो गई, जो सामान्य सरकारी क्षेत्र का अधिव्यय कम होने के कारण हुआ, जिससे घरेलू बचत में गिरावट की भरपाई की। घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत- दो घाटे वाले क्षेत्रों, अर्थात् सामान्य सरकारी क्षेत्र और गैर-वित्तीय निगमों के लिए धन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत - 2021-22 में जीएनडीआई के 7.6 प्रतिशत तक कम हो गई (सारणी II.2.2 और परिशिष्ट सारणी 3)। भारत में घरेलू वित्तीय बचत में कमी, दबी हुई मांगों की पूर्ति और 2021-22 में आय प्रवाह से संबंधित चिंताओं के कम होने के कारण एहतियाती बचत में तत्संबंधी कमी को दर्शाती है।

सारणी II.2.2 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए. सकल वित्तीय बचत	**10.4**	**10.5**	**10.4**	**9.9**	**10.7**	**10.4**	**11.9**	**11.8**	**11.4**	**15.2**	**11.0**
जिसमें:											
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1
2. जमाएं	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.2
5. बीमा नीधि	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	1.9
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4
बी. वित्तीय देयताएं	**3.2**	**3.2**	**3.1**	**3.0**	**2.7**	**3.0**	**4.3**	**4.0**	**3.8**	**3.9**	**3.4**
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**6.9**	**7.9**	**7.3**	**7.5**	**7.8**	**7.6**	**11.3**	**7.6**

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय निपटान आय

नोट : पूर्णांकन (राउंडिंग ऑफ के कारण) आंकड़े कुल देय की जोड़ के बराबर नहीं भी हो सकते हैं।

स्रोत : एनएसओ।

II.2.12 निवेश मांग में पुनरुद्धार के कारण, 2021-22 में निजी गैर-वित्तीय निगमों का संसाधन-अंतर बढ़ गया (चार्ट II.2.4)। 2020-21 में कोविड-19 के चलते राजकोषीय घाटे में वृद्धि के बाद, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिव्यय उच्च स्तर से कम हो गया।

3. समग्र आपूर्ति

II.2.13 मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति 2022-23 में 6.6 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आर्थिक गतिविधियों में क्रमिक पुनरुद्धार के साथ, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि दर (एमए-एसएएआर) के तीन-तिमाही चल औसत ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्शाई, लेकिन 2022-23 की तीसरी तिमाही में यह कम हो गया (चार्ट II.2.5)।

चार्ट II.2.4 : क्षेत्रीय संसाधन अंतर

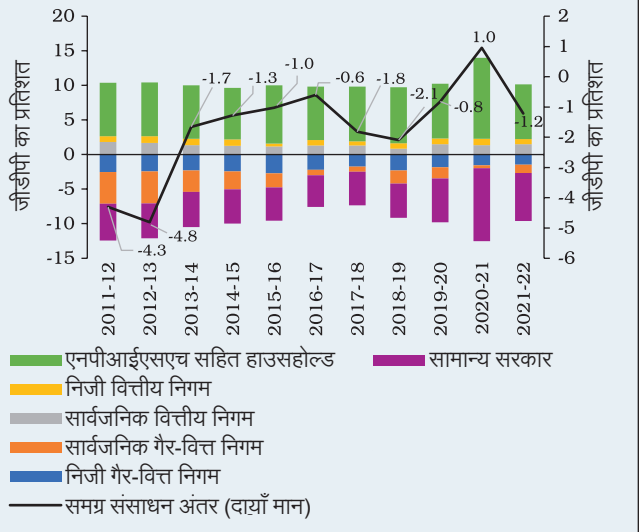

एनपीआईएसएच : नॉन-प्रॉफिट इन्स्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.2.5: जीवीए संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और एसएएआर

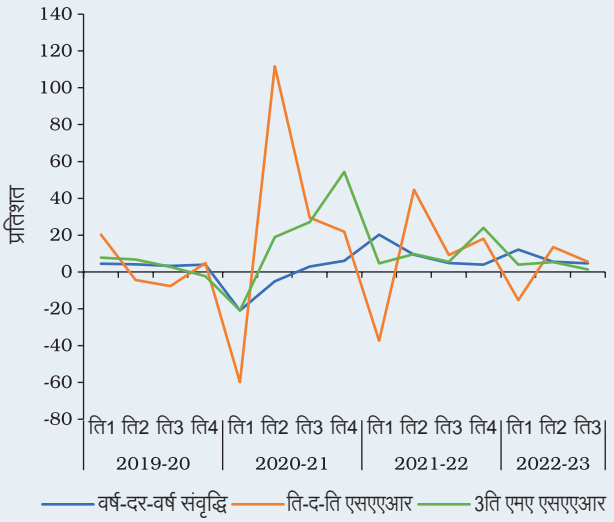

एसएएआर : मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर एमए: चलती औसत

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.2.14 जीवीए वृद्धि, अघात-सह कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार पर सुधार से प्रेरित थी (सारणी II.2.3)। दूसरी ओर, इनपुट लागत दबाव में तेजी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक मांग की नई स्थिति के बीच औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई।

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

II.2.15 कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर में 2022-23 में लगातार तीसरे साल नरमी आई। खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मक्का, जौ और दालों सहित), गन्ना, रेप सीड और सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन से, 2022-23 के दौरान इस क्षेत्र का जीवीए 3.3 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की उछाल को, आम तौर पर सामान्य संचयी दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) वर्षा– विभिन्न समयों और क्षेत्रों में इसके असमान वितरण, और वापसी में देरी के बावजूद - और सामान्य उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश से समर्थन मिला। सर्दियों के मौसम में कम बारिश (जनवरी-फरवरी) और फरवरी 2023 के दौरान रहे सामान्य से अधिक तापमान ने *रबी* उत्पादन के लिए अधोगामी जोखिम पैदा किया। फरवरी महत्वपूर्ण महीना होता है, जब गेहूं और अन्य *रबी* फसलों के साथ-साथ बागवानी फसलों में फूल फूटते हैं और दाने भरते हैं। इसके अलावा, मार्च महीने के दौरान ओलावृष्टि के साथ असामान्य बारिश ने *रबी* फसलों के लिए और जोखिम पैदा कर दिया और प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसलों की कटाई में देरी हुई।

II.2.16 एसडब्ल्यूएम के असमान अस्थायी और स्थानिक वितरण ने *खरीफ* बुवाई की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे फसल बुआई का रकबा कम हो गया। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुरूप, मानसून 29 मई, 2022 को (अपनी सामान्य तारीख से दो दिन पहले) भारतीय मुख्य भूमि पर उतरा, लेकिन जून 2022 में बारिश सामान्य से कम रही, जिससे *खरीफ* बुवाई की शुरुआत में देरी हुई। जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक वर्षा में उतार-चढ़ाव होता रहा (चार्ट II.2.6)। हालांकि, मौसम के अंत (30 सितंबर, 2022) तक संचयी वर्षा, लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक रहते हुए, सामान्य थी। स्थानिक रूप से, जहां उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश सामान्य बेंचमार्क के आसपास मंडराती रही, वहीं मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में मौसम के मध्य और अंत के दौरान अत्यधिक बारिश हुई, जिससे कुछ खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों, जो भारत के चावल उत्पादन में एक तिहाई से अधिक का योगदान करते हैं, में *खरीफ* बुवाई के महत्वपूर्ण महीनों- जुलाई से

सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	**2.1**	**6.2**	**4.1**	**3.5**	**3.3**
II. उद्योग	**4.9**	**-2.5**	**0.9**	**10.5**	**1.7**
II.1 खनन और उत्खनन	-0.8	-3.0	-8.6	7.1	3.4
II.2 विनिर्माण	5.4	-3.0	2.9	11.1	0.6
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	7.9	2.3	-4.3	9.9	9.2
III. सेवाएँ	**7.1**	**5.8**	**-7.9**	**9.6**	**9.3**
III.1 निर्माण	6.5	1.6	-5.7	14.8	9.1
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	7.2	6.0	-19.7	13.8	14.2
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	7.0	6.8	2.1	4.7	6.9
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	7.5	6.6	-7.6	9.7	7.1
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	**5.8**	**3.9**	**-4.2**	**8.8**	**6.6**

स्रोत: एनएसओ।

चार्ट II.2.6: साप्ताहिक वर्षा 2022-23

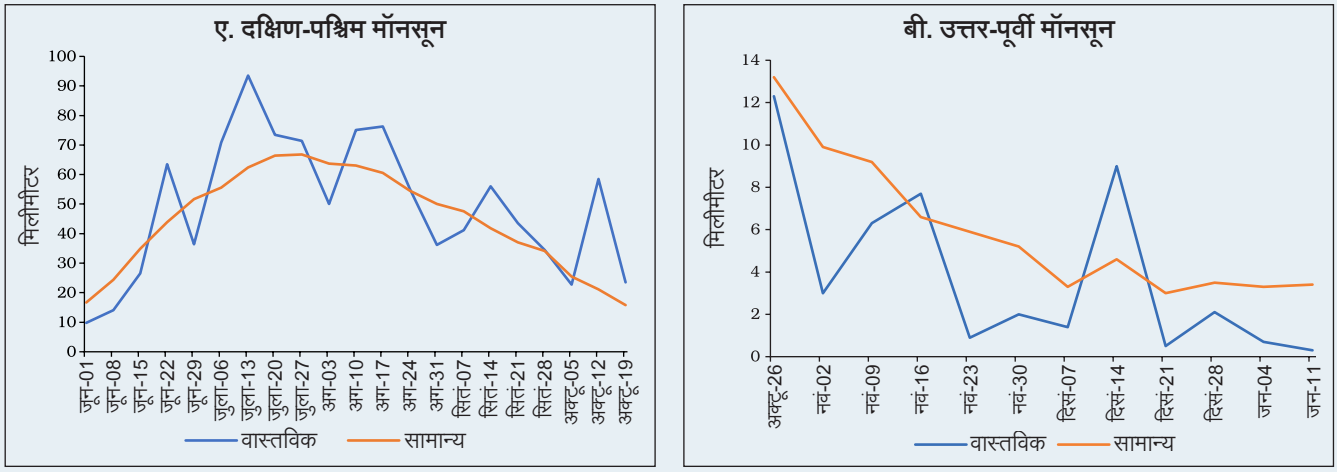

स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारत सरकार।

अगस्त 2022 की अधिकांश अवधि के दौरान कम वर्षा देखी गई। उल्लेखनीय है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वर्षा के सामान्य स्तर की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई। सितंबर 2022 के अंत तक अंतिम *खरीफ* रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम था।

II.2.17 दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) की वापसी 20 सितंबर, 2022 के आसपास शुरू हुई और यह 23 अक्टूबर, 2022 को समाप्त हुई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती विक्षोभ के कारण धीमी गति से इसकी वापसी हुई। नतीजतन, अधिकांश प्रमंडलों में सितंबर और अक्टूबर 2022 के दौरान भारी बारिश हुई। इन बारिशों ने मिट्टी में अनुकूल नमी के साथ-साथ, पर्याप्त जलाशय स्तर सुनिश्चित किया, जो *रबी* फसलों के लिए अच्छा होता है। 12 जनवरी, 2023 (उत्तर-पूर्वी मानसून के अंत) तक जलाशय जल भंडारण स्तर, पूर्ण जलाशय क्षमता का 70 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के स्तर के बराबर था और पिछले 10-वर्षीय औसत से 20 प्रतिशत अधिक था (चार्ट II.2.7)। इन कारकों की मदद से *रबी* फसलों का बुवाई सत्र 2022-23, 720.7 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड रकबे के साथ समाप्त हुआ, जो पिछले साल की बुवाई से 3.3 प्रतिशत अधिक है। *रबी* फसलों के रकबे में उछाल मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, मसूर, रेपसीड और सरसों से आया। नतीजतन, तीसरे अग्रिम अनुमानों (तृतीय एई) के अनुसार, 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3305.3 लाख टन अनुमानित है, जो 2021-22 के लिए अंतिम अनुमानों (एफई) से 4.7 प्रतिशत अधिक है (सारणी 2.2.4)। लगातार सातवें वर्ष रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य रूप से *रबी* फसलों (6.2 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) का योगदान है

चार्ट II.2.7 : जलाशय स्तर (12 जनवरी, 2023 की स्थितिनुसार)

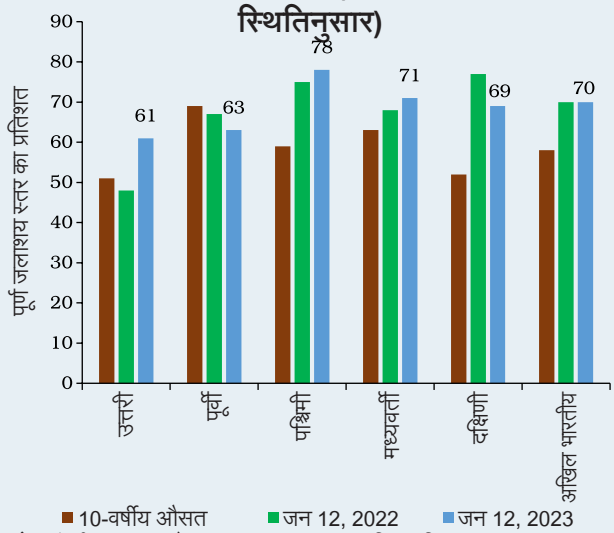

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी II.2.4: कृषि उत्पादन 2022-23

(लाख टन)

फसल	2021-22		2022-23		2022-23 (तृतीय एई) परिवर्तन (प्रतिशत)		
	तृतीय एई	अंतिम	लक्ष्य	तृतीय एई	2021-22 की तुलना में		2022-23 की तुलना में
					तृतीय एई	अंतिम	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्यान्न	3,145.1	3,156.2	3,280.0	3,305.3	5.1	4.7	0.8
खरीफ	1,549.3	1,553.6	1,631.5	1,551.2	0.1	-0.2	-4.9
*रबी**	1,595.9	1,602.5	1,648.5	1,754.2	9.9	9.5	6.4
चावल	1,296.6	1,294.7	1,305.0	1,355.4	4.5	4.7	3.9
गेहूं	1,064.1	1,077.4	1,120.0	1,127.4	6.0	4.6	0.7
दालें	277.5	273.0	295.5	275.0	-0.9	0.7	-6.9
तिलहन	385.0	379.6	413.5	410.0	6.5	8.0	-0.8
गन्ना	4,305.0	4,394.3	4,150.0	4,942.3	14.8	12.5	19.1
कपास #	315.4	311.2	370.0	343.5	8.9	10.4	-7.2
जूट और मेस्ता ##	102.2	101.5	105.0	94.9	-7.1	-6.5	-9.6

*: ग्रीष्म ऋतु उत्पादन को शामिल करते हुए। #: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें। ##: हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

क्योंकि *खरीफ* फसलों के उत्पादन में सीमांत रूप से संकुचन (-1.2 प्रतिशत) हुआ है। बागवानी उत्पादन के मामले में, 2021-22 के लिए (तीसरे एई) ने कुल उत्पादन को 7.0 लाख टन बढ़ाकर 3,423.3 लाख टन कर दिया, जो 2020-21 की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है और यह फलों एवं सब्जियों - दोनों के उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित है।

II.2.18 हाल के वर्षों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, *रबी* और *खरीफ*- दोनों फसलों के लिए 2022-23 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उत्पादन लागत पर[3] 50 प्रतिशत का न्यूनतम लाभ (रिटर्न) सुनिश्चित किया। सभी फसलों के लिए कीमतें 2.0 प्रतिशत (चना के लिए) से लेकर 9.1 प्रतिशत (मसूर के लिए) के दायरे में बढ़ीं। 31 मार्च, 2023 तक, 2022-23 के *खरीफ* विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 492.2 लाख टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम है (चार्ट II.2.8)। नतीजतन, 31 मार्च, 2023 तक चावल का बफर स्टॉक बफर मानदंड का 3.2 गुना था (चार्ट II.2.9)।

चार्ट II.2.8 : चावल और गेहूं की वार्षिक खरीद (अप्रैल-मार्च)

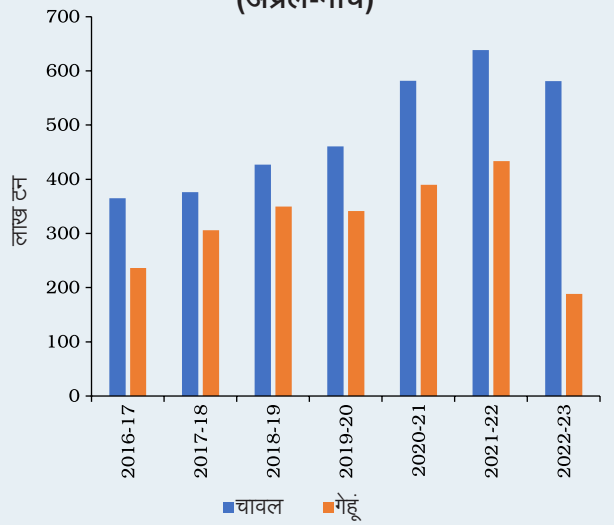

स्रोत : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

[3] वास्तविक भुगतान लागत (ए2) *और* पारिवारिक श्रम (एफएल) का आरोपित मूल्य [ए2 + एफएल]।

चार्ट II.2.9 : अनाज भंडार और बफर मानदंड की मासिक स्थिति

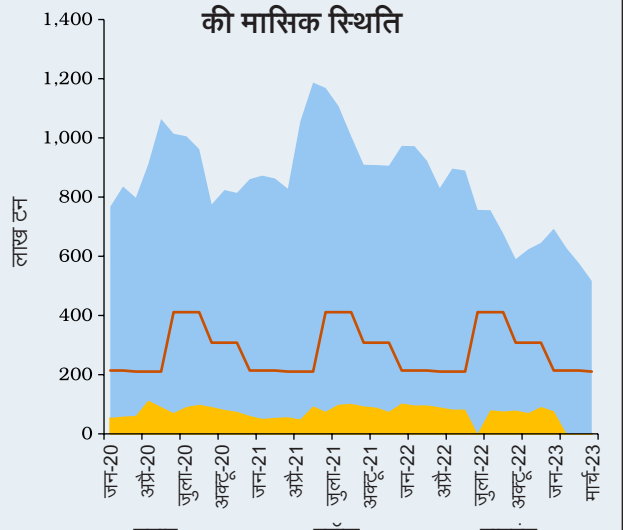

स्रोत : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट II.2.10 : खाद्यान्न का वितरण

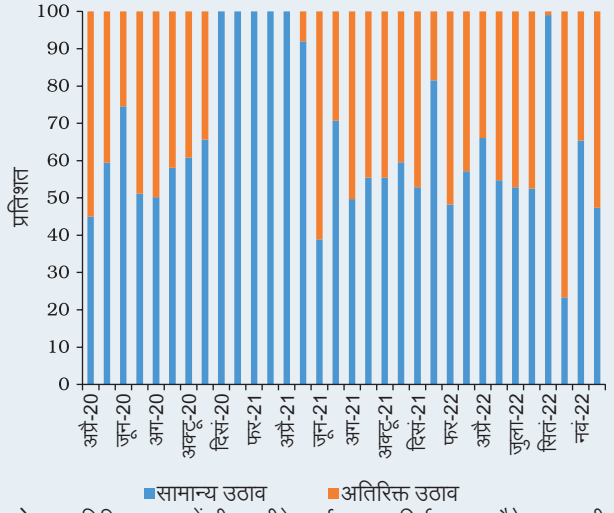

नोट : अतिरिक्त उठाव में पीएम-जीकेएवाई, *आत्म निर्भर भारत पैकेज* (प्रवासी) और गैर-एनएफएसए (कोविड-19) शामिल हैं।
स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

II.2.19 2022-23 के रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 56.6 प्रतिशत की गिरावट के कारण, गेहूं का स्टॉक बफर मानदंडों (31 मार्च, 2023 तक) का 1.1 गुना था। गेहूं की कम खरीद, मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल 2022 के कटाई के महीनों के दौरान लगातार लू चलने से उपज में हुए नुकसान; और रूस-यूक्रेन युद्ध के फैलने के बाद गेहूं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई थी। भारत सरकार ने गेहूं पर (14 मई, 2022 को), गेहूं आधारित उत्पादों पर (25 अगस्त, 2022 को) और खुद्दी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके साथ ही, परमल चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर उच्च निर्यात शुल्क लगा दिया ताकि इनकी घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। फरवरी और मार्च 2023 के महीनों में, सरकार ने गेहूं से मुद्रास्फीति पर पड़ते दबाव को रोकने के लिए, मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत ई-नीलामी के माध्यम से, केंद्रीय पूल स्टॉक से 3.4 मिलियन टन गेहूं बाजार में उतारा।

II.2.20 गेहूं के घटते स्टॉक की भरपाई के लिए, अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएम-जीकेएवाई) के तहत इसके छठे और सातवें चरण में गेहूं के स्थान पर चावल का वितरण किया गया था। अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से, इस योजना के तहत खाद्यान्नों का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कुल उठाव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था [चार्ट II.2.10]। महामारी के कम होने के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण 1 जनवरी, 2023 से बंद कर दिया गया था। इसके बजाय, केंद्र सरकार ने एकीकृत पीएम-जीकेएवाई योजना की घोषणा की, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) 2023 में नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे। पहले एनएफएसए के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और *अंत्योदय अन्न योजना* के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर (चावल/गेहूं/मोटे अनाज, क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम) दिया जाता था।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.21 2022-23 के दौरान, औद्योगिक क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग की स्थिति में सुधार देखा।

चार्ट II.2.11: संगठित विनिर्माण कंपनियाँ

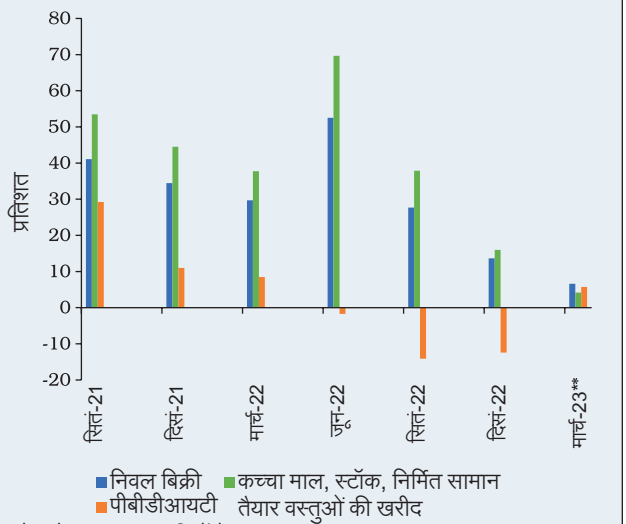

*: डेटा केवल 576 कंपनियों के लघु सैंपल पर आधारित हैं।
पीबीडीआईटी - मूल्य-ह्रास व्याज तथा कर पूर्व लाभ
स्रोत : सीएमआईई प्रोवेस।

चार्ट II.2.12: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि

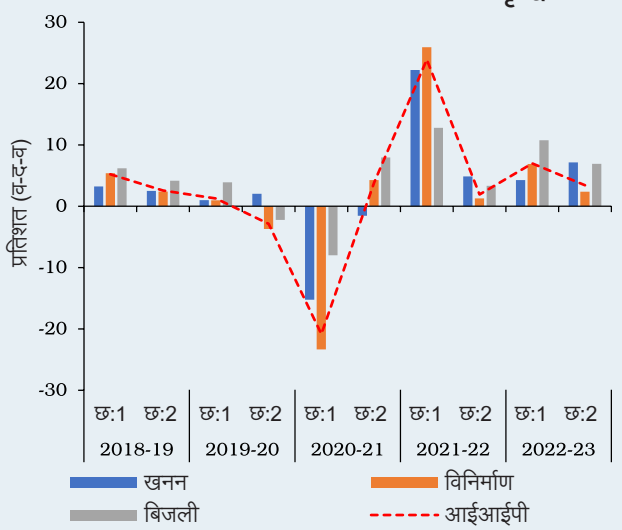

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, (एमओएसपीआई) भारत सरकार।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र, जो 2021-22 के दौरान कम आधार के साथ-साथ, कच्चे माल की लागत में नरमी से लाभान्वित हुआ था, को 2022-23 की पहली छमाही में कच्चे माल की बढ़ती लागत का खामियाजा भुगतना पड़ा (चार्ट II.2.11)। यूक्रेन में युद्ध के बाद आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के साथ-साथ मांग की स्थिति में सुधार ने विनिर्माण कंपनियों की लाभप्रदता को प्रभावित किया। हालांकि 2022-23 की पहली तिमाही में बिक्री में वृद्धि ने राहत प्रदान की, लेकिन वैश्विक मंदी ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप मुनाफे में तेजी से कमी आई। 2022-23 की तीसरी तिमाही में, इनपुट लागत में कमी आने से मुनाफे में होती गिरावट पर कुछ हद तक रोक लग सकी।

II.2.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में 2022-23 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले साल 11.4 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र का तीन-चौथाई हिस्सा है, ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र की बहाली को आकार दिया (चार्ट II.2.12)। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 में से 19 उद्योग समूहों ने 2022-23 की पहली छमाही में विस्तार दर्ज किया, जो मोटर वाहनों, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रासायनिक उत्पादों और मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण से प्रेरित था। वैश्विक मांग में नरमी से प्रभावित होने के कारण, विनिर्माण गतिविधियां 2022-23 की दूसरी छमाही में घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ गईं। जहां एक ओर, वस्त्र; परिधान; चमड़े और संबंधित उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; और विद्युत उपकरणों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों ने 2022-23 की दूसरी छमाही में संकुचन दर्ज किया, वहीं दूसरी ओर, मूल धातुओं, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों, मशीनरी और उपकरण, और अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों में विस्तार दर्ज किया गया। आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से जूझ रहे वाहन क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान त्योहारी मौसम में बिक्री से बल पाकर रफ्तार पकड़ ली।

II.2.23 2022-23 की पहली छमाही में उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर, सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष विस्तार दर्ज किया गया, जबकि 2022-23 की दूसरी छमाही में, केवल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में गिरावट देखी गई। 2022-23 में, प्राथमिक वस्तुओं, और बुनियादी ढांचा/निर्माण वस्तुओं ने वर्ष-दर-वर्ष के साथ-साथ, महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 के मुकाबले मजबूत वृद्धि दर्ज

चार्ट II.2.13: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - उपयोग आधारित वर्गीकरण

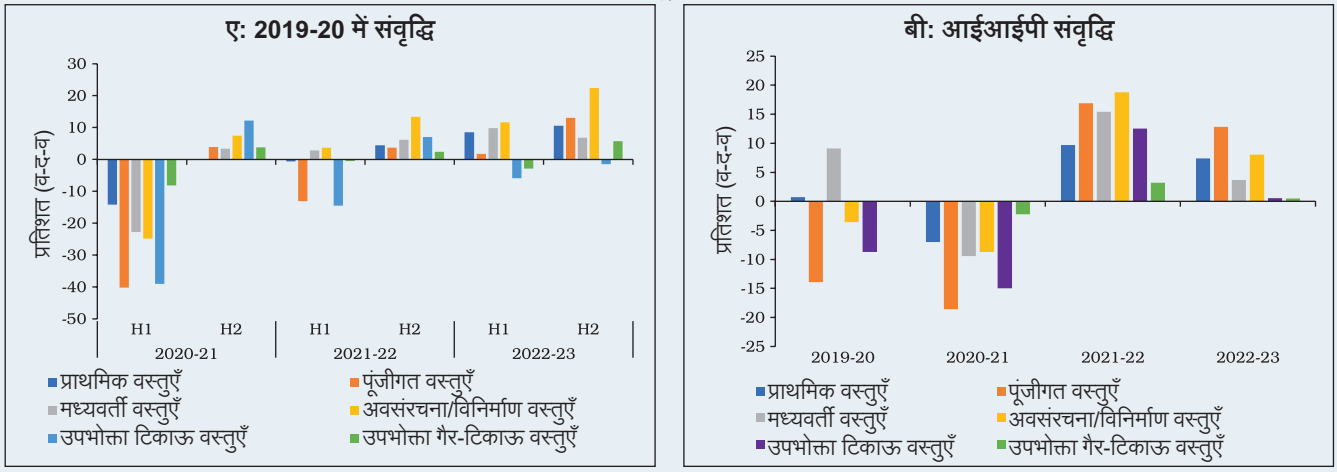

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

की। जहां एक ओर, पूंजीगत वस्तुओं ने आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 2019-20 के महामारी-पूर्व उत्पादन स्तर से नीचे रहने और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 के दौरान स्थिर रहने के साथ, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सुस्त बना रहा (चार्ट II.2.13)।

II.2.24 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है, ने मामूली सुधार दर्ज किया। एमएसएमई क्षेत्र का राजस्व 2022-23 में कोविड-19 से पहले के स्तर से 25 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है।[4] 99.8 प्रतिशत एमएसएमई के अपंजीकृत होने के साथ, असंगठित क्षेत्र के उत्पादन और रोजगार [राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), 2015-16] में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। कोविड-19 महामारी के आक्रमण से इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय पेश किए गए थे, जिसमें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) योजना भी शामिल थी, जिसका उद्देश्य व्यापार संचालन को बनाए रखने के लिए उनकी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) के आकलन के अनुसार, इस योजना ने एमएसएमई उधारकर्ताओं को उन उधारकर्ताओं की तुलना में सुविधा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के लिए कम अनर्जक आस्तियों (एनपीए) दरों के साथ अपने व्यवसायों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता की, जो पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया (सूक्ष्म, लघु और मध्यम की सभी श्रेणियों में) [चार्ट II.2.14]।

चार्ट II.2.14: एमएसएमई पर ईसीएलजीएस योजना का प्रभाव

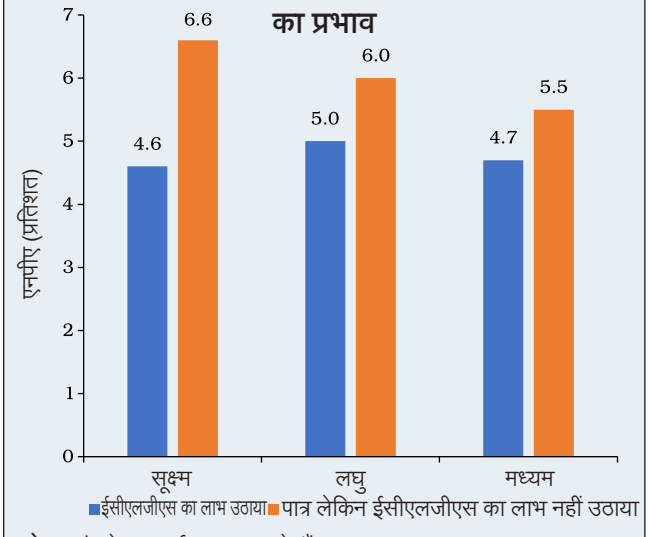

नोट: आंकड़े 31 मार्च 2022 तक के हैं।
स्रोत: ट्रान्सयूनियन सिबिल।

[4] क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)

II.2.25 खनन क्षेत्र ने 2022-23 की पहली छमाही में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण कोयला उत्पादन में दोहरे अंकों की संवृद्धि थी, जो उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के जवाब में कम आयात की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक हो गया था। 2022-23 की दूसरी छमाही में खनन क्षेत्र वार्षिक आधार पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत रहा, कोयले ने मजबूत संवृद्धि दर्ज की, जबकि कच्चे तेल ने 2022-23 की दूसरी छमाही में संकुचन दर्ज किया। थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत संवृद्धि के कारण 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बिजली उत्पादन 10.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, लेकिन 2022-23 की दूसरी छमाही में यह घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल उत्पादन का 12.6 प्रतिशत है, ने 2022-23 की पहली छमाही के दौरान 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान 21.3 प्रतिशत की मजबूत संवृद्धि दर्ज की। जबकि भारत 2022 तक 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य से चूक गया, अब तक की प्रगति सराहनीय है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो को छोड़कर) की स्थापित क्षमता 2017-18 और 2022-23 के बीच 81.3 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे मार्च 2023 में कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय[5] (हाइड्रो को छोड़कर) की हिस्सेदारी बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गई है। कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी भी सितंबर 2015 में समाप्त तिमाही में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में समाप्त तिमाही में 12.6 प्रतिशत हो गई है (चार्ट II.2.15)।

II.2.26 बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बकाया भारत में बिजली क्षेत्र को परेशान करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। इसके समाधान के लिए सरकार ने मई 2022 में देर से भुगतान अधिभार (एलपीएस) योजना शुरू की थी, जिसके तहत 3 जून 2022 तक बिजली उत्पादक को दिए गए सभी बकाये को 48 किस्तों में समाप्त किया

चार्ट II.2.15: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

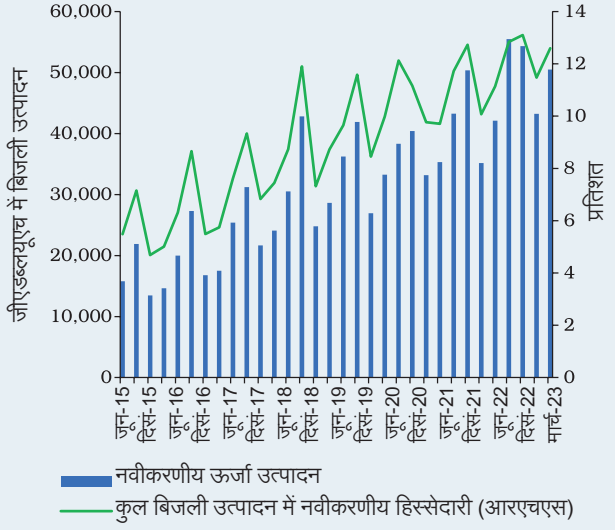

जीएडब्लयूएच: गीगावाट घंटे।
स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण।

जा रहा है। तदनुसार, डिस्कॉम द्वारा कुल बकाया 1 मार्च 2023 तक घटकर ₹58,231 करोड़ रह गया, जो 18 मई 2022 को ₹1,00,018 करोड़ था।

सेवा क्षेत्र

II.2.27 संपर्क-गहन होने के कारण कोविड-19 महामारी की बड़ी मार झेल रहे सेवा क्षेत्र में 2022-23 में मजबूती से सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति संकेतकों ने 2022-23 की पहली तिमाही में मजबूत संवृद्धि का संकेत दिया, लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में गति कम हो गई। 2022-23 की चौथी तिमाही में तिपहिया वाहनों की बिक्री, हवाई यात्री यातायात और जीएसटी ई-वे बिल में सुधार हुआ, जबकि यात्री वाहनों और निर्माण क्षेत्र की बिक्री में कमी आई। निर्माण, घरेलू व्यापार और परिवहन क्षेत्रों ने अपने महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर लिया, जबकि विमानन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, हालांकि ठीक हो रहे हैं, अभी भी संबंधित महामारी-पूर्व स्तरों तक नहीं पहुंचे हैं (सारणी II.2.5)।

[5] मार्च 2019 में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के तहत जल विद्युत को शामिल किया। इससे पहले केवल 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय माना जाता था। यदि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए तो स्थापित क्षमता में नवीकरणीय हिस्सेदारी 40.1 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

संकेतक	2021-22				2022-23			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी मांग								
ऑटोमोबाइल बिक्री	108.5	-10.2	-23.2	-19.3	51.4	16.9	10.0	8.7
यात्री वाहन बिक्री	317.7	-2.1	-20.2	-6.1	33.9	34.4	21.4	10.7
कृषि / ग्रामीण मांग								
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	38.9	-10.6	-13.5	-25.7	15.8	4.8	10.5	18.7
दुपहिया वाहनों की बिक्री	85.7	-12.3	-24.8	-22.4	54.4	13.6	7.2	6.7
तिपहिया वाहनों की बिक्री	92.0	52.0	12.5	-4.0	210.9	71.2	68.2	84.4
यातायात								
कुल वाहन पंजीकरण	78.0	11.6	-9.5	-8.5	61.5	1.3	18.8	14.8
घरेलू हवाई यात्री यातायात	371.1	108.5	61.5	6.7	206.2	64.1	18.5	52.2
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	328.0	110.4	138.5	80.8	403.3	263.9	98.1	93.6
घरेलू हवाई कार्गो	201.9	27.2	2.5	-4.4	32.1	9.9	-3	2.3
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	118.6	24.8	15.4	2.0	-1.7	-3.8	-11	-2.8
माल यातायात निवल टन किलो मी	52.8	16.6	14.1	11.1	19.4	14.5	3.7	4.7
फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट उत्पत्ति	40.5	12.8	7.3	7.0	11.8	8.4	3.2	3.7
पोर्ट कार्गो*	26.8	6.1	1.8	-0.9	9.2	12.8	5.2	12.0
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	97.9	27.5	10.8	9.2	45.6	20.1	17.2	18.1
जीएसटी ई-वे बिल इंट्रा-स्टेट	87.5	25.5	11.7	11.2	46.6	23.8	23.6	22.3
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	117.4	30.7	9.6	6.2	43.8	14.6	7.4	11.4
जीएसटी राजस्व	81.9	28.2	20.3	15.9	34.5	27.5	14.2	12.6
निर्माण								
स्टील की खपत	104.3	1.7	-6.4	-1.6	9.8	13.0	13.3	12.3
सीमेंट उत्पादन	55.9	22.5	8.7	9.0	17.3	4.9	9.8	3.6
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	71.9	118.4	56.0	0.3	140.0	21.1	13.5	32.2
विदेशी पर्यटकों का आगमन	786.7	363.6	280.7	131.7	895.4	496.5	209.5	222.4

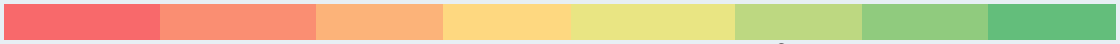

* : उपलब्धता के अनुसार 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए जनवरी/फरवरी 2023 के आंकड़े हैं।

स्रोत: एसआईएएम, एनारॉक, सीएमआईई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, संयुक्त संयंत्र समिति और सीईआईसी।

II.2.28 सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर निरंतर जोर दिए जाने के कारण निर्माण क्षेत्र मजबूत बना रहा। महामारी में एक मजबूत प्रदर्शन के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2022-23 में नरमी आई, जिसमें कंपनियों ने धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों के कारण लाभ में गिरावट दर्ज की गई। अवकाश और कॉर्पोरेट यात्रा की मांग बढ़ने से आतिथ्य क्षेत्र ने 2022-23 में वापसी की। वित्तीय क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कुल जमा और बैंक ऋण में विस्तार दर्ज किया गया। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं (पीएडीओ) 2022-23 में मुख्य रूप से अन्य सेवाओं में तेज संवृद्धि के कारण

आघात-सहनीय रहीं, जबकि वर्ष के दौरान सरकारी व्यय - विशेष रूप से केंद्र सरकार का धीमा रहा।

II.2.29 महामारी के बाद घर के स्वामित्व के लिए दबी हुई मांग और मजबूत उपभोक्ता धारणा ने 2022-23 में आवासीय आवास क्षेत्र में मजबूत सुधार की गति को कम कर दिया। 2022-23 में, दो वर्ष के रुक-रुक कर बंद होने के बाद पूरी हुई परियोजनाओं के मामले में आवासीय शुभारंभ में लगातार सुधार हुआ। तीसरी तिमाही में कुछ समय के लिए गति खोने के बाद 2022-23 की पहली छमाही में आवास बिक्री में तेजी आई और चौथी तिमाही में सुधार हुआ। जैसे-जैसे लॉन्च बिक्री से आगे निकलता गया, अनसोल्ड इन्वेंट्री में संवृद्धि हुई (चार्ट II.2.16)।

II.2.30 महामारी ने सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया। डिजिटल अपनाने से व्यापार संचालन के त्वरित पुन: अभिविन्यास की सुविधा प्रदान करके आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने में मदद मिली। 3 मार्च, 2023 तक 30,887 कंपनियों के साथ 1,08,585 कंपनियों वाली भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की कुल फंडिंग 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो अपने मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र भी है, जिसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 2022 में 26,542 तक बढ़ गई है [चार्ट II.2.17]।

II.2.31 विमानन यात्री यातायात ने 2022-23 की पहली छमाही और 2022-23 की दूसरी छमाही में कार्गो यातायात की

चार्ट II.2.16: स्थावर संपदा

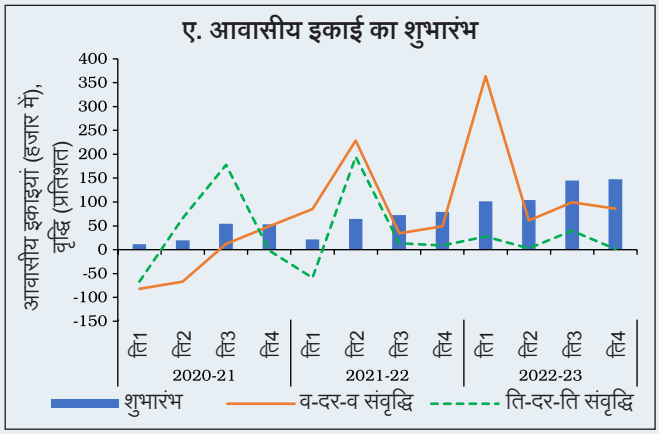

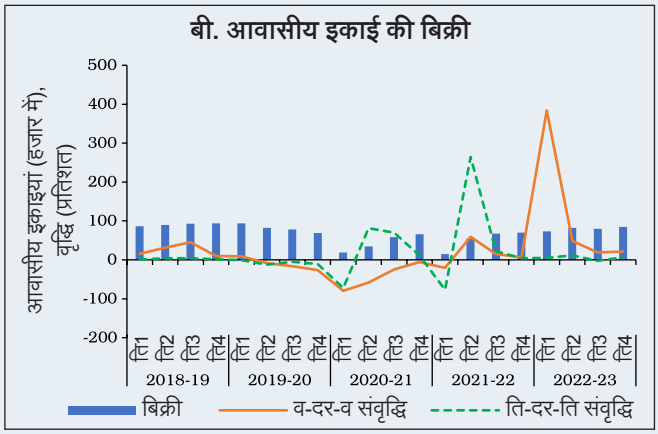

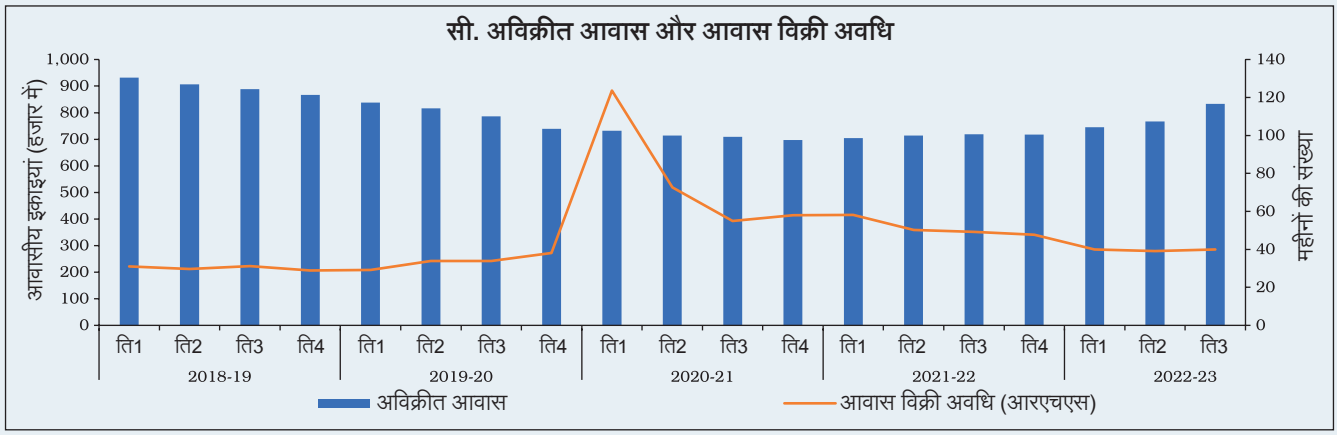

स्रोत: प्रॉपटाइगर।

चार्ट II.2.17: भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र - भारत में उद्यमशीलता गतिविधि

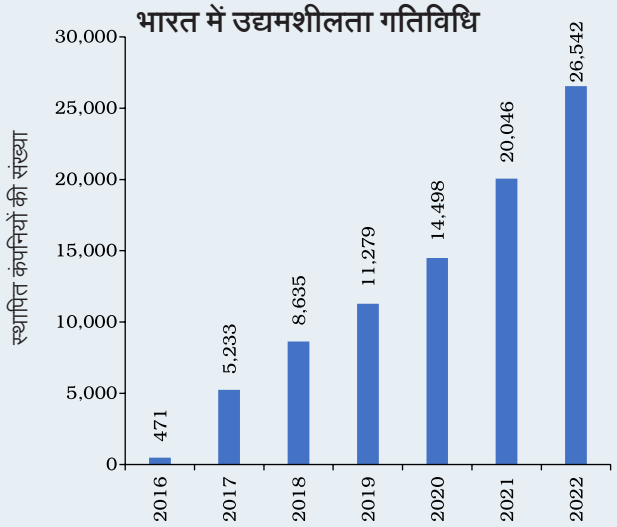

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार।

चार्ट II.2.18: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक

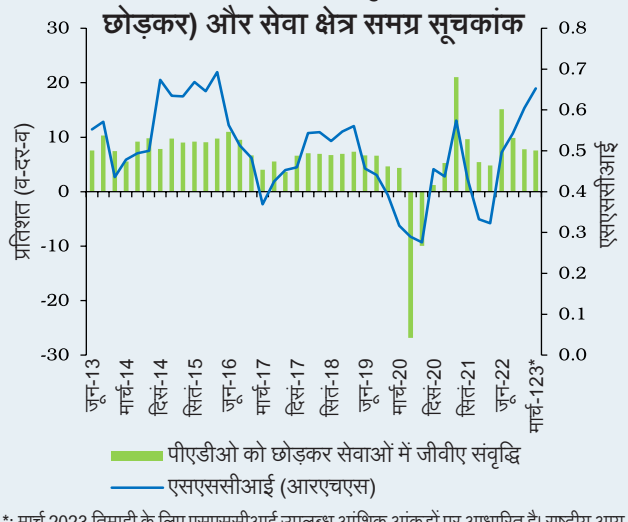

*: मार्च 2023 तिमाही के लिए एसएससीआई उपलब्ध आंशिक आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय आय 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अंतर्निहित जीवीए वृद्धि का उपयोग किया गया है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि यह महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा। पोर्ट कार्गो 2022-23 की पहली छमाही में मजबूत रहा, लेकिन बाद की तिमाहियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के कारण इसमें नरमी आई। जीएसटी ई-वे बिल, जीएसटी राजस्व और रेलवे माल ढुलाई संग्रह ने 2022-23 में उत्साहजनक गति प्रदर्शित की (सारणी II.2.5)।

II.2.32 रिज़र्व बैंक का सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)[6] जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में गतिविधि को ट्रैक करता है और पीएडीओ को छोड़कर, सेवा क्षेत्र में जीवीए संवृद्धि का एक संयोग सूचक है, में 2022-23 की चौथी तिमाही में और संवृद्धि देखी गई (चार्ट II.2.18)।

4. रोजगार

II.2.33 वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के श्रम बाजार संकेतक 2021-22 के दौरान बढ़ती श्रमबल भागीदारी दर के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति का सुझाव देते हैं (चार्ट II.2.19)।

II.2.34 तिमाही पीएलएफएस के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार की स्थिति में 2022-23 के दौरान लगातार सुधार हुआ है। 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान श्रम बल की भागीदारी

चार्ट II.2.19: श्रम बाजार संकेतक (सामान्य स्थिति) - वार्षिक पीएलएफएस

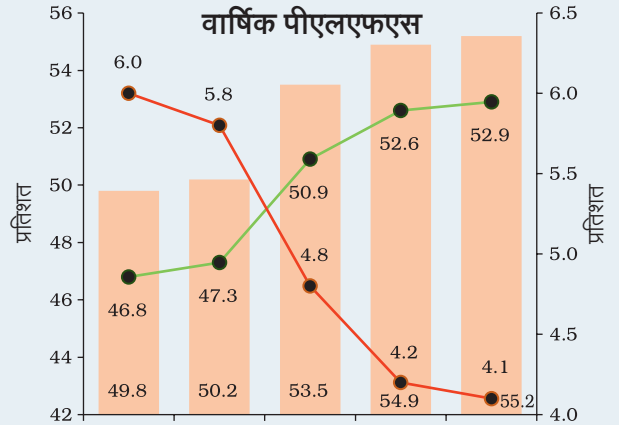

नोट: 1. श्रम बाजार के लिए वार्षिक अवधि जुलाई -जून से संबंधित है।
2. आंकड़े '15 वर्ष और ऊपर' आयु-वर्ग से संबंधित हैं।
स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

[6] एसएससीआई का निर्माण उच्च आवृत्ति संकेतकों, अर्थात् इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर संभाले गए कार्गो, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री /उत्पादन, रेलवे माल यातायात, हवाई यात्री / माल यातायात, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक क्रेडिट और जमा से एकत्र की गई जानकारी को उपयुक्त रूप से निकालकर और संयोजित करके किया जाता है।

चार्ट II.2.20: त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक - शहरी क्षेत्र

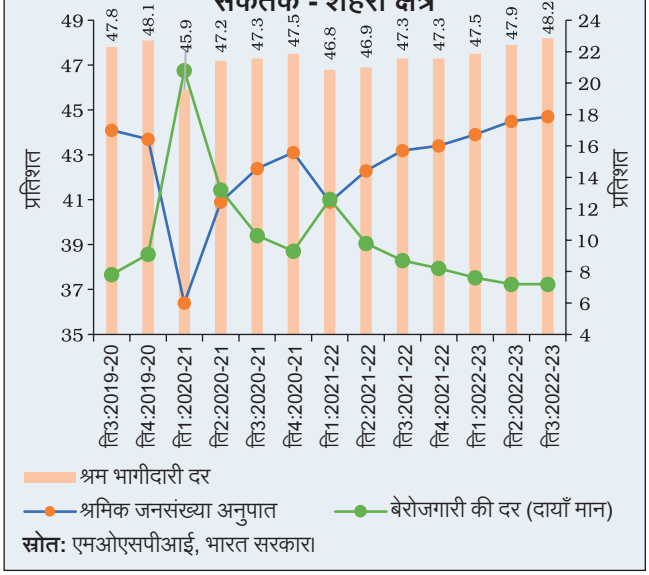

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

चार्ट II.2.21: वैकल्पिक रोजगार संकेतक

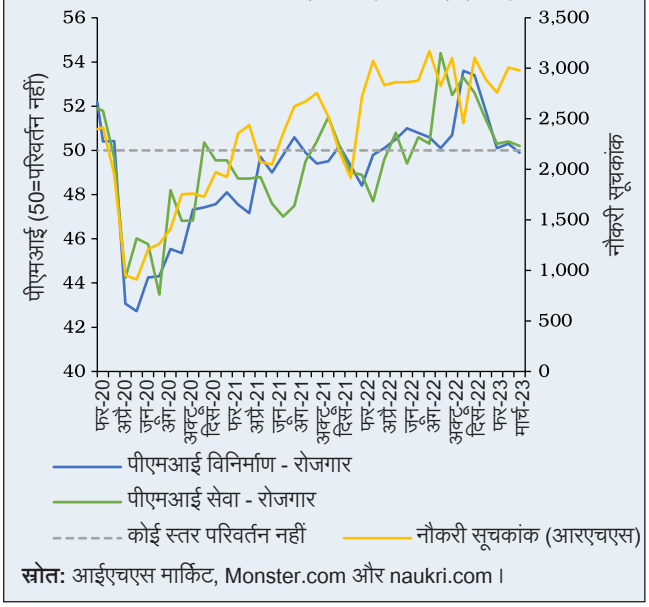

स्रोत: आईएचएस मार्किट, Monster.com और naukri.com ।

ने महामारी से पहले के जनवरी-मार्च 2020 के स्तर को पार कर लिया। श्रमिकों और जनसंख्या का अनुपात अक्तूबर-दिसंबर 2022 के दौरान चरम पर था और बेरोजगारी दर 2017-18 में सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे कम थी (चार्ट II.2.20)।

II.2.35 पेरोल डाटा द्वारा मापा गया संगठित क्षेत्र का रोजगार, 2022-23 में रोजगार सृजन में सुधार का संकेत देता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रति माह जुड़ने वाले औसत शुद्ध अंशधारक 2022-23 के दौरान बढ़कर 11.5 लाख हो गए, जो 2021-22 में 10.2 लाख थे, जो औपचारिक रोजगार अवसरों में बेहतरी का संकेत है।

II.2.36 विभिन्न वैकल्पिक रोजगार संकेतकों ने भी 2022-23 के दौरान रोजगार की स्थिति में लगातार सुधार दिखाया। रोजगार के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में पेरोल नियुक्तियों में लगातार वृद्धि दिखाई। मार्च 2023 में मामूली संकुचन को छोड़कर, 2022-23 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के लिए रोजगार सूचकांक 50 के 'कोई परिवर्तन नहीं' स्तर से ऊपर रहा, जबकि सेवाओं के लिए, यह मई 2022 में मामूली गिरावट को छोड़कर, पूरी अवधि के लिए सकारात्मक था। इसी तरह, नौकरी सूचकांक जो Naukri.com पर नौकरी लिस्टिंग के आधार पर भर्ती गतिविधि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, ने भी 2022-23 के दौरान रोजगार की स्थिति में सुधार दिखाया है (चार्ट II.2.21)।

5. निष्कर्ष

II.2.37 भारत ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच, 2022-23 में सुदृढ़ संवृद्धि का प्रदर्शन किया। मजबूत घरेलू समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों, पूंजीगत व्यय पर राजकोषीय नीतिगत जोर, कॉर्पोरेट क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ तुलनपत्रों, और सरकार द्वारा हाल के वर्षों में घोषित और लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने संवृद्धि की गति को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता को सुदृढ़ किया है। कमजोर बाहरी मांग की स्थिति ने गति कम कर दी। श्रम बाजार की स्थिति सामान्य हो गई है, और असंगठित क्षेत्र की गतिविधि 2022-23 में विस्तार क्षेत्र में लौट आई है। सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम - दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक टीकाकरण अभियानों में से एक, जिसमें दो अरब से अधिक खुराक शामिल हैं- ने उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में सुधार करने में मदद की।

II.3 कीमतों की स्थिति

II.3.1 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई जो मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद नए सिरे से आपूर्ति व्यवधानों के बीच खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, एई में श्रम बाजार की तंग स्थिति, महामारी के समय के निचले स्तर से विकास की गति में आ रही मजबूती और अमेरिकी फेड द्वारा मौद्रिक नीति अति सख्त किए जाने के परिणामस्वरूप ईएमडीई में वित्तीय बाजारों में उत्पन्न अस्थिरता से प्रेरित है। वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते और यह महसूस किए जाने पर कि मूल्य दबाव क्षणभंगुर नहीं है, मौद्रिक नीति को समन्वित रूप से सख्त किया गया, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए एकबारगी नीतिगत कार्रवाई पर जोर दिया गया।

II.3.2 2022 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं, जो कोविड-19 के बाद आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित थीं और जो यूक्रेन में युद्ध से बढ़ गईं, जिससे प्रमुख खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की वैश्विक स्तर पर कमी हो गई। विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक दिसंबर 2021 की तुलना में 54.4 प्रतिशत बढ़कर जून 2022 में शिखर पर पहुंच गया, जबकि खाद्य कीमतों में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मई 2022 में शिखर पर पहुंच गईं तथा 'धातु और खनिज' की कीमतें 21 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2022 में शिखर पर पहुंच गयीं। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, पण्य-वस्तुओं की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ और ऊर्जा मूल्य सूचकांक जून 2022 के स्तर की तुलना में मार्च 2023 में 40.4 प्रतिशत नीचे आया। इसी तरह खाद्य पदार्थों की कीमतों में 15.3 प्रतिशत और धातुओं एवं खनिजों की कीमतों में 23.3 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में और शुरुआती 2023 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद भू-राजनीतिक अनिश्चितता में वृद्धि, वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव, कुछ देशों में कोविड-19 की लहर के फिर से उभरने और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने कीमतों के दबाव को बनाए रखा जिससे मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण सख्ती के बावजूद अवस्फीति की गति सीमित हो गई।

II.3.3 भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति[7], जनवरी-अक्तूबर 2022 के दौरान लगातार मुद्रास्फीति लक्ष्य के स्वीकार्य ऊपरी स्तर से ऊपर रही। खाद्य कीमतों में मौसमी नरमी के कारण नवंबर और दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति में अल्पकालिक कमी देखी गई। जनवरी-फरवरी 2023 में इनमें फिर से वृद्धि हुई और मार्च 2023 में इसमें कमी आई। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के चरम पर पहुंच गई जो निरंतर आपूर्ति व्यवधान, वैश्विक पण्य-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा मूल्यह्रास, यूक्रेन में युद्ध के कारण ईएमडीई को पहुंचे एक जैसे प्रतिकूल वैश्विक आघात के कारण तीन प्रमुख समूहों - खाद्य, ईंधन और कोर (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति में आई

चार्ट II.3.1: सभी प्रमुख घटकों की मुद्रास्फीति

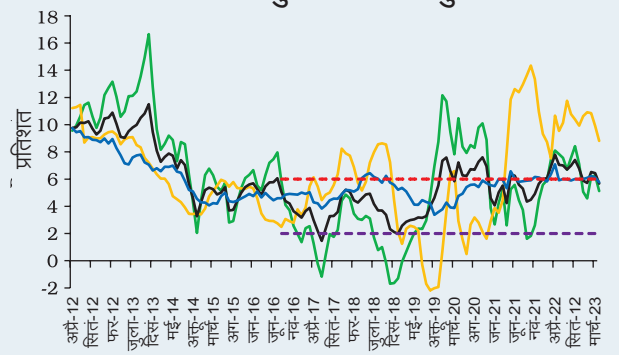

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई-संयुक्त में भार दर्शाते हैं। अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[7] हेडलाइन मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आधार वर्ष: 2012 = 100 लेते हुए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है।

सारणी II.3.1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति – प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7
मानक विचलन	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7
स्क्यूनेस	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1
कर्टोसिस	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6
माध्यिका	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7
अधिकतम	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8
न्यूनतम	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7

टिप्पणी : स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तीव्र वृद्धि से प्रेरित थी - (चार्ट II.3.1)। इसके बाद, आपूर्ति श्रृंखला के दबावों के सामान्य होने, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण इनपुट लागत दबाव में कमी, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से मौद्रिक नीति को कड़ा करने से मूल्य दबाव कम हो गया, जिससे मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर 2022 में ऊपरी स्वीकार्य के स्तर से नीचे आ गई, तथापि जनवरी-फरवरी 2023 में अनाज में उम्मीद से अधिक मूल्य वृद्धि के कारण यह फिर से बढ़ गई। वर्ष के दौरान कोर मुद्रास्फीति आम तौर पर ऊंची और जड़ बनी रही, जो माल मुद्रास्फीति और सेवा मुद्रास्फीति में सूक्ष्म वृद्धि के चलते इनपुट लागत दबाव के क्रमिक प्रभाव को दर्शाता है।

II.3.4 2022-23 में औसत मुद्रास्फीति 2021-22 से तेजी से बढ़ी, जबकि मुद्रास्फीति में अस्थिरता, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है, एक साल पहले की तुलना में मामूली रूप से कम थी (सारणी II.3.1)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कई महीनों में मुद्रास्फीति की स्थिति प्रतिकूल रही जो पूर्व औसत मुद्रास्फीति स्थिति की तुलना में अधिक है।

II.3.5 इस पृष्ठभूमि में उप-खंड 2 में वस्तुओं की वैश्विक कीमतों और मुद्रास्फीति में हुए उतार-चढ़ाव का आकलन किया गया है। उप-खंड 3 में प्रमुख परिवर्तनकारी बिंदुओं सहित भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। इसके बाद उप-खंड 4 में इसके प्राथमिक घटकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कीमतों और लागतों के अन्य संकेतकों का विश्लेषण उप-खंड 5 में किया गया है और इसके बाद निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति विकास

II.3.6 2022-23 की पहली तिमाही में पण्य की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक और वैश्विक मांग में सुधार के कारण हुई थी (चार्ट II.3.2)। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 2022-23 की पहली तिमाही में तेजी

चार्ट II.3.2: अंतराष्ट्रीय पण्य कीमतें

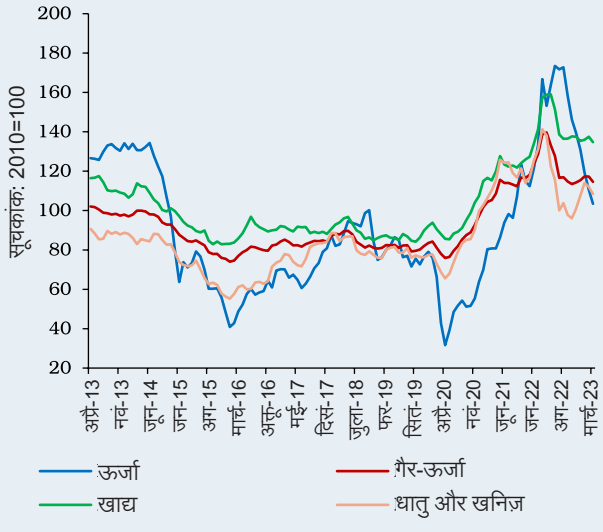

स्रोत : विश्व बैंक पिंक शीट डेटाबेस।

से बढ़ीं और जून 2022 में 117 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के शिखर पर पहुंच गईं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) और उनके सहयोगियों (ओपेक +) के संगठन द्वारा अक्तूबर 2022 में अपने उत्पादन लक्ष्य को 2 मिलियन बैरल प्रति दिन तक कम करने के निर्णय के बावजूद, आपूर्ति बाधाओं में ढील और मौद्रिक नीति के समकालिक सख्ती के कारण मार्च 2023 में कच्चे तेल की कीमतों में 76.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक तेज गिरावट आई (अर्थात जून 2022 के शीर्ष से 34.5 प्रतिशत की गिरावट)। प्राकृतिक गैस की चरम सीमा वाली कीमतें अगस्त 2022 में यूरोप द्वारा सामना की जाने वाली संघर्ष से प्रेरित आपूर्ति बाधाओं को दर्शाती हैं, लेकिन यूरोपीय संघ (ईयू) में हल्की सर्दियों और ऊर्जा संरक्षण उपायों के परिणामस्वरूप यह मार्च 2023 तक काफी कम हो गई। वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ने और मांग में नरमी के कारण 2022-23 से धातु की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। खाद्य तेलों और अनाजों में आपूर्ति की स्थिति में नरमी के साथ अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में मई 2022 के शीर्ष स्तर से नीचे आई, लेकिन प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधों के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण वे संघर्ष-पूर्व स्तर से ऊपर बने रहे। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस और कोयले की ऊंची कीमतों ने उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गईं और इसके परिणामस्वरूप खाद्य फसलों के लिए इनपुट लागत बढ़ गई। इन वैश्विक पण्य मूल्य वृद्धि को दर्शाते हुए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एई और ईएमडीई दोनों में बढ़ी, जिससे वर्ष के दौरान समकालिक मौद्रिक नीति सख्त करने की आवश्यकता महसूस हुई (चार्ट II.3.3)।

चार्ट II.3.3: सभी देशों की मुद्रास्फीति

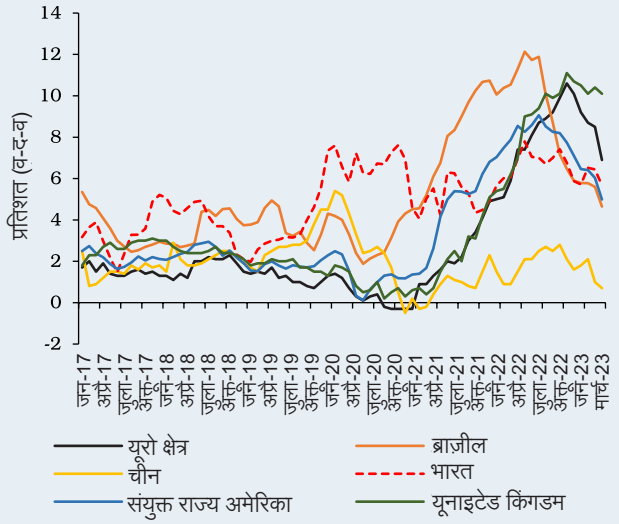

स्रोत : सीईआईसी।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.3.7 खाद्य कीमतों में मौसमी नरमी के कारण नवंबर-दिसंबर के दौरान नरम पड़ने से पहले भारत में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से लगातार 10 महीनों के लिए 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर रही। मुद्रास्फीति जनवरी-फरवरी 2023 में फिर से बढ़ी और मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई (चार्ट II.3.4)। वर्ष के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि व्यापक आधार पर थी जो वैश्विक वस्तुओं की उच्च कीमतों (कच्चे तेल, धातुओं और खाद्य कीमतों) और प्रतिकूल घरेलू मौसम की स्थिति के कारण था। यूक्रेन में युद्ध के पश्चात अप्रैल 2022 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद वैश्विक आपूर्ति स्थितियों में क्रमिक सुधार, रिकॉर्ड घरेलू खाद्य उत्पादन, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और कम आयात शुल्क सहित सरकार द्वारा किए गए लक्षित आपूर्ति पक्ष के उपायों और कुछ मुद्रास्फीति संवेदनशील कृषि वस्तुओं पर निर्यात

चार्ट II.3.4: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

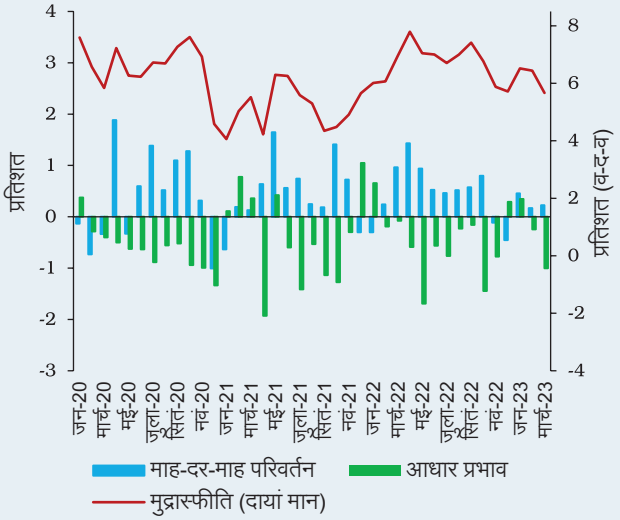

टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रतिबंध लगाने के कारण मुद्रास्फीति कम हो गई। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी सख्ती ने भी 2022-23 की दूसरी छमाही में मूल्य दबाव को नियंत्रित करने में मदद की (बॉक्स II.3.1)।

बॉक्स II.3.1
मौद्रिक नीति और अवस्फीति

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और इसे तत्काल प्राथमिकता के रूप में सहनीयता बैंड के भीतर लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की।

मौद्रिक सख्ती की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 1998-99 की पहली तिमाही से 2021-22 की चौथी तिमाही तक की अवधि के लिए डेटा को शामिल करके एक डमी चर के माध्यम से कोविड-19 महामारी के आघातों के लिए अनुमानित चार चर वीएआर मॉडल का प्रयोग वास्तविक जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि, सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष), सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा और नीतिगत ब्याज दर को प्रमुख चर के रूप में उपयोग करते हुए किया जाता है । आवेग प्रतिक्रिया परिणाम मौद्रिक नीति के आघातों के लिए विकास और मुद्रास्फीति की सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं (चार्ट 1)। नीतिगत दर में एक प्रतिशत अंक (पीपी) की वृद्धि से तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 30 आधार अंकों की गिरावट का अधिकतम प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव 8वीं तिमाही तक रहता है। मुद्रास्फीति पर प्रभाव 5वीं तिमाही में 22 बीपीएस का अधिकतम प्रभाव के साथ और लंबे समय, यहां तक कि चार वर्ष से भी आगे तक भी उच्च अंतराल के साथ बना रहता है ।

उसी वीएआर मॉडल का उपयोग करते हुए चो और मोरेनो (2006) के बाद, समय पर और एकबारगी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के महत्व का आकलन करने के लिए एक नीति प्रतिक्रिया प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत स्थितियों में यह कार्य 2022-23 की पहली तिमाही को शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग कर और मौद्रिक नीति संचरण के लिए आठ तिमाहियों तक के प्रभाव का आकलन निम्नलिखित तीन परिदृश्यों के अंतर्गत किया जाता है: (ए) कोई नीतिगत बदलाव नहीं या पूरी अवधि के लिए रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना; (ख) 2022-23 की प्रथम तिमाही में केवल एक बार नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों की वृद्धि; और (ग) वर्तमान नीतिगत परिदृश्य के तहत सख्त रुख *अर्थात* फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि। इस अभ्यास के अनुकरण परिणाम बताते हैं कि नीतिगत परिवर्तन नहीं होने के परिदृश्य के तहत मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती और आठवीं तिमाही के अंत तक यह 7.3 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई होती (चार्ट 2)। दूसरे परिदृश्य में मुद्रास्फीति नीतिगत बदलाव नहीं होने की स्थिति की तुलना में करीब 25 आधार अंक कम होती। हालांकि, मौजूदा सख्त मौद्रिक नीति रुख (परिदृश्य सी) के तहत, मुद्रास्फीति में 50 बीपीएस से अधिक की कमी आने का अनुमान है, जबकि नीतिगत रेपो दर के तहत मुद्रास्फीति में लगभग 90 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसे 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। सख्त नीतिगत रुख को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों ने विकास को लगभग 65 बीपीएस तक कम

चार्ट 1: नीतिगत दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि पर आवेग प्रतिक्रिया

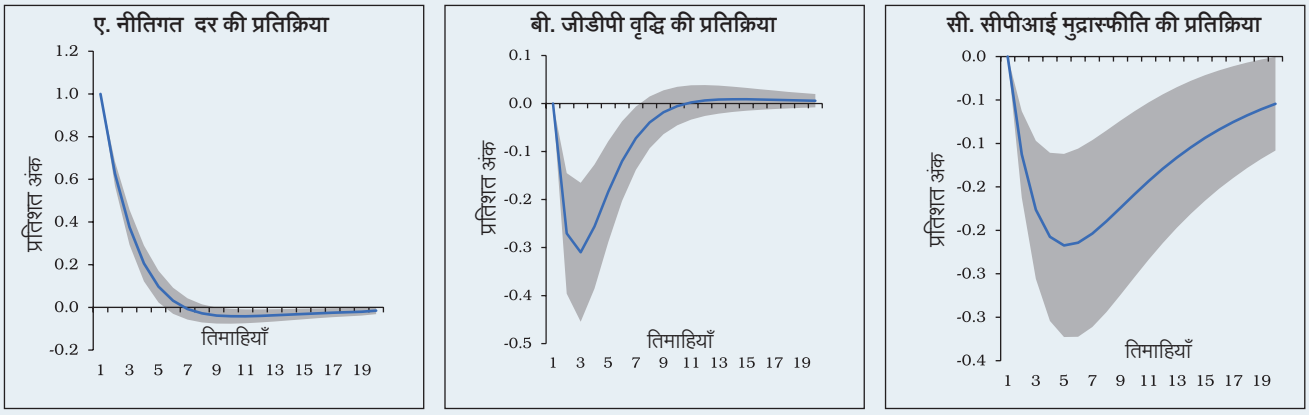

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

चार्ट 2 : जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति का प्रभाव

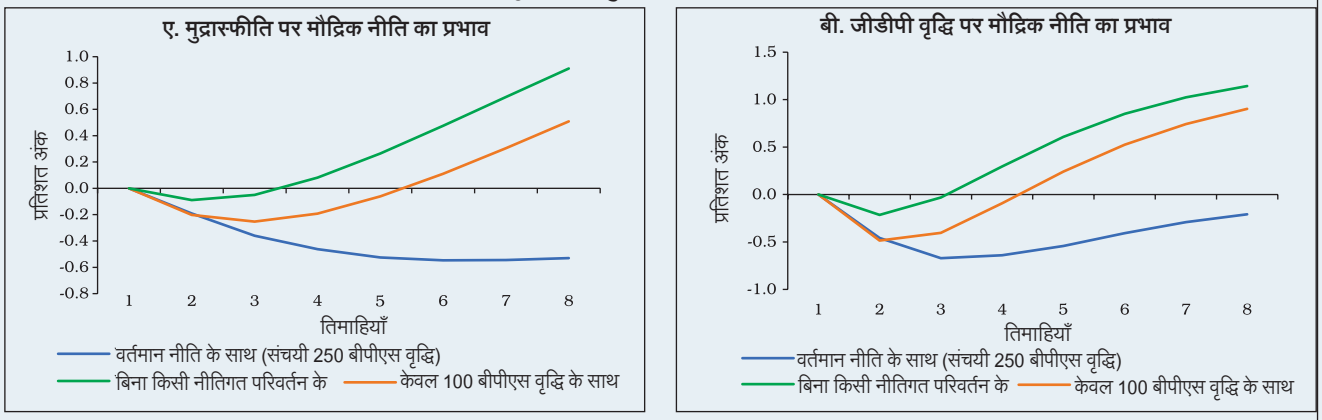

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कर दिया होगा। एकबारगी नीतिगत कार्रवाई का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति 90 बीपीएस अधिक होती, जबकि रेपो दर में केवल 100 बीपीएस की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति केवल 25 बीपीएस कम होती।

संदर्भ:

चो, एस., एन्ड मोरेनो, ए. (2006), 'ए स्मॉल-सैम्पल स्टडी ऑफ द न्यू-केनिसियन मैक्रो मॉडल, 'जर्नरल ऑफ मनी, क्रेडिट एन्ड बैंकिंग', खंड 38, अंक 6, 1461-1481 ।

II.3.8 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति निर्माण का प्राथमिक स्रोत थी, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान पिछले वर्ष के 35.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 46.4 प्रतिशत हो गया। खाद्य की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति में कमी और प्रतिकूल घरेलू मौसम की स्थिति के कारण प्रमुखता से अनाज, सब्जियों और खाद्य तेलों के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आई।

II.3.9 2022-23 में ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति औसतन 10.3 प्रतिशत थी, जो मिट्टी के तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में तेज उछाल से प्रेरित थी, जो कि यूक्रेन में युद्ध के बाद ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। अक्तूबर 2022 तक अवस्फीति में रहने के बाद प्रतिकूल आधार प्रभाव और कुछ राज्यों में शुल्क में वृद्धि के कारण नवंबर 2022 में बिजली की कीमतों में 3.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

II.3.10 खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति या मुख्य मुद्रास्फीति, पूरे वर्ष लगभग 6 प्रतिशत के लगातार उच्च स्तर पर बनी रही। मूल्य दबाव व्यापक आधार पर थे जो इनपुट लागत दबावों और घरेलू मांग की वसूली को दर्शाते थे (बॉक्स II.3.2)। आपूर्ति के आघातों, मांग में सुधार, मुद्रास्फीति की उम्मीदें, विनिमय दर में गिरावट, राजकोषीय रुख जैसे कारकों ने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया (आरबीआई, 2023)[8]। अप्रैल 2022 में तेज उछाल के बाद, हालांकि, कीमतों का दबाव कुछ हद तक कम हो गया, जिसमें 22 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल में उत्पाद शुल्क में कटौती सहित सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के उपायों से सहायता मिली। मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के मुख्य चालक कपड़े और जूते, आवास, परिवहन और संचार, स्वास्थ्य, घरेलू सामान और सेवाएं और आमोद-प्रमोद थे।

II.3.11 2022-23 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत थी, जो एक साल पहले की तुलना में 115 बीपीएस अधिक थी (परिशिष्ट सारणी 4)।

[8] आरबीआई (2023), "भारत के लिए एक रीकैलिब्रेटेड त्रैमासिक प्रोजेक्शन मॉडल (क्यूपीएम 2.0)", आरबीआई बुलेटिन, फरवरी।

बॉक्स II.3.2
भारत में मुद्रास्फीति संबंधी हाल की स्थिति - मांग की तुलना में आपूर्ति की भूमिका

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के कठिन कार्य में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मांग और आपूर्ति की भूमिका के बीच अंतर की पहचान करना मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि आपूर्ति आघातों के बने रहने तथा आर्थिक विकास दमित रहने से (शापिरो, 2022 ए) उच्च मुद्रास्फीति होने का जोखिम बढ़ता है, इसलिए आपूर्ति में बार-बार अस्थिरता के विभिन्न चरणों या दौर में आपूर्ति आघातों से संबंधित योगदान को समझना अनिवार्य है।

पाठ में, संयुक्त राज्य अमेरिका (शापिरो, 2022 ए और 2022 बी) के मामले में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) से समान मूल्य तथा मात्रा डेटा, और जहां समान मूल्य और मात्रा डेटा उपलब्ध नहीं हैं वहां घरेलू उपभोग व्यय के लिए त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा डेटा (ओईसीडी, 2022) का उपयोग मांग और आपूर्ति के आघातों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यह रोलिंग विंडो पर द्वि-भिन्नरूपी वेक्टर ऑटो प्रतिगामी (वीएआर) मॉडल चलाकर और उनके अवशिष्ट की व्याख्या करके विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य और मात्रा के आघातों की दिशा की पहचान करके किया जाता है। समान संकेतों के साथ मूल्य और मात्रा अवशिष्ट को मांग को प्रतिबिंबित करने के लिए माना जाता है - उच्च मांग कीमतों और मात्रा, दोनों को एक ही दिशा में धकेलती है और इसके विपरीत दिशा में विपरीत भी होता है- जबकि विपरीत संकेत वाले अवशिष्ट आपूर्ति आघातों से संबंधित होते हैं - कम आपूर्ति का अर्थ मात्रा में कमी लेकिन कीमत में वृद्धि है।

चूंकि भारत के संबध में सीपीआई मदों के लिए समान मूल्य और मात्रा डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कीमतों से संबंधित 23 सीपीआई उप-समूह डेटा को सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) सीपीएचएस (उपभोक्ता पिरामिड व्यय सर्वेक्षण) उपभोग व्यय डेटा[9] में मैप किया जाता है, जिसे बाद में संबंधित सीपीआई द्वारा मात्रा के लिए प्रॉक्सी प्राप्त करने के लिए घटाया जाता है। एकसमान आधार प्राप्त करने के लिए इन 23 मैप किए गए सीपीआई उप-समूहों और संबंधित सीएमआईई सीपीएचएस व्यय श्रेणियों को जनवरी 2014 = 100 पर पुनर्स्थापित किया गया है और फिर डी-सीजनलाइज किया गया है। सीएमआईई सीपीएचएस डेटा की उपलब्धता के आधार पर विश्लेषण के लिए नमूना अवधि जनवरी 2014 से दिसंबर 2022 है। ओईसीडी, 2022 के अनुसार, कीमतों और मात्राओं के लिए दो समीकरणों वाला वीएआर मॉडल निम्नानुसार 5 साल की रोलिंग विंडो के लिए चलाया गया:

$$P_{i,t} = z_{i,t-1}\,\gamma + \varepsilon^{p}_{i,t} \qquad ...(1)$$

$$Q_{i,t} = z_{i,t-1}\,\gamma + \varepsilon^{q}_{i,t} \qquad ...(2)$$

जहां $P_{i,t}$ और $Q_{i,t}$ महीने *t* में श्रेणी *i* के लिए क्रमशः कीमत और मात्रा सूचकांकों के लॉग मान हैं, और $z_{i,t-1}$ महीने *t* में श्रेणी *i* के क्रमशः लॉग कीमत और लॉग मात्रा सूचकांकों के अंतराल का एक वेक्टर है, और $\varepsilon^{p}_{i,t}$ एवं $\varepsilon^{q}_{i,t}$ महीने *t* में श्रेणी *i* के लिए कीमत और मात्रा अवशिष्ट हैं।

मूल्य और मात्रा, दोनों के एक-अवधि आगे के पूर्वानुमान 23 समान श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए प्राप्त किए गए और उनके वास्तविक मूल्यों के साथ तुलना की गई।

जनवरी 2019-दिसंबर 2022 के दौरान प्रत्येक महीने में 23 उप-समूहों को मांग, आपूर्ति और अस्पष्ट[10] में वर्गीकृत करने के बाद, इन उप-समूहों के सीपीआई भार का उपयोग सीपीआई मुद्रास्फीति में उनके योगदान की गणना करने के लिए किया गया और फिर मांग और आपूर्ति संचालित मुद्रास्फीति की सीमा को निर्धारित करने के लिए मांग संचालित, आपूर्ति संचालित और अस्पष्ट घटकों में एकत्र किया गया। परिणाम बताते हैं कि खाद्य समूह के भीतर सब्जियां, दूध, तेल और वसा, चीनी, अंडे, और मांस तथा मछली ने लगातार आपूर्ति-पक्ष का दबाव अनुभव किया, जबकि गैर-मादक पेय, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामान, शिक्षा और आमोद तथा मनोरंजन मुख्य रूप से मांग पक्ष कारकों से प्रभावित हुए। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति में मांग पक्ष के कारकों का औसत योगदान 2019 में 35.2 प्रतिशत था, जो कोविड-19 आघात के दौरान घटकर 2020 में 24.6 प्रतिशत हो गया, और फिर धीरे-धीरे सुधरकर 2021 में 31.8 प्रतिशत और 2022 में 30.50 प्रतिशत हो गया। अक्तूबर-नवंबर 2019 में अधिक बारिश से उत्पन्न आपूर्ति आघातों के दौरान और कोविड-19 के विभिन्न चरणों के दौरान आपूर्ति पक्ष के कारक हावी रहे और पूरे नमूना अवधि के दौरान सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति में उनका लगभग 55 प्रतिशत योगदान रहा (चार्ट 1)।

(जारी)

[9] सीएमआईई सीपीएचएस डेटा से विभिन्न उप समूहों के लिए प्राप्त व्यय शेयर आवास किराये को छोड़कर अधिकांश उप-समूहों के लिए सीपीआई भारिता के बराबर हैं।

[10] यदि पूर्वानुमानित मूल्य और मात्रा के लिए अवशिष्ट के संकेत समान हैं, तो इसे मांग संचालित के रूप में व्याख्या की जाती है और यदि यह विपरीत संकेत है, तो इसे आपूर्ति संचालित के रूप में व्याख्या किया जाता है। इसके अलावा, यदि वास्तविक मूल्यों में से कोई एक अपने अनुमानित मूल्य के काफी करीब है (अवशिष्ट सांख्यिकीय रूप से शून्य से अविभेद्य है), *यानी,* यदि मूल्य या मात्रा में अप्रत्याशित परिवर्तन प्रत्येक रोलिंग 5 साल की विंडो में अवशिष्ट के 45वें और 55वें पर्सेंटाइल के बीच होता है, तो श्रेणी को अस्पष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट 1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के चालक

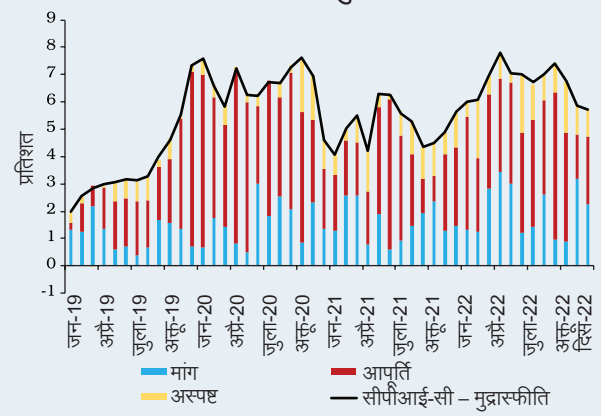

स्रोत : एनएसओ, सीएमआईई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

यूक्रेन में युद्ध के बाद से, आपूर्ति पक्ष के कारकों के अलावा, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने में मांग पक्ष के कारकों की भूमिका भी बढ़ी है, जो मार्च-मई 2022 के दौरान लगभग 42.5 प्रतिशत और त्यौहारी मांग में तेजी के कारण नवंबर 2022 में 54.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस अध्ययन का निष्कर्ष मई 2022 में उचित समय पर की गई मौद्रिक सख़्ती, वर्ष के दौरान यह सख़्ती जारी रखने तथा नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि का समर्थन करता है। इस प्रकार, संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति के बीच विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर उठाए गए नीतिगत कदम समय के अनुसार उचित थे।

संदर्भ:

1. शापिरो, एएच (2022 ए), 'ए सिंपल फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इन्फ्लेशन', *फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को*, वर्किंग पेपर 2020-29।
2. शापिरो, एएच (2022 बी), 'हाऊ मच डू सप्लाय एंड डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन?', *फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को इकोनॉमिक लेटर*, 15।
3. ओईसीडी (2022), 'सप्लाय-एंड डिमांड-ड्रिवन इन्फ्लेशन इन ओईसीडी इकॉनोमीज़', *इकोनॉमिक आउटलुक*, वॉल्यूम 2022, अंक 2।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

II.3.12 वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों से प्रेरित थी, इसके बाद ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते, परिवहन और संचार, और स्वास्थ्य और शिक्षा का स्थान रहा (चार्ट II.3.5)।

चार्ट II.3.5: मुद्रास्फीति के चालक (वर्ष-दर-वर्ष)

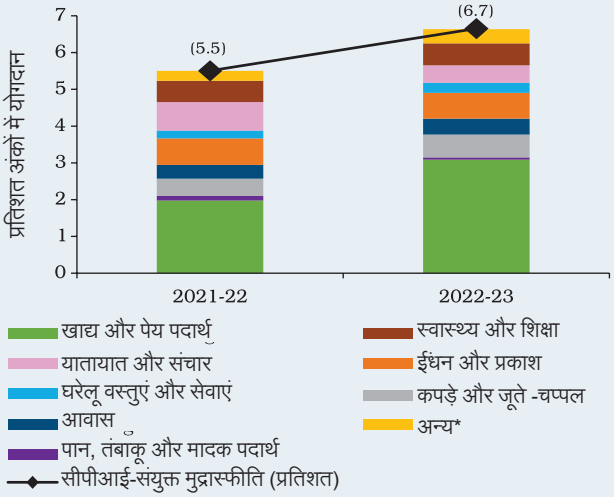

*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

खाद्यान्न

II.3.13 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में भार: 45.9 प्रतिशत) 2022-23 में 4.6 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत के एक विस्तृत दायरे में परिवर्तनशील थी, जो आघातों के संयोजन को दर्शाती है, यथा - संघर्ष प्रेरित, वैश्विक खाद्य और उर्वरक मूल्य वृद्धि, घरेलू रबी फसल उत्पादन पर गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव और कृषि इनपुट के बढ़े हुए लागत के दबाव - और मौसमी मूल्य-प्रवृत्ति। सब्जियों, तेल और वसा, पशु प्रोटीन, और अनाज और उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पहली छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति-वृद्धि के प्रमुख कारक थे, जबकि सब्जियों और तेल और वसा की कीमतों में कमी से दूसरी छमाही में नरमी आई (चार्ट II.3.6)।

II.3.14 वर्ष 2021-22 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत रही। खाद्य समूह के भीतर पांच उप-समूहों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में कुल बारह उप-समूहों में से शेष सात उप-समूहों में यह कम हुई (चार्ट II.3.7)। अनाज, सब्जियों और मसालों की कीमतों में वर्ष की एक प्रमुख अवधि के दौरान

चार्ट II.3.6: खाद्य मुद्रास्फीति चालक (वर्ष-दर-वर्ष)

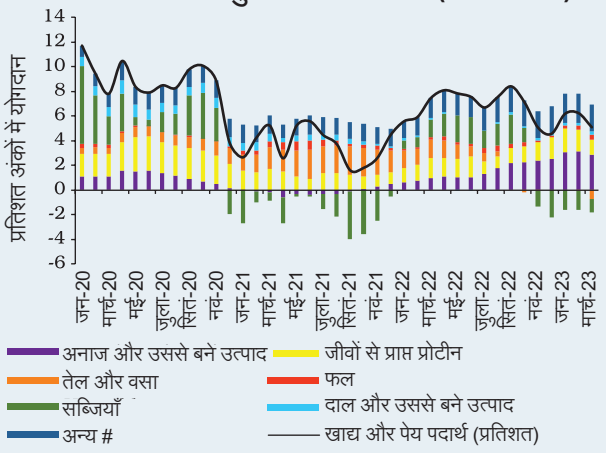

*: इसमें मांस और मछली, अंडे और दूध और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
#: चीनी और मिष्ठान्न, मसाले, एल्कोहोल मुक्त पेय-पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं।
टिप्पणी : अप्रैल 2020 के लिए मांस तथा मछली और तैयार भोजन, आदि का सूचकांक और मई 2020 के लिए तैयार भोजन, आदि का सूचकांक एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.7: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति

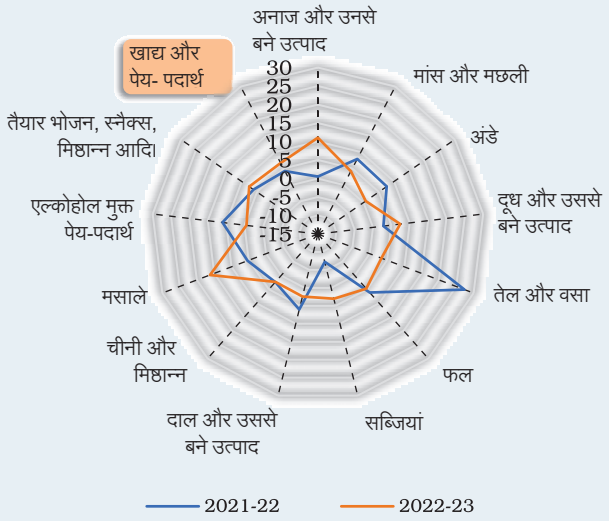

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उच्च मुद्रास्फीति का दबाव देखा गया, जिससे समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई।

II.3.15 वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में गर्मी की शुरुआत, ताप की लहरों और अत्यधिक बारिश ने सब्जियों की कीमतों (भार: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 13.2 प्रतिशत) को बढ़ा दिया, जो नवंबर 2022 में नई फसल की आवक के साथ कम हो गया (चार्ट II.3.8ए और II.3.8बी)। परिणामस्वरूप, अक्तूबर 2022 तक वृद्धि के बाद नवंबर में सब्जियों की कीमतों की संचयी गति तेजी से कम हुई और दिसंबर 2022 से ऋणात्मक हो गई और वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

II.3.16 अच्छी *रबी* फसल [2020-21 के अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में तीसरे उन्नत अनुमानों (एई) के अनुसार 2021-22 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि] और 2022-23 के लिए मूल्य स्थिरीकरण बफर हेतु केंद्र द्वारा 2.5 लाख टन की रिकॉर्ड खरीद (2021-22 की तुलना में 0.5 लाख टन अधिक) के

चार्ट II.3.8: सीपीआई-सब्जी कीमतों और तापमान विसंगति में मौसमी प्रभाव

ए: सीपीआई-सब्जियां (संचयी उतार-चढ़ाव)

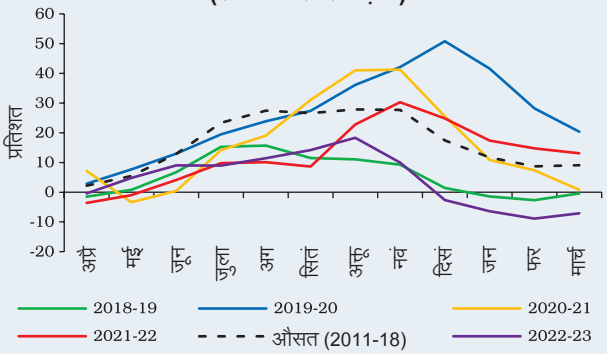

बी: तापमान विसंगति

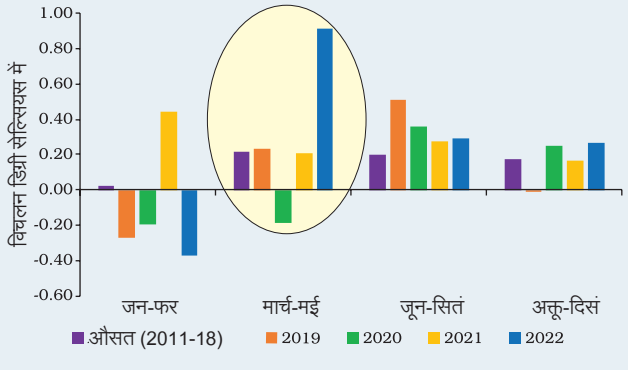

टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, तापमान विसंगति को 30-वर्ष के औसत (1981 से 2010) से विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: एनएसओ, एन्वी स्टैट्स इंडिया 2022, सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

कारण, अप्रैल-मई 2022 के दौरान प्याज की कीमतों में नरमी आई। हालांकि, बाद के महीनों में (सितंबर 2022 को छोड़कर) नवंबर 2022 तक मांग में मौसमी वृद्धि और प्रमुख *खरीफ* प्याज उत्पादक राज्यों में कम और अत्यधिक वर्षा दोनों के कारण *खरीफ* उत्पादन में कमी के कारण मूल्य दबाव उभरा। 2022-23 में टमाटर की कीमतों में, अप्रैल-जून 2022 के दौरान तेज गर्मी के कारण अस्थिरता आई और इसके बाद अगले दो महीनों में कीमतें कम हुईं और मानसून की अनिश्चितता के कारण सितंबर-अक्तूबर 2022 के दौरान कीमत-वृद्धि का एक और दौर चला। कीमतों में उतार-चढ़ाव तीव्र मौसम की घटनाओं से प्रेरित था, जिसमें उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, पूरे देश में मानसून का असमान वितरण और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक वर्षा शामिल थी, जिसके कारण फसल की क्षति हुई और बाज़ार में आमद में देरी हुई। उत्पादन में गिरावट [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई में (-) 4.0 प्रतिशत] ने भी 2022 की शुरुआत में आपूर्ति को कम कर दिया। नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान बेमौसम बारिश के कारण कम उत्पादन [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई में (-) 5.0 प्रतिशत] और नयी फसलों की आमद में देरी के कारण अप्रैल-अक्तूबर 2022 (सितंबर को छोड़कर) के दौरान आम तौर पर आलू की कीमतों में भी वृद्धि हुई। सरकार ने जुलाई 2022 में बिना किसी लाइसेंस के 30 जून 2023 तक भूटान से आलू के मुफ्त आयात की अनुमति दी ताकि बढ़ते मूल्य दबावों को नियंत्रित किया जा सके। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज ने बाजार में ताजा स्टॉक भेजा, नवंबर 2022 से कीमतों में गिरावट आई।

II.3.17 अनाज और उत्पादों की कीमतों (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21.1 प्रतिशत भार) ने 2022-23 में स्थिर वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है। पंजाब और हरियाणा के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गर्मी की लहरों और अगस्त 2022 से रुक-रुक कर बफर मानदंडों के नीचे स्टॉक स्तर में गिरावट के कारण 2021-22 में घरेलू उत्पादन में गिरावट [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 एफई के अनुसार (-)1.7 प्रतिशत] की वजह से गेहूं की कीमतों में मजबूती आई। वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों से मूल्य दबाव बढ़ गया था जिसके कारण उच्च निर्यात (अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान 11.8 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष) हुआ, जिससे गेहूं की घरेलू आपूर्ति में कमी आई। घरेलू कीमतों में तेज वृद्धि ने सरकार को मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और बाद में अगस्त 2022 से गेहूं उत्पादों के निर्यात पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया, हालाँकि, सरकार - से - सरकार के माध्यम से निर्यात जारी रहा। चावल के मूल्य में दबाव, *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) के तहत गेहूं वितरण की जगह चावल के वितरण, के साथ-साथ, निर्यात में वृद्धि (2022-23 के दौरान 5.2 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष) और अनुमानित *खरीफ* उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण आया [2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 तीसरे एई में (-) 0.9 प्रतिशत]। सरकार द्वारा आपूर्ति-पक्ष के उपाय - गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाना और मजबूत बफर स्टॉक के साथ सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर रोक (जो 1 अप्रैल 2023 के मानक से 3.2 गुना अधिक था) ने मूल्य वृद्धि सीमा को सीमित रखने में मदद की।

II.3.18 पशु प्रोटीन युक्त वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत का वजन) के मामले में, फीड और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण 2022-23 की पहली तिमाही में मांस और मछली में मूल्य दबाव देखा गया (चार्ट II.3.9 ए)। श्रावण माह के कारण मौसमी मांग में गिरावट और मई 2022 में सरकार द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन भोजन के 0.55 मिलियन टन के अतिरिक्त आयात को मंजूरी देने के कारण कीमतों का दबाव बाद में कम हो गया। हालांकि, कम होने से पहले, सितंबर-अक्तूबर में कीमत दबाव फिर से उभरा। अंडे की कीमतें अस्थिर रहीं और बढ़ती फीड लागत से भी प्रेरित थीं। दूध और उत्पादों के मामले में कीमतें पूरे

वर्ष बढ़ती रहीं क्योंकि प्रमुख दूध सहकारी समितियों जैसे अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ती फीड लागत दबाव का हवाला देते हुए वर्ष के दौरान कई बार अपने खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की (चार्ट II.3.9 बी)।

II.3.19 जून 2022 के बाद से तेलों और वसा (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का भार) में मूल्य दबाव धीरे-धीरे कम हो गया क्योंकि खाद्य तेलों, विशेष रूप से पाम तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी से गिरावट आई (चार्ट II.3.10)। यूक्रेन संघर्ष और अप्रैल 2022 में इंडोनेशिया द्वारा कच्चे पाम तेल पर निर्यात प्रतिबंध लगाने के कारण वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च-मई 2022 के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इसके अलावा, खाद्य तेलों के लिए आयात पर उच्च निर्भरता के कारण भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भी बढ़ती घरेलू कीमतों में उछाल आया। वैश्विक कीमतों में नरमी, निर्यात प्रतिबंध हटने और इंडोनेशिया द्वारा 31 अक्तूबर 2022 तक निर्यात शुल्क हटाने के साथ कीमतों की गति धीरे-धीरे कम हो गई। सरकार ने कई आपूर्ति-पक्ष उपाय भी किए जिनमें मार्च 2024 तक कच्चे पाम तेल, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर शून्य प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ाना, परिष्कृत सोयाबीन, और सूरजमुखी और पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क

चार्ट II.3.10: सीपीआई-तेल और वसा (संचयी उतार-चढ़ाव)

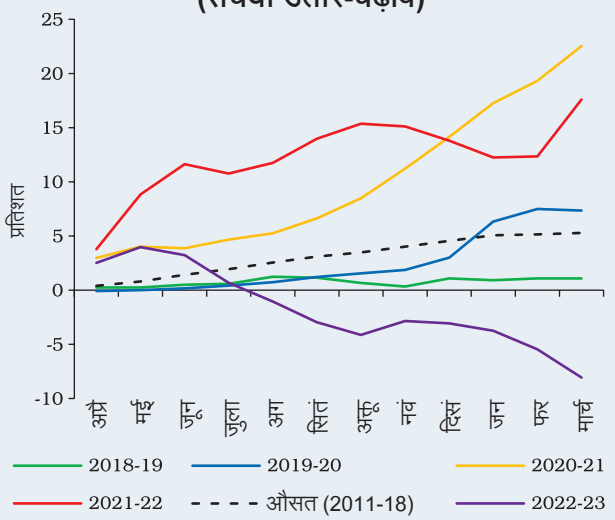

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

को घटाकर क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत (32.5 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत से) करना शामिल है। मार्च 2023 तक रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनके अलावा, सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा भी लागू की और 2022-23 के लिए 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात के लिए आवंटित टैरिफ रेट कोटा

चार्ट II.3.9: सीपीआई - पशु प्रोटीन: कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव

ए: सीपीआई-अंडे, मांस और मछली (संचयी उतार-चढ़ाव)

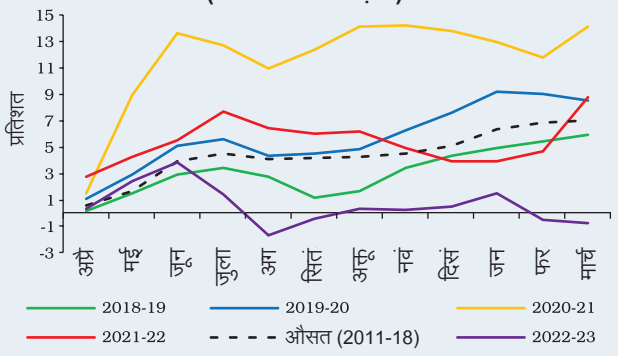

बी: सीपीआई-दूध और उत्पाद (उतार-चढ़ाव)

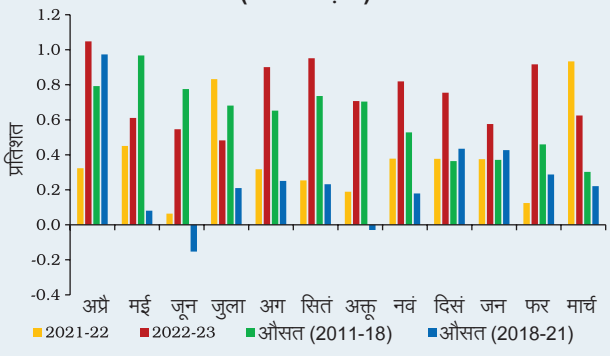

टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए, मांस और मछली के लिए सूचकांक संख्या एनएसओ के है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(टीआरक्यू) पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचनात्मक विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट दी। इन उपायों से खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार गिरावट आई।

II.3.20 दालों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का भारांक) 31 मार्च 2024 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर और उड़द के आयात में वृद्धि, मार्च 2024 तक मसूर के आयात पर शून्य एआईडीसी के विस्तार और 2021-22 में उच्च उत्पादन के कारण 2022-23 में कम रही (चार्ट II.3.11)। लेकिन 2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 के तीसरे एई के अनुसार अरहर और उड़द दोनों के अनुमानित खरीफ उत्पादन में क्रमशः 18.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण अगस्त 2022 से कीमतों में वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल के उपायों, जिसमें किसानों से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए सरकारी सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना और रबी फसल की अधिक बुवाई शामिल है, के कारण अक्तूबर से कीमत दबावों में कमी आई।

II.3.21 फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भार) वर्ष के दौरान काफी हद तक सीमित रही, जो मुख्य रूप से मौसमी फलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रेरित थी। गर्मी की लहरों और बेमौसम बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के कारण आम की कीमतों में वृद्धि से अप्रैल 2022 में कीमतों के दबाव में तेज वृद्धि हुई, जो आवक में वृद्धि के साथ धीरे-धीरे कम हो गई। हालांकि, केला, पपीता और अन्य ताजे फलों की मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है, जिससे फरवरी-मार्च 2023 के दौरान फलों की मुद्रास्फीति बढ़ गई है।

II.3.22 अन्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख मसालों विशेष रूप से सूखी मिर्च, जीरा और धनिया में 2021-22 में घरेलू उत्पादन [(-) 2.7 प्रतिशत एफई 2020-21 की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई के अनुसार] में समग्र गिरावट के कारण मसालों में वर्ष 2022-23 में औसतन 16.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई।

ईंधन

II.3.23 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत भार) का योगदान पिछले वर्ष के 13.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10.5 प्रतिशत हो गया। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि के अनुसरण में घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन मुद्रास्फीति वर्ष के अधिकतम भाग में दोहरे अंकों में रही (चार्ट II.3.12 और चार्ट II.3.13)। फिर भी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई कमी और एलपीजी और बिजली की कीमतों में कोई खास वृद्धि नहीं

चार्ट II.3.11: सीपीआई में घटक-वार योगदान - दाल मुद्रास्फीति

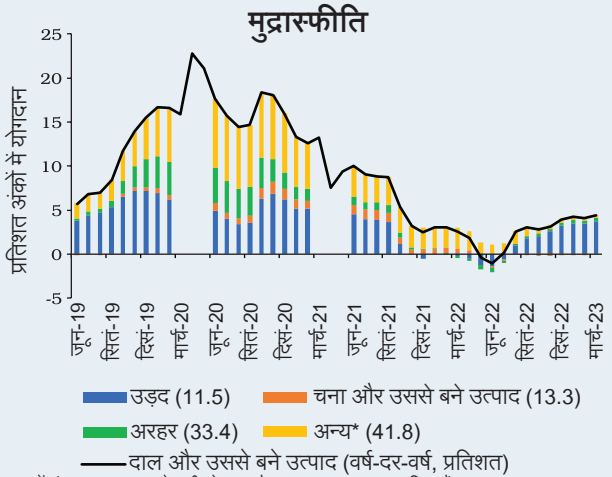

*: इसमें मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, बेसन और अन्य दाल उत्पाद शामिल हैं।
टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-दालों और उससे बने उत्पादों में भार को इंगित करते हैं।
2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.12: ईंधन मुद्रास्फीति के चालक

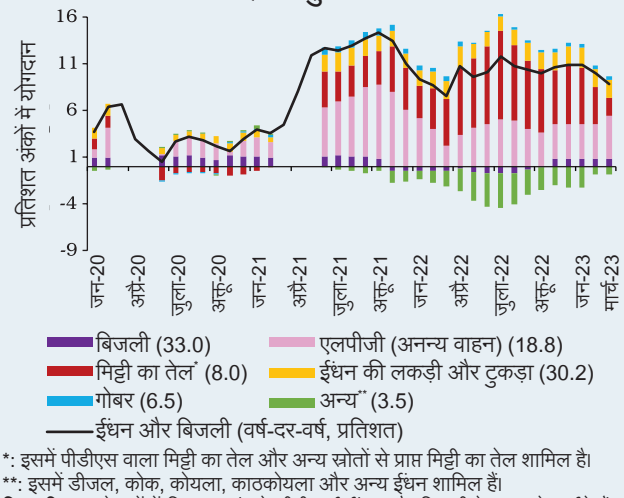

*: इसमें पीडीएस वाला मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।
**: इसमें डीजल, कोक, कोयला, काठकोयला और अन्य ईंधन शामिल हैं।
टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई-ईंधन और बिजली के भार को दर्शाते हैं।
2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.13: एलपीजी की खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव

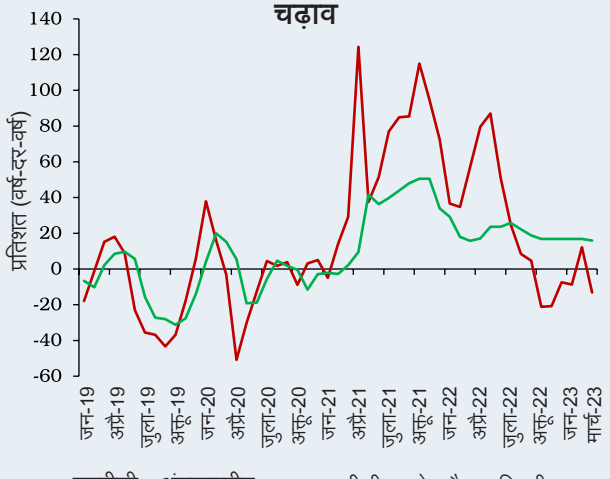

टिप्पणी : घरेलू गैर-सब्सिडी एलपीजी की कीमतें चार महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) की औसत कीमतें हैं।
स्रोत : ब्लूमबर्ग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)।

चार्ट II.3.14: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के चालक

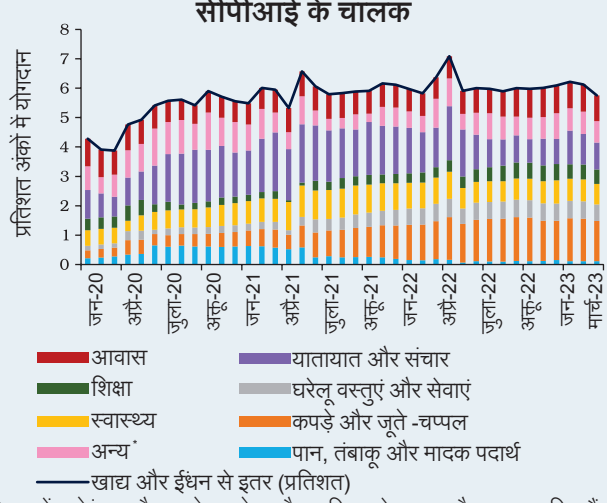

*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

होने की वजह से मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 11.8 प्रतिशत के अपने उस वर्ष के शिखर से कम हो गई।

खाद्यान्न और इंधन छोड़कर मुद्रास्फीति

II.3.24 अस्थिर खाद्य और ईंधन मदों को छोड़कर मुद्रास्फीति, यानी, कोर मुद्रास्फीति, 2022-23 में औसतन 6.1 प्रतिशत तक बढ़ गई - अप्रैल 2022 में 7.1 प्रतिशत के शिखर के साथ 2021-22 की तुलना में मामूली वृद्धि (चार्ट II.3.14) [परिशिष्ट सारणी 4]। मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद मई 2022 से कोर मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत पर बनी हुई है, इसके बाद कई राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की गई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक-आधार दबाव देखा गया।

II.3.25 2022-23 की पहली तिमाही में प्रमुख घटकों में तेज उछाल के बाद परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट II.3.15)। परिवहन और संचार के भीतर, व्यक्तिगत परिवहन वाहनों की कीमतों में वृद्धि हुई, जो मांग में सुधार के साथ-साथ इनपुट लागत के दबाव के प्रभाव-अंतरण को दर्शाती है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद बस और टैक्सी किराए में संशोधन के साथ परिवहन किराए में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही क्योंकि कोविड-19 मामलों में कमी और चिकित्सा आपूर्ति के सामान्य होने के साथ महामारी से प्रेरित मांग धीरे-धीरे कम हो गई। खुदरा कीमतों पर

चार्ट II.3.15: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान

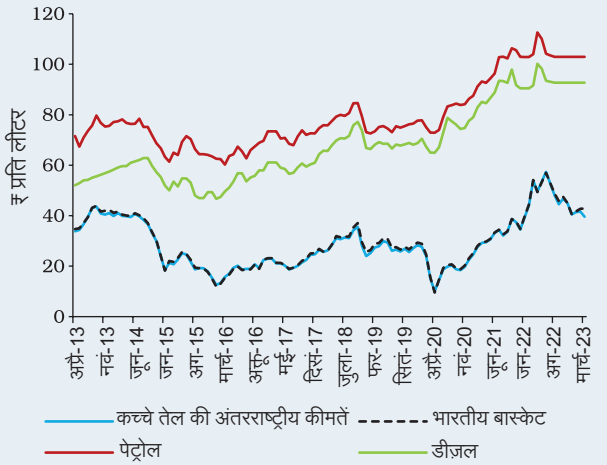

टिप्पणी : कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।
स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिंक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

इनपुट लागत के प्रभाव अंतरण के कारण मूल कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि देखी गई क्योंकि 2022-23 के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं ने 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की (चार्ट II.3.16)।

II.3.26 आवास मुद्रास्फीति 2022-23 में लगभग 4.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो हाइब्रिड कार्य संस्कृति के कारण किराये की मांग में कमी को दर्शाता है। 2022-23 में निवल आवास, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति औसतन 6.6 प्रतिशत रही, जिसका स्तर एक वर्ष पहले जैसा ही था।

II.3.27 कपड़ों और जूते में मुद्रास्फीति एक प्रमुख दबाव बिंदु बनी रही, जो 2022-23 में औसतन 9.5 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति में तेज़ वृद्धि मुख्य रूप से कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि (जैसा कि कपास ए सूचकांक द्वारा मापा गया है) के कारण लागत दबाव और मौसम में गड़बड़ी और कीट हमलों के कारण प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में फसल की उपज में गिरावट के कारण कम घरेलू कपास की आवक के प्रभाव अंतरण को दर्शाती है।

चार्ट II.3.16: मुद्रास्फीति : कोर वस्तुएं

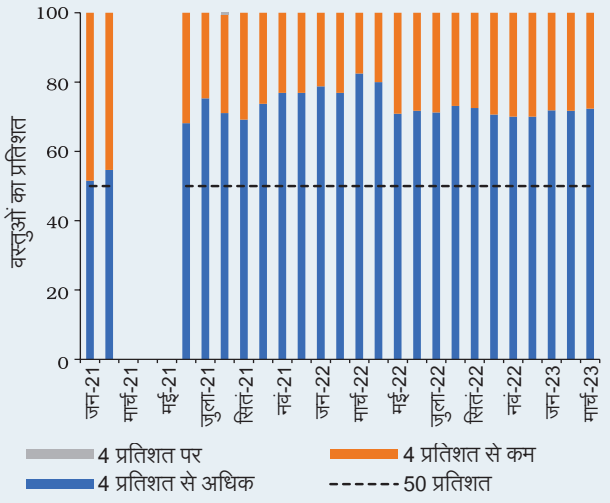

नोट: एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.28 क्षेत्रवार परिप्रेक्ष्य से, 2022-23 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति औसतन 6.1 प्रतिशत तक बढ़ी रही, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि है। 2022-23 के दौरान खेतिहर मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति, क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत पर औसतन अधिक थी, जो खाद्य, ईंधन और वस्त्रों में उच्च मुद्रास्फीति से प्रेरित थी।

II.3.29 वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, जो मई 2022 में 16.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। इस वृद्धि ने यूक्रेन में युद्ध के बाद कच्चे तेल और अन्य पण्य कीमतों में वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। वर्ष के उत्तरार्द्ध में वैश्विक पण्य कीमतों, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य और धातुओं में गिरावट से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में लगातार कमी आई, जो मई 2022 के अपने शिखर से मार्च 2023 में 1.3 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति से निचले स्तर पर आ गई। अक्तूबर-मार्च 2022-23 में सभी तीन प्रमुख समूहों - प्राथमिक वस्तुओं (डब्ल्यूपीआई समूह में 22.6 प्रतिशत का भारांक), ईंधन और पॉवर (13.2 प्रतिशत का भारांक) और विनिर्मित उत्पादों (64.2 प्रतिशत का भारांक) में कीमतों के दबाव में कमी के कारण तेज गिरावट आई। यद्यपि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति में समूह की संरचना के साथ-साथ भारांक पैटर्न में अंतर को दर्शाते हुए छिटपुट रूप से विचलन होता है, वे एक दीर्घकालिक संबंध दर्शाते हैं।[11] नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान डब्ल्यूपीआई प्राथमिक वस्तुओं में से मुख्य रूप से फलों और सब्जियों की कीमतों में तेज मौसमी गिरावट से प्रेरित होकर, खाद्य मुद्रास्फीति में अच्छी-ख़ासी गिरावट आई।

[11] आरबीआई (2021), " लॉकडाउन के बाद सीपीआई-डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति: दीर्घकालिक सह-एकीकरण और अल्पकालिक त्रुटि सुधार", बॉक्स II.2, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अक्तूबर 2021, पृष्ठ 30।

हालांकि, मसाले एक नए दबाव बिंदु के रूप में उभरे और पूरे वर्ष इनमें दहाई अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई। 2022-23 में ईंधन और पॉवर द्वारा दर्ज की गई लगातार उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, वैश्विक ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में कमी के अनुरूप, जून 2022 के स्तर से धीरे-धीरे कमी आई। उच्च वैश्विक पण्य कीमतों से इनपुट लागत दबाव में व्यापक वृद्धि के साथ, विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति अप्रैल-मई 2022 के दौरान दहाई अंकों में रही, जो मुख्य रूप से खाद्येतर-निर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति से प्रेरित थी। हालांकि, इसके बाद कम होते लागत दबाव के साथ मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आई। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति, 2021-22 की पहली छमाही में 8.6 प्रतिशत की तुलना में, 2022-23 की पहली छमाही में बढ़कर 11.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। अक्तूबर 2022 के बाद से डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ, जीडीपी डिफ्लेटर 2022-23 की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2022-23 की दूसरी तिमाही में यह 10.3 प्रतिशत था। कुल मिलाकर 2022-23 में जीडीपी अवस्फीति मुद्रास्फीति घटकर 8.3 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 8.5 प्रतिशत थी।

II.3.30 वर्ष 2022-23 में *खरीफ* और *रबी* फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, *खरीफ* फसलों के लिए 4.4-8.9 प्रतिशत और *रबी फसलों* के लिए 2.0-9.1 प्रतिशत की सीमा थी। *खरीफ* फसलों में सोयाबीन (पीले) में अधिकतम एमएसपी वृद्धि देखी गई, जबकि *रबी* फसलों में मसूर *(लेंटिल)* के लिए यह वृद्धि सबसे अधिक थी।

II.3.31 खेतिहर और कृषितर मजदूरों के लिए 2022-23 के दौरान वेतन वृद्धि कम रही और यह औसतन क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत थी। फिर भी, खेतिहर और कृषितर मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि की गति में वृद्धि हुई, जो मार्च 2023 में सामान्य होने से पहले जनवरी 2023 और नवंबर 2022 में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत के वार्षिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

6. निष्कर्ष

II.3.32 यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न सामान्य आघात - खाद्य, ऊर्जा और अन्य पण्य की उच्च कीमतें- और मुद्रास्फीति के बहु-दशकीय उच्च स्तर तक वैश्वीकरण ने भारत में निरंतर ऊर्ध्वगामी मूल्य दबाव डाले, जिससे मुद्रास्फीति लगातार दस महीनों (जनवरी - अक्तूबर 2022) में 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से अधिक रही। खाद्य कीमतों में मौसमी कमी के कारण नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान मुद्रास्फीति में थोड़ी बहुत कमी आई, पर जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान फिर से बढ़ गई और मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नियंत्रण और वित्तीय बाजारों में संबंधित अस्थिरता के कारण, आयातित मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न हुए। उच्च औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों, परिवहन लागत, और वैश्विक रसद व आपूर्ति शृंखला बाधाओं से इनपुट लागत दबावों ने मूल मुद्रास्फीति पर असर डाला। पहली छमाही में गर्मी की असमय शुरुआत, ग्रीष्म लहरों और बेमौसम बारिश से खाद्य कीमतों पर ऊर्ध्वगामी दबाव - वर्ष की दूसरी छमाही में कम हो गए क्योंकि अच्छी *खरीफ* पैदावार और मौसमी नई फसल की आवक के साथ-साथ वैश्विक खाद्य कीमतों में कुछ कमी आई। सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति पक्ष के मध्यक्षेपों ने भी कीमत दबाव को नियंत्रित करने में मदद की। मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के चक्र की समय पर शुरुआत करते हुए, मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि ने मांग के दबाव को कम करने, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कम करने और लगातार आपूर्ति के आघातों के अप्रत्यक्ष प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद की। लेकिन समय पर मौद्रिक और राजकोषीय कार्रवाइयों के लिए मुद्रास्फीति के 90 आधार अंक अधिक होने का अनुमान है। भू-राजनीतिक गतिशीलता और संभावित मौसम की गड़बड़ी ने भारत में मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

II.4 मुद्रा एवं ऋण

II.4.1 मौद्रिक और ऋण की स्थिति, मौद्रिक नीति के रुख और वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति के साथ तालमेल में विकसित हुई। आरक्षित मुद्रा (आरएम), पहले दौर के प्रभावों के लिए समायोजित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)[12] में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान व्यापक मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$) में वृद्धि मोटे तौर पर इसके सबसे बड़े घटक - कुल जमा के अनुरुप रही - आंशिक रूप से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि और अधिशेष चलनिधि की क्रमिक निकासी के बाद उच्च जमा दरों के फलस्वरूप, जिसका विवरण अध्याय III में दिया गया है। हालांकि, जमा वृद्धि ऋण की मजबूत वृद्धि के अनुरूप नहीं रही और बैंकों ने आस्ति विस्तार के वित्तपोषण के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) बाजार का सहारा लिया। वर्ष के दौरान जनता के साथ मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) में कमी आई, जो 2013-14 के बाद पहली बार कुल जमा की वृद्धि से नीचे गिर गई। यह आंशिक रूप से एक ऐसे वातावरण में मुद्रा रखने की बढ़ती अवसर लागत के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें जमा दरों में वृद्धि के साथ-साथ लेनदेन करने के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों को अपनाना भी शामिल है। उपभोक्ता आशावाद की वापसी और व्यावसायिक भावनाओं में सुधार को दर्शाते हुए, मुद्रा की गति, जो गिर गयी थी, पिछले दशक में व्यापक रूप से स्थिर प्रवृत्ति के अनुरूप, महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच गयी।

II.4.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2, आरएम में अंतर्निहित गतिविधियों की गतिशीलता और इस प्रकार, रिज़र्व बैंक की तुलन पत्र में बदलाव की चर्चा करता है। उप-खंड 3 बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देनदारियों में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालते हुए, इसके घटकों और स्रोतों के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति में विकास की जांच करता है। बैंक ऋण के आधार को उप-खंड 4 में शामिल किया गया है, इसके बाद निष्कर्ष टिप्पणियां दी गयी हैं।

2. *आरक्षित मुद्रा* [13]

II.4.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) केंद्रीय बैंक की तुलन पत्र में मौद्रिक देनदारियों के स्टॉक को दर्शाता है। 24 मार्च 2023 तक, आरएम, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र आकार के 68 प्रतिशत से अधिक रहा (चार्ट II.4.1)। शेष[14] में बड़े पैमाने पर जोखिम बफर और पुनर्मूल्यांकन खाते [निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा बनाते हुए)], साथ ही रिज़र्व बैंक के पास रिवर्स रेपो/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जमा चलनिधि अधिशेष, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा

चार्ट II.4.1: रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के घटक (देनदारियां)

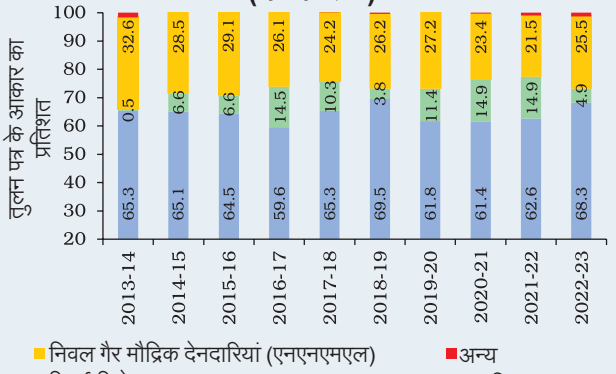

एनएनएमएल: निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों में आर्थिक पूंजी (जैसे पूंजी, भंडार, आकस्मिक निधि, आस्ति विकास निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता), आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाता और आईएमएफ कोटा सदस्यता और अन्य भुगतान से अन्य आस्तियों को घटाकर शामिल किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

[12] 21 मई, 2022 से सीआरआर 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

[13] उप-खंड 2 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम शुक्रवार (केवल 2022-23 के आंकड़े 24 मार्च, 2023 से संबंधित हैं) पर आधारित हैं।

[14] आईएमएफ के मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी मैनुअल और संकलन गाइड का पालन करते हुए, क्रॉस-कंट्री प्रथाओं के साथ समन्वय में आरएम की गणना में उनकी गणना नहीं की जाती है।

'रेनी डे'[15] में संभावित उपयोग के लिए देश की बचत के रूप में बनाए रखा जाता है।

II.4.4 वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित तनाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के हिस्से के रूप में कई लक्षित और प्रणाली-स्तरीय चलनिधि उपायों का उपयोग किया था, जिससे इसके तुलन पत्र आकार में स्थिर विस्तार हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार 2019-20 के 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 28.6 प्रतिशत हो गया, जो 2021-22 में 26.7 प्रतिशत और 2022-23 में 22.5 प्रतिशत तक कम हो गया (चार्ट II.4.2ए)। हालांकि, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का विस्तार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। इसी अवधि के दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आरक्षित मुद्रा भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्थिर रहा क्योंकि चलनिधि उपायों को सावधानीपूर्वक बनाया गया था और इन-बिल्ट टर्मिनल तिथियों के साथ लक्षित किया गया था, जिससे कोविड के बाद की गैर पारंपरिक नीतियों से बाहर निकलने की चुनौती कम हो गई (चार्ट II.4.2बी)।

II.4.5 घटक पक्ष (देनदारियों) पर, आरएम में प्रचलन में मुद्रा, रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमा और रिज़र्व बैंक में अन्य जमा शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, आरएम संवृद्धि एक साल पहले के 12.3 प्रतिशत तथा अपने दशकीय (2013-22) औसत 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.0 प्रतिशत हो गई, जो इंगित करता है कि 2022-23 के दौरान अनुभव की गई उच्च औसत मुद्रास्फीति के पीछे अत्यधिक आधार मुद्रा संवृद्धि एक प्रेरक कारक नहीं थी। सीआरआर में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित, आरएम में एक साल पहले के 7.3 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 7.5 प्रतिशत की संवृद्धि हुई, जो दो वर्षों की अवधि में कोविड-19 प्रेरित अधिशेष चलनिधि के क्रमिक और नपीतुली निकासी को दर्शाता है[16] (चार्ट II.4.3 और परिशिष्ट सारणी 4)।

चार्ट II.4.2: केंद्रीय बैंक का तुलनपत्र तथा आरक्षित मुद्रा (बहुराष्ट्रीय)

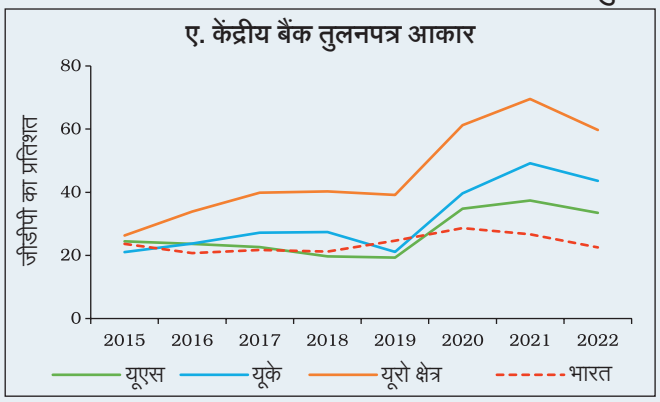

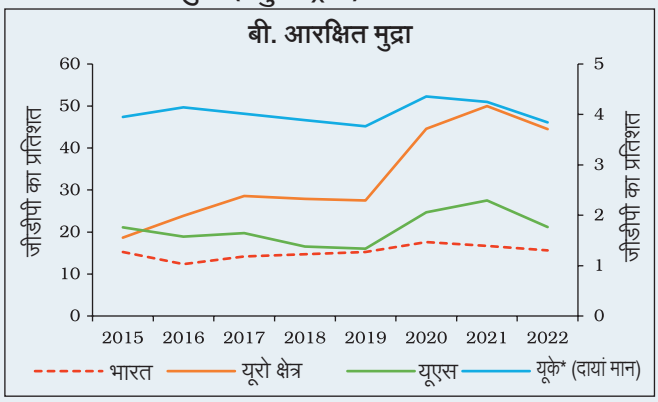

* यूके के लिए मौद्रिक आधार स्टर्लिंग नोट और सिक्के हैं जो इंग्लैंड के बैंक के बाहर परिचालित हैं और बैंक की परिचालन जमा होता है।

टिप्पणी: 1 वर्ष 2022-23 के लिए भारत का नॉमिनल जीडीपी डेटा दूसरा अग्रिम अनुमान हैं।

2. भारत के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर हैं (अर्थात, 2022, 2022-23 से संदर्भित है), जबकि अन्य देशों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के अनुसार हैं।

स्रोत: एफआरइडी (सेंट लुइस फेड), सीइआइसी जीओआइ, तथा आरबीआई स्टाफ की गणना

[15] भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, अगस्त 2019 (अध्यक्ष: डॉ बिमल जालान)।

[16] सीआरआर को 3.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 मार्च 2021 से प्रभावी 3.5 प्रतिशत; 22 मई 2021 से 4.0 प्रतिशत; और 21 मई 2022 से 4.5 प्रतिशत तक कर दिया गया।

चार्ट II.4.3: आरक्षित मुद्रा- घटक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)

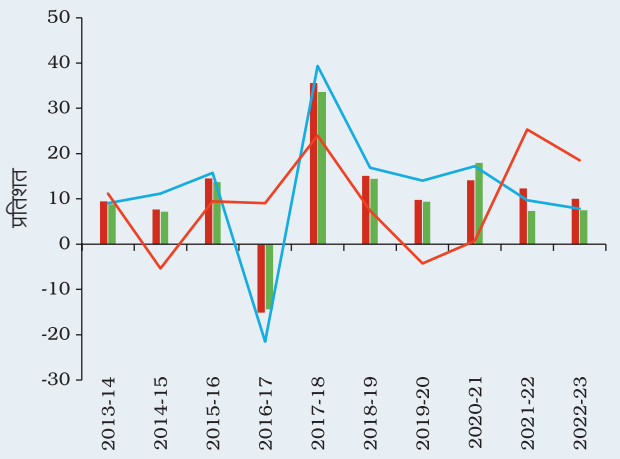

स्रोत: आरबीआई

II.4.6 वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित मुद्रा के घटकों में, प्रमुख घटक, संचलनगत मुद्रा (सीआईसी), जिसकी हिस्सेदारी 78.4 प्रतिशत है, में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो आरक्षित मुद्रा में वृद्धि की गति की तुलना में कम है। सीआईसी-जीडीपी अनुपात में कमी के बीच, रिज़र्व बैंक की विभिन्न पहलों जैसे कि भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के प्रचालन और वर्ष के दौरान केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरूआत के माध्यम से, जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के अध्याय VI, VIII और IX में शामिल किया गया है, महामारी के बाद की अवधि में नए उपयोगकर्ताओं की तेजी से डिजिटल ऑनबोर्डिंग के साथ भारत में डिजिटल भुगतान काफी बढ़ गया (चार्ट II.4.4)।

II.4.7 यद्यपि भारत में मुद्रा-जीडीपी अनुपात कम हो रहा है, यह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इस स्थिति को विशेष रूप से नकदी लेनदेन के विकल्प के रूप में डिजिटल भुगतान में हासिल घातीय वृद्धि की परिस्थिति में व्यापक रूप से मुद्रा मांग विरोधाभास के रूप में जाना जाता है (चार्ट II.4.5)। चूंकि आम तौर पर यह उम्मीद किया जाता है कि नकदी और डिजिटल तरीके एक-दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए दोनों में एक साथ वृद्धि विरोधाभाषी लगती है (बॉक्स II.4.1)।

II.4.8 सीआईसी की मांग एक महीने के दौरान सामान्यत: अनुमानित इंट्रा-महीने पैटर्न पर चलती है - परिवारों द्वारा लेनदेन के कारण पहले पखवाड़े के दौरान विस्तार के बाद परिवारों से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के लौटकर वापस जाने के कारण दूसरे पखवाड़े में संकुचन हुआ। इसमें त्रैमासिक पैटर्न भी है जो पहली

चार्ट II.4.4 : संचलन में मुद्रा और डिजिटल भुगतान

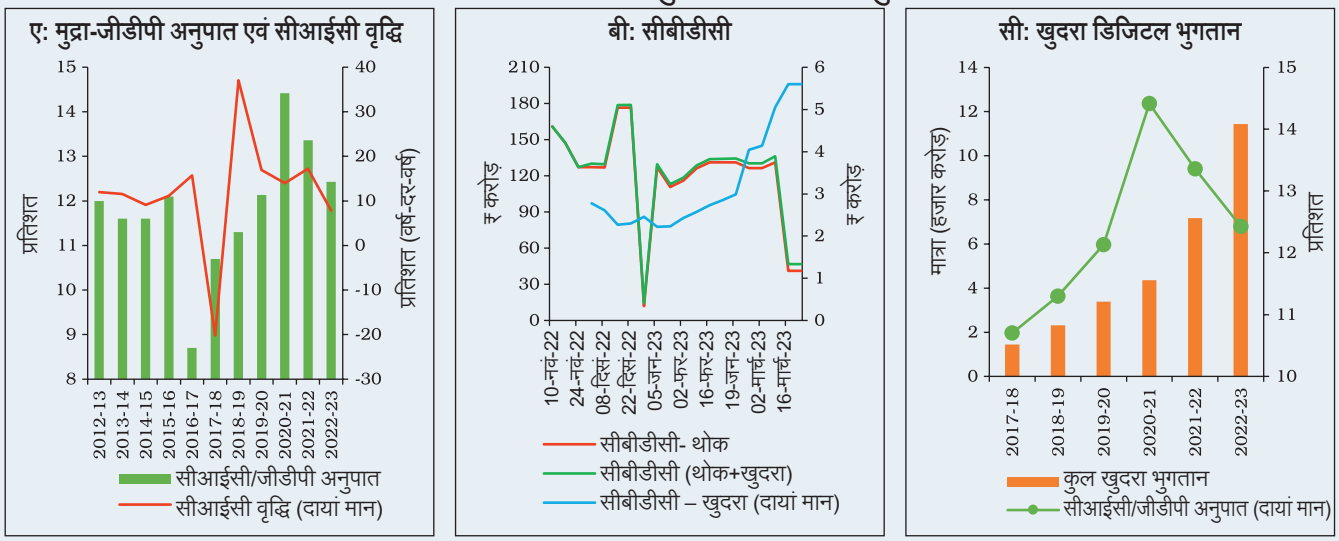

नोट: 2022-23 के लिए भारत के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।
स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार।

चार्ट II.4.5: संचलनगत मुद्रा तथा खुदरा डिजिटल लेनदेन (अंतर-देशीय)

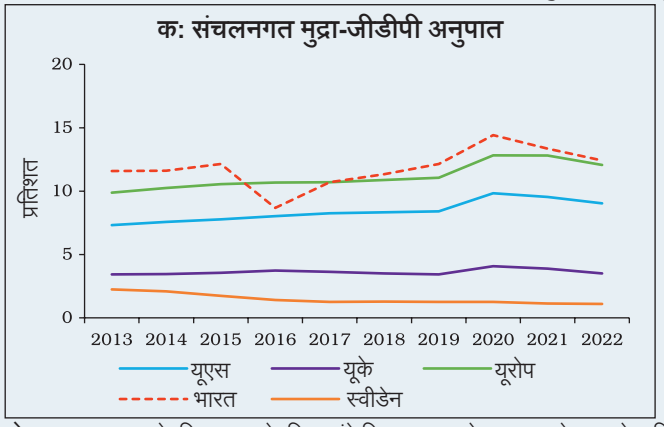

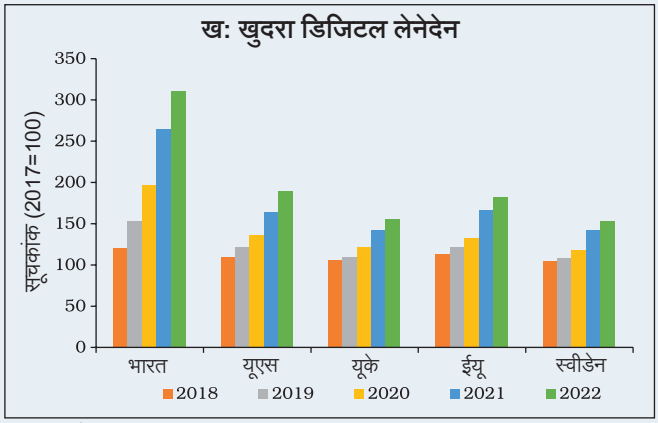

नोट: 1. 2022-23 के लिए भारत के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद डेटा दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।
2. भारत के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर हैं (यानी, 2022, 2022-23 को संदर्भित करता है), जबकि अन्य देशों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के अनुसार हैं।
स्रोत: सीईआईसी, स्टेटिस्टा, आरबीआई स्टाफ अनुमान और भारत सरकार।

तिमाही में *रबी* की खरीद और *खरीफ़* की बुवाई से जुड़ी मौसमी तेजी से संचालित होने के बाद विनिर्माण और कृषि जैसे नकद-प्रधान क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में मौसमी मंदी के कारण दूसरी तिमाही में सीआईसी में संकुचन के रूप में दिखता है। तीसरी तिमाही में सीआईसी का विस्तार दिखता है, जो त्योहारों और *खरीफ़* की फसल के लिए मुद्रा की बढ़ती माँग को दर्शाता है। चौथी तिमाही में सीआईसी में विस्तार *रबी* फसलों की कटाई, विभिन्न त्योहारों और शादी के मौसम को ट्रैक करता है। वर्ष

बॉक्स II.4.1
भारत में मुद्रा मांग विरोधाभास

लेनदेन करने के लिए मुद्रा और डिजिटल भुगतान तरीकों के बीच समझी गई प्रतिस्थापन क्षमता को देखते हुए किसी देश में उनकी समानांतर वृद्धि विरोधाभाषी लगती है, जिससे मुद्रा विरोधाभास (बेली, 2009) पैदा होता है। इसके अलावा, कोविड-19 ने इस विरोधाभास को तेज कर दिया है क्योंकि भुगतान के डिजिटल तरीकों में तेजी से माइग्रेशन के बावजूद बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण नकदी की मांग में वृद्धि हुई है (अर्दिज़ी और अन्य, 2020)। भारत में, जहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) द्वारा संचालित खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 50 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2016-17 से 2021-22 के दौरान) से वृद्धि हुई, वहीं सकल घरेलू उत्पाद के लिए संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) का अनुपात भी बढ़ा और 2020-21 में यह 14.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। हालांकि, यह घटना भारत के लिए नई या अनूठी नहीं है और 2007 से कई देशों के लिए देखी गई है। मुद्रा रखने की अवसर लागत में गिरावट जैसे कारकों को नकदी के लिए लगातार लगाव के लिए जिम्मेदार माना गया है, यानी, ब्याज दरें; अनिश्चितता के बीच एहतियाती होल्डिंग, एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की उपस्थिति और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), नकद और डिजिटल दोनों तरीकों को बढ़ावा देता है, क्योंकि डिजिटल रूप से लाभ के रूटिंग के बाद नकद निकासी होती है।

भारत में कोविड-19 के दौरान मुद्रा की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से एहतियाती थी क्योंकि सीआईसी में मजबूत वृद्धि उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की मांग से संचालित थी, जिसमें वर्ष 2010-16 के दौरान 82 प्रतिशत के औसत से वर्ष 2021-22 में कुल सीआईसी के 90 प्रतिशत तक की उछाल देखी गई। इसके अतिरिक्त कम मूल्यवर्ग के नोटों में गिरावट देखी गई जिसका आंशिक कारण छोटे मूल्य के भुगतानों का यूपीआई और मोबाइल वॉलेट द्वारा प्रतिस्थापित होना था जो कि उनके घटते टिकट आकार से सिद्ध होता है। लेनदेन संबंधी नकदी में कम मांग एटीएम से नकद निकासी के मामले में मूल्यों की तुलना में निकासी संख्या में तेज गिरावट से भी स्पष्ट थी जिससे निकासी आकारों में वृद्धि हुई। इन कारकों को देखते हुए, वर्तमान में हो रहे डिजिटल रूपांतरण के प्रभाव के आकलन में केवल सीआईसी-जीडीपी अनुपात के रुझान पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक प्रतितथ्यात्मक आकलन दर्शाता है कि यदि आधार (जीडीपी) में महामारी-जनित गिरावट और मुद्रा स्तरों में अनिश्चितता-जनित उछाल नहीं होती तो वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत के वास्तविक अनुपात की जगह सीआईसी-जीडीपी अनुपात 12 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत होता।[17]

(जारी)

[17] मुद्रा उपयोग पर महामारी के प्रभाव आकलन के लिए, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सीआईसी-जीडीपी अनुपात के प्रतितथ्यों की गणना वर्ष 2011-12 से 2019-20 के सीआईसी के सीएजीआर और जीडीपी आँकड़ों का प्रयोग करके की गई है।

वर्ष 2009 की दूसरी तिमाही से वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही तक की नमूना अवधि को कवर करते हुए ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल का उपयोग करके दीर्घकालीन मुद्रा मांग प्रकार्य (फ़ंक्शन) का प्रायोगिक विश्लेषण कुछ रोचक परिप्रेक्ष्य देता है। आर्थिक अनिश्चितता के लिए बेकर व अन्य. (2016) से तथा अन्य चरों के लिए रिज़र्व बैंक से विश्लेषण हेतु आंकड़े लिए गए हैं। ब्याज दरों को छोड़कर प्रायोगिक विश्लेषण के लिए नियोजित सभी चर प्रासंगिक चरों हेतु मौसमी समायोजन के साथ प्राकृतिक लघुगणक में परिवर्तित किए गए हैं। विमुद्रीकरण (ति4: 2016, ति1: 2017) और प्रथम कोविड-प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (ति 2: 2020) हेतु सामायोजन (कंट्रोल) के लिए उपयुक्त डमी जोड़े गए। वर्धित डिकी-फुलर (एडीएफ) परीक्षण के अनुसार, सभी चर अपने स्तरों पर अथवा पहले अंतर पर स्थिर हैं।

बेसलाइन मॉडल यह दर्शाता है कि नामिक आय (एलवाईएन) नकद मांग (एलसीआईसी) [धनात्मक संबंध] का प्रमुख वाहक है, जबकि प्रमुख बैंकों की जमा ब्याज दरों (आईएनटी) द्वारा दर्शाई गई अल्पकालिक ब्याज दरों का मुद्रा उपयोग के साथ ऋणात्मक संबंध है (सारणी 1)। आगे, डिजिटल मोड तक पहुँच जो डिजिटल भुगतान मूल्य (एलडीआईजीवीएएल) द्वारा दर्शाई गई है, मुद्रा उपयोग को कम करती है (मॉडल 2 और 3)। यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव, महत्त्वपूर्ण है, पर आय प्रभाव से कम है जो यह दर्शाता है कि डिजिटल लेनदेन मुद्रा मांग पर आय के प्रभाव को ऑफसेट कर सकता है और समय के साथ मुद्रा एवं जमा अनुपात को कम कर सकता है। आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक (एलईपीयू) [धनात्मक] द्वारा दर्ज मुद्रा उपयोग पर एहतियाती प्रभाव अनिश्चित अवधियों में नकदी के प्रति झुकाव दर्शाता है।

आकलन दर्शाता है कि एहतियात और मूल्य संचय (स्टोर-ऑफ-वैल्यू) के उद्देश्य को कोविड-19 के दौरान सीआईसी वृद्धि में अचानक उछाल का कारण बताया जा सकता है, जबकि डिजिटल मोड उत्तरोत्तर नकदी के लेन-देन के उपयोग का स्थान लेता गया है। हालिया आँकड़े महामारी में नकदी के लिए एहतियाती मांग में बदलाव को दर्शाते हैं। 24 मार्च 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए, सीआईसी में 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, अर्थात् अगस्त 2021 (अप्रैल 2022 को छोड़कर) से 86 सप्ताह के लिए एकल-अंक की वृद्धि दर्ज की गई और इसका समग्र औसत 8.5 प्रतिशत रहा। साथ ही, कोविड के उपरांत, डिजिटल भुगतान के माध्यम मजबूत वृद्धि गति बनाए हुए हैं।

सारणी 1: मुद्रा मॉडलिंग रिग्रेशन के दीर्घकालिक गुणांक

[आश्रित चर: एलसीआईसी (संचलन में मुद्रा का प्राकृतिक लॉग)]

	मॉडल 1 (बेसलाइन)	**मॉडल 2**	**मॉडल 3**
1	2	3	4
मॉडल का प्रकार	*एआरडीएल (3,1,0)*	*एआरडीएल (3,3,0,2)*	*एआरडीएल (3,2,0,2,1)*
नामिक आय (एलवाईएन)	0.88***	1.19***	1.26***
	(0.04)	(0.20)	(0.18)
ब्याज दर (आईएनटी)	-0.06***	-0.07***	-0.07***
	(0.01)	(0.01)	(0.01)
डिजिटल भुगतान मूल्य (एलडीआईजीवीएएल)		-0.30**	-0.32**
		(0.16)	(0.15)
आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू)			0.06*
			(0.00)
अवरोध (इंटरसेप्ट)	1.53**	1.96**	0.83
	(0.81)	(0.84)	(0.80)
त्रुटि सुधार	-0.24***	-0.24***	-0.27***
	(0.01)	(0.01)	(0.01)
बाउंड्स टेस्ट: एफ सांख्यिकी	48.52	33.89	33.73
मॉडल परीक्षण			
समायोजित आर-स्क्वायर्ड	0.99	0.99	0.99
अकाइक सूचना मानदंड (एआईसी)	-4.81	-5.06	-5.08
श्वार्ट्ज सूचना मानदंड (एसआईसी)	-4.46	-4.52	-4.50
डर्बिन-वाटसन स्टैट	2.18	1.84	2.04

*** : 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। ** : 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
* : 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन।

संदर्भ:

1. आर्डिज़्जी, जी., ए. नोबिली और जी. रोक्को (2020), 'ए गेम चेंजर इन पेमेंट हैबिट्स: एविडेंस फ्रॉम डेली डेटा ड्यूरिंग ए पैनडेमिक', बैंक ऑफ इटली, ऑकेज़नल पेपर नं. 591।

2. बेली, ए. (2009), 'बैंकनोट्स इन सर्कुलेशन-स्टिल राइजिंग। व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द फ़्यूचर ऑफ़ कैश?', स्पीच एट द *बैंकनोट कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन डीसी,* वॉल्यूम. 6 ।

3. बेकर, एस.आर., ब्लूम, एन., और डेविस, एस.जे. (2016), 'मेज़रिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेन्टी', *द क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स*, 131(4), 1593-1636।

2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान सीआईसी में घट-बढ़ छह राज्यों में विधानसभा चुनावों से भी प्रभावित हुए (चार्ट II.4.6)।

II.4.9 आरएम का अन्य घटक, रिज़र्व बैंक के पास बैंकरों की जमाराशियां (शेयर: 20.1 प्रतिशत) पिछले वर्ष की इसी अवधि के 25.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में 18.5 प्रतिशत बढ़ी, क्योंकि पिछले वर्ष के 100 बीपीएस की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष सीआरआर को 50 बीपीएस ही बढ़ाया गया (चार्ट II.4.3)।

II.4.10 स्रोत पक्ष (आस्ति) में, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल देशी आस्ति (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए)

चार्ट II.4.6: संचलन में मुद्रा में तिमाही परिवर्तन

स्रोत: आरबीआई।

शामिल हैं। एनडीए में बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक व्यापारियों) को निवल रिज़र्व बैंक क्रेडिट शामिल है, जबकि एनएफए के घटक सोना और विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) हैं।[18] 2022-23 के दौरान, आरएम का विस्तार मुख्य रूप से एनएफए द्वारा संचालित था, जिसने लगभग 67 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में घट-बढ़ देखा गया; जबकि एनडीए का योगदान बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र पर चलनिधि प्रबंधन परिचालन से उत्पन्न रिजर्व बैंक के शुद्ध दावों को दर्शाता है।[19] मूल्यांकन के लिए समायोजित, एनएफए ने वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की, जो विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप को दर्शाता है (चार्ट II.4.7)।

चार्ट II.4.7: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)

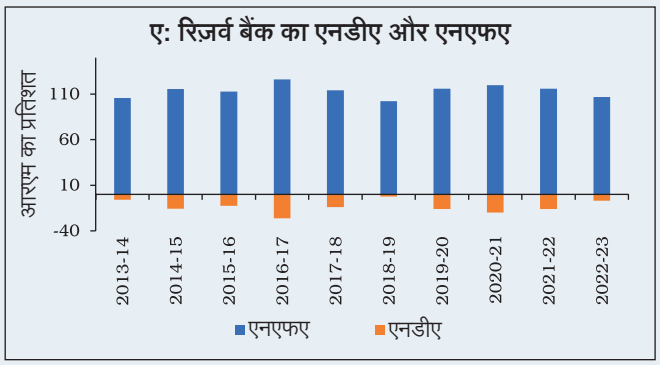

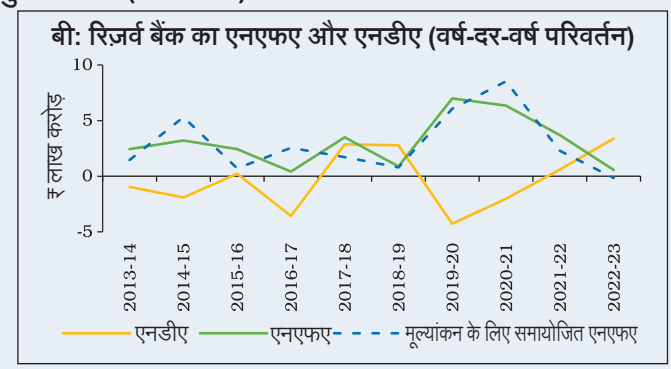

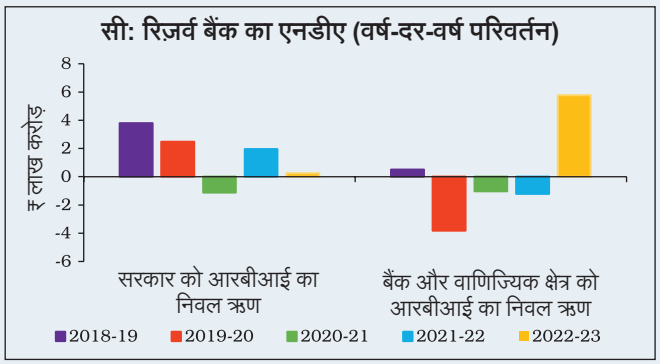

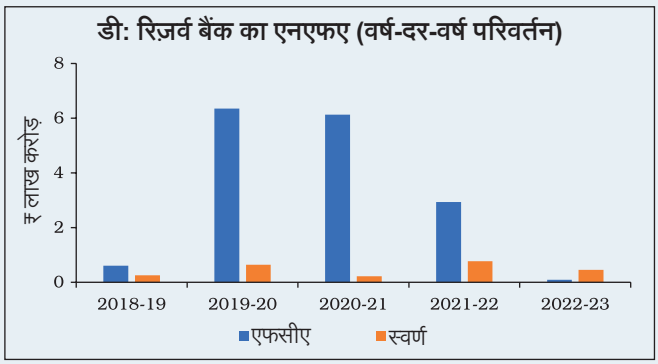

स्रोत: आरबीआई ।

[18] इसमें भारत सरकार (जीओआई) से अंतरित विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। भारत सरकार के पास एसडीआर होल्डिंग शेष और आईएमएफ़ में रिज़र्व ट्रांच पोज़िशन (आरटीपी) जो कि आईएफ़एम में भारत के कोटे का अंशदान विदेशी मुद्रा में दर्शाता है और यह रिजर्व बैंक की तुलन पत्र का भाग नहीं है।

[19] चलनिधि प्रबंधन परिचालन से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

3. मुद्रा आपूर्ति [20]

II. 4.11 वित्तपोषण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है और मांग के अनुरूप मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था के पहियों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आरक्षित मुद्रा इसमें मौद्रिक वित्त पोषण का आधार बनाता है जिस पर बैंकिंग चैनल के माध्यम से जमाराशियों को कई गुना किया जाता है और यह क्रेडिट निर्माण प्रक्रिया को सहारा प्रदान करता है। प्रायः मुद्रा आपूर्ति परोक्ष रूप में व्यापक मुद्रा (एम$_3$) है जिसमें मुख्य रूप से जनता के पास मुद्रा (सीडबल्यूपी) और घटक भाग (देयताएं) की संकलित जमाराशियां (एडी) शामिल होती हैं। आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में देखी जाने वाली मुद्रा आपूर्ति - एम$_3$ और नॉमिनल जीडीपी अनुपात - यह दर्शाती है कि भारत ने कोविड-19 जनित प्रोत्साहन को तेजी से सामान्यीकृत होते देखा है और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत यह अनुपात महामारी से पहले के स्थिर स्तर तक लौट आया है (चार्ट II. 4.8)।

II.4.12 महामारी से पहले मुद्रा आपूर्ति का मंद विस्तार वर्ष 2010-2017 के दौरान के अपने दीर्घकालिक मंदी में परिलक्षित

चार्ट II.4.8: एम$_3$ और जीडीपी अनुपात

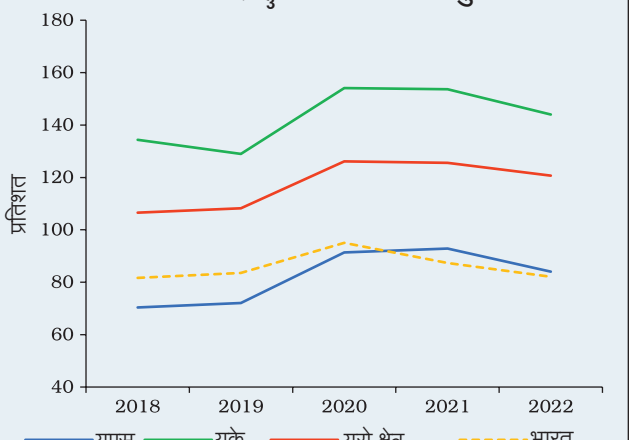

नोट: 1. वर्ष 2022-24 के लिए भारत का नॉमिनल जीडीपी आंकड़ा द्वितीय अग्रिम अनुमान है।
2. भारत के लिए आंकड़ा वित्तीय वर्ष के आधार पर है (अर्थात 2022 का अर्थ 2022-23 है), जबकि अन्य देशों के लिए यह कैलेंडर वर्ष के अनुसार है।
स्रोत: सीईआईसी, आरबीआई और भारत सरकार।

चार्ट II.4.9: मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) घटक – 5 वर्षीय वार्षिकीकृत संवृद्धि दर (मौसमी रूप से समायोजित)

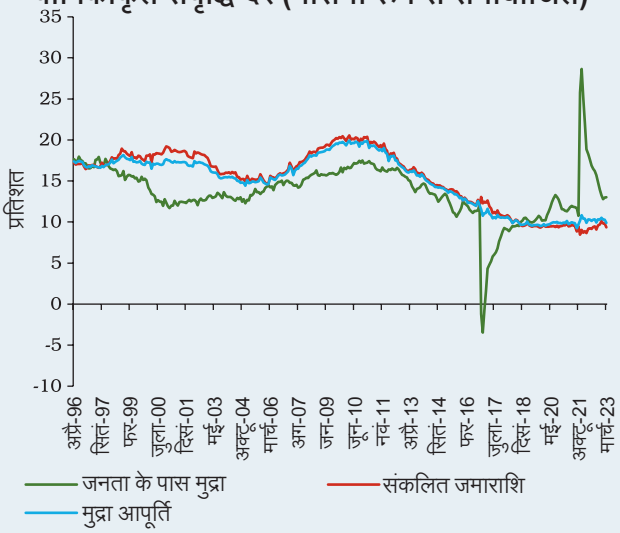

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना।

होता है, जिसका वाहक इसका प्रमुख घटक -संकलित जमाराशि है – जिसने मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक बढ़ोतरी संबंधी जोखिम की स्थिति के बिना महामारी जनित प्रोत्साहनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान किया (चार्ट II.4.9)।

II.4.13 इस वर्ष के दौरान जमा राशि की संवृद्धि, जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) से आगे निकल गई और यह वर्ष 2013-14 (विमुद्रीकरण वर्ष 2016-17 को छोड़कर) से चले आ रहे रुख में एक बदलाव है। इस वर्ष के दौरान, 24 मार्च 2023 के अनुसार व्यापक मुद्रा में 9.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 8.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से सावधि जमा[21] द्वारा संचालित थी, यह चलनिधि की क्रमिक निकासी के रुख के साथ नीतिगत दर में 250 बीपीएस की संचयी वृद्धि के कारण जमा ब्याज दरों में हुई वृद्धि से आंशिक रूप से समर्थित थी (चार्ट II. 4.10)।

II.4.14 वर्ष 2022-23 में स्रोत पक्ष (आस्तियों) से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण के साथ सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण ने एम$_3$ में विस्तार में भूमिका निभाई। पहला जो, एम$_3$

[20] उप-खंड 3 और 4 में, वित्तीय वर्ष/ तिमाही / माह के अंत से संबंधित संवृद्धि और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष / तिमाही / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।

[21] हमेशा की तरह, मांग जमा अस्थिर रही, जो काफी हद तक जनता के पास मुद्रा में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है।

चार्ट II.4.10: मुद्रा आपूर्ति एवं एससीबी सावधि जमा-राशियाँ

ए : मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) घटक - वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

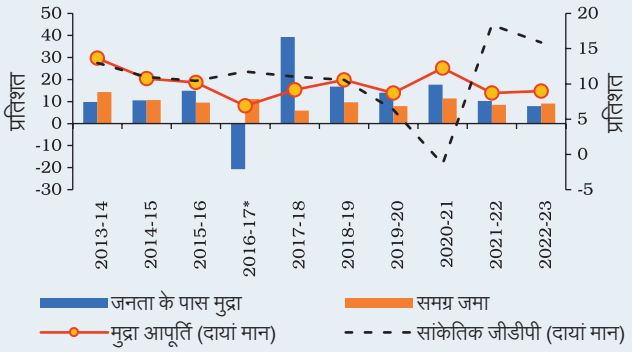

बी : एससीबी की सावधि जमा में वृद्धि (वर्ष- दर- वर्ष) और ब्याज दर

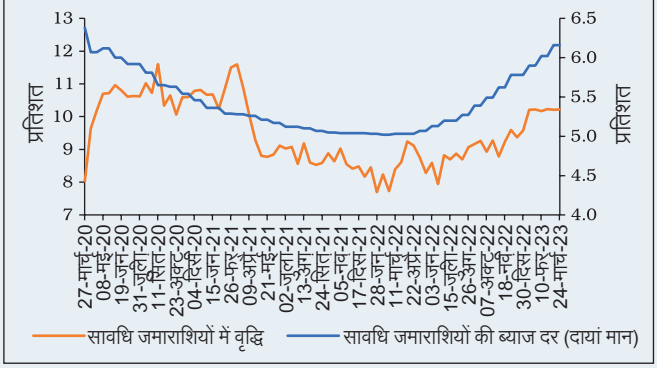

*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।
टिप्पणी: 1. 2022-23 के लिए भारत के सांकेतिक जीडीपी डेटा दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।
2. एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा के लिए, सावधि जमा ब्याज दरें, भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: आरबीआई।

का सबसे बड़ा घटक है, वर्ष 2022-23 के दौरान 14.4 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी, जो क्रेडिट निर्माण के लिए मुद्रा के सक्रिय उपयोग को दर्शाती है। 08 अप्रैल 2022 से परिपक्वता (एचटीएम) श्रेणी के तहत प्रतिभूतियों (एसएलआर प्रतिभूतियों सहित) को रखने की सीमा को एनडीटीएल के 22.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 23.0 प्रतिशत[23] करने के बाद से और ऋण वृद्धि में अक्टूबर 2022 के 17.8 प्रतिशत के शिखर से गिरावट के कारण भी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों[22] में उच्च निवेश के बीच, 2022-23 में सरकार का निवल बैंक ऋण 11.5 प्रतिशत (एक साल पहले 8.2 प्रतिशत) बढ़ गया। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी संपत्ति में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जो वैश्विक प्रभाव-विस्तार और विदेशी मुद्रा बाजार में संबंधित अस्थिरता के बीच वाणिज्यिक बैंकों के रुख को दर्शाती है (चार्ट II.4.11 और सारणी II.4.1)।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.4.15 मुद्रा और मुद्रा गुणक की गति का रुख, अक्सर आघातों के लिए आर्थिक एजेंटों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ नीतिगत

चार्ट II.4.11: मुद्रा आपूर्ति स्रोत-वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

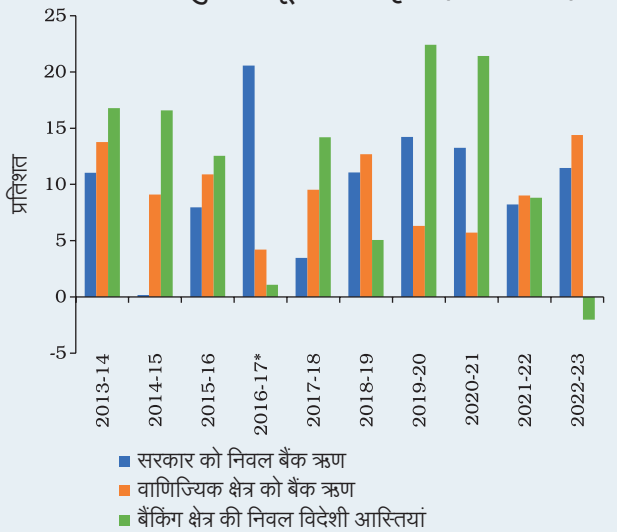

*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।
स्रोत: आरबीआई।

[22] सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती है और यह चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी है।

[23] 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर 31 मार्च, 2025 तक चरणबद्ध तरीके से एचटीएम की सीमा 23.0 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

सारणी II.4.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	24 मार्च 2023 को बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2022-23 (24 मार्च, 2023 तक)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	43,13,542	14.2	12.3	10.0
II. मुद्रा आपूर्ति (एम $_3$)	2,23,33,227	12.3	8.7	9.0
III. एम $_3$ के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	32,78,334	17.7	10.2	7.9
III.2। समग्र जमाराशियां	1,89,89,563	11.3	8.4	9.1
IV. एम $_3$ के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	69,16,058	13.2	8.2	11.5
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	1,44,23,483	5.7	9.0	14.4
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	4,86,22,73	21.4	8.8	-2.0
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम $_3$	2,21,79,106	12.6	8.9	8.9
VI. मुद्रा गुणक*	5.2	4.8	3.8	4.7

*: कॉलम 3, 4 और 5 के आंकड़े वृद्धिशील मुद्रा गुणक को दर्शाते हैं।
नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई।

परिवर्तनों के प्रभाव को भी दर्शाता है। भारत में, मुद्रा लेन-देन की गति, यानी सांकेतिक जीडीपी को व्यापक मुद्रा से विभाजित करने पर प्राप्त गति, महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़कर, जब इसमें गिरावट आई थी, 2010-11 के बाद से व्यापक रूप से स्थिर रही, लेकिन 2022-23 में इसने अपने महामारी पूर्व स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर, मुद्रा गुणक (एमएम), जो 2012-13 में 5.5 के शीर्ष स्तर पर था, उसके बाद मुख्य रूप से स्थिर हो गया, और 24 मार्च, 2023 को 5.2 पर पहुंच गया, जो आंशिक रूप से, अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में गैर-बैंकों की बढ़ती भूमिका के कारण, 5.5 (2012-22) के दशकीय औसत[24] से नीचे था। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित - विश्लेषणात्मक रूप से केंद्रीय बैंक के पास, बैंकों की जमाराशियों के समान- मुद्रा गुणक 24 मार्च, 2023 को मामूली रूप से कम होकर 5.1 हो गया, जो ऋण मांग की स्थिति में सुधार के बीच एमएम और समायोजित एमएम के अभिसरण को दर्शाता है, जिससे बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो / एसडीएफ के तहत रखी गई राशि में भारी गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II.4.12)।

II.4.16 एमएम को चलाने वाले दो व्यवहारिक अनुपातों में, मुख्यतः सीआरआर पर नज़र रखने के दौरान, आरक्षित-जमा अनुपात[25] पिछले एक दशक (2013-2023) कमोबेश स्थिर था, जबकि मुद्रा-जमा-अनुपात में एक व्यापक-बढ़त प्रवृत्ति दिखी जो कि मुद्रा के रूप में उच्चतर एहतियाती घरेलू बचतों को दर्शाता

चार्ट II.4.12 : मुद्रा वेग और मुद्रा बहुगुणक

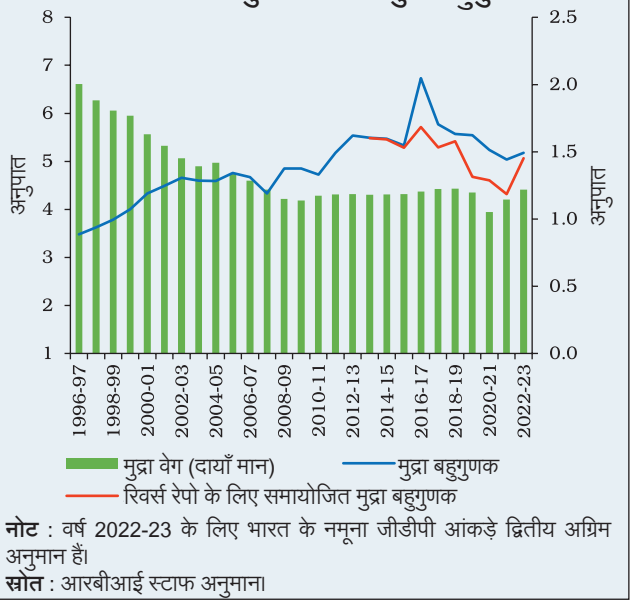

नोट : वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नमूना जीडीपी आंकड़े द्वितीय अग्रिम अनुमान हैं।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[24] विमुद्रीकरण का वर्ष 2016-17 को छोड़कर।

[25] दिनांक 24 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, आरक्षित-जमा अनुपात 4.6 प्रतिशत था (एक वर्ष पूर्व 4.2 प्रतिशत), जो 21 मई 2022 से कि 50 बीपीएस बढ़त के कारण 4.5 प्रतिशत हुए सीआरआर के प्रभाव को दर्शाता है।

चार्ट II.4.13 : व्यवहारगत अनुपातों में अंतर्निहित मुद्रा बहुगुणक

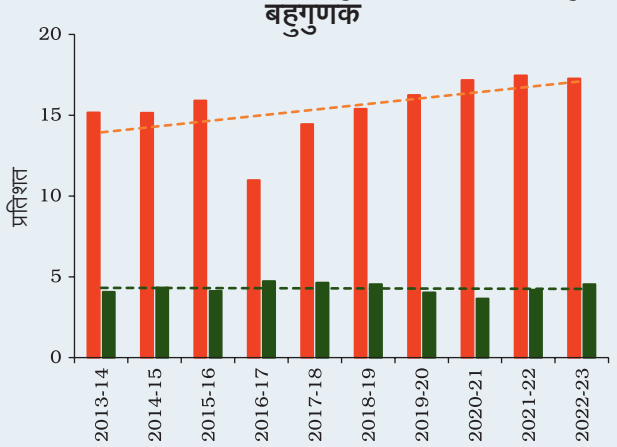

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.4.14 समग्र जमा और बैंक ऋण – पाँच वर्ष की वार्षिकीकृत वृद्धि दर (मौसमी रूप से समायोजित)

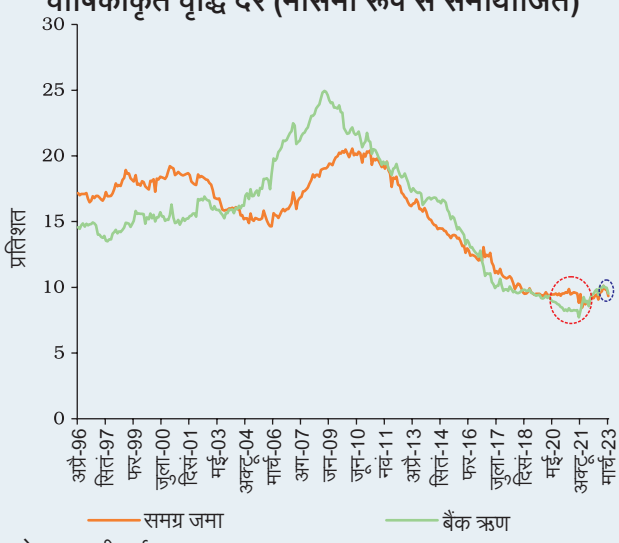

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

है, जिसने बदले में मुद्रा-बहुगुणक को कम कर दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान, हाल ही की घटनाओं के बाद, मुद्रा-जमा अनुपात कम होकर 17.3 प्रतिशत पर स्थित हो गया, हालांकि यह तब भी अपने 16.0 प्रतिशत के दशकीय औसत (2013-22) से अधिक था (चार्ट II.4.13), जो कि कोविड के उपरांत हुए अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण के कारण आर्थिक एजेंटों द्वारा एहतियाती 'डैश फॉर कैश' से दूर हटने के अतिरिक्त मई 2022 से ब्याज दरों के बढ़ते दौर को दर्शाता है।

4. ऋण

II.4.17 जुलाई 2011 से जमा और ऋण में 5 साल की मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि ने एक-दूसरे को बारीकी से ट्रैक किया, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के सापेक्ष भारतीय अनुकूल विकास विभेदक के कारण विदेशी पूंजी प्रवाह (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार) तक बेहतर पहुंच के साथ मेल खाता था। महामारी के मद्देनजर, हालांकि, फरवरी 2020 से ऋण वृद्धि की तुलना में जमाराशि में हुई वृद्धि के साथ, ऋण और जमा की वृद्धि दर में एक विचलन फिर से प्रकट हुआ। नवंबर 2021 तक उक्त अंतर कम हो जाने के बाद भी अंतराल जारी रहा (चार्ट II.4.14 और चार्ट II.4.15ए)।

II.4.18 गत समय में, जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से सामान्यतः अधिक स्थिर रही है (चार्ट II.4.15ए)। आगे, कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन/पाबंदियों के क्रमशः हटने के साथ, अगस्त 2021 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण उठाव की गति अधिकांशतः सकारात्मक रही है (चार्ट II.4.15बी)। दिनांक 24 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, एससीबी का ऋण-जमा अनुपात 75.8 प्रतिशत (मार्च 2022 के अंत में 72.4 प्रतिशत) रहा।

II.4.19 वर्ष 2022-23 के दौरान, ऋण वृद्धि के लिए उत्साहवर्धक मांग के बीच, पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों के द्वारा जमाराशि प्रमाण पत्र (सीडी) जारी करने में काफी वृद्धि हुई, जो बैंकों द्वारा उत्साही ऋण उठाव (ऑफटेक) और मामूली जमा वृद्धि के बीच वित्त पोषण अंतराल को कम करने के लिए चलनिधि की अतिरिक्त मांग को दर्शाता है। प्राथमिक बाजार में, वर्ष के दौरान सीडी जारी करने के माध्यम से निधि जुटाना ₹6.73 लाख करोड़ पर मजबूत रहा, जो स्पष्ट रूप से पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक रहा। दूसरी ओर, नीतिगत दर में वृद्धि के अनुरूप वाणिज्यिक पत्रों (सीपी)

चार्ट II.4.15: एससीबी की जमाराशियाँ और ऋण

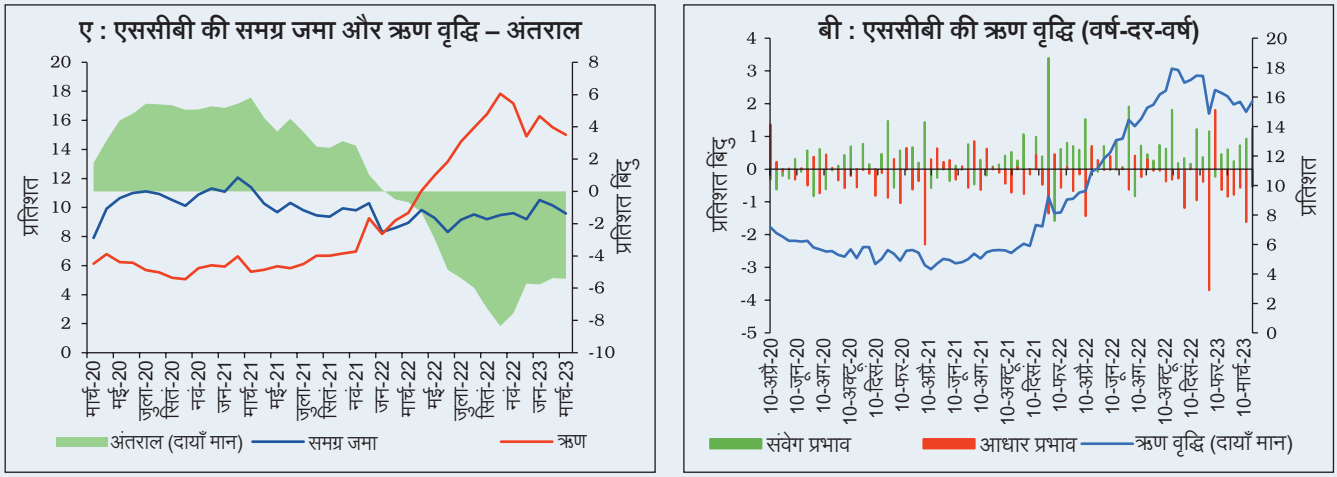

स्रोत : आरबीआई

पर ब्याज दर में कमी होने के कारण, वर्ष के दौरान सीपी निर्गम में अत्यधिक गिरावट देखी गई तथा फर्मों ने 2022-23 के दौरान सीपी पर अपनी निर्भरता कम कर दी और बैंक ऋण की उनकी मांग में सुधार हुआ (चार्ट II.4.16ए)। 24 मार्च, 2023 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि 15.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 9.6 प्रतिशत) के साथ, वर्ष के दौरान ऋण उठाव (ऑफ टेक) व्यापक आधार पर रही। बैंक समूहों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) दोनों ने ऋण वृद्धि में तेजी दर्ज की। 24 मार्च, 2023 को पीएसबी की वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि 16.4 प्रतिशत (एक साल पहले 5.6 प्रतिशत) थी, जो पीवीबी की 17.8 प्रतिशत (एक साल पहले 12.8 प्रतिशत) की तुलना में कम थी, जिससे कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में पीवीबी की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई। हालांकि, कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में पीएसबी का हिस्सा बैंक-समूहों में सर्वाधिक रहा (चार्ट II.4.16बी और चार्ट II.4.16सी)।

चार्ट II.4.16: सीडी, सीपी और बैंक-समूहवार ऋण

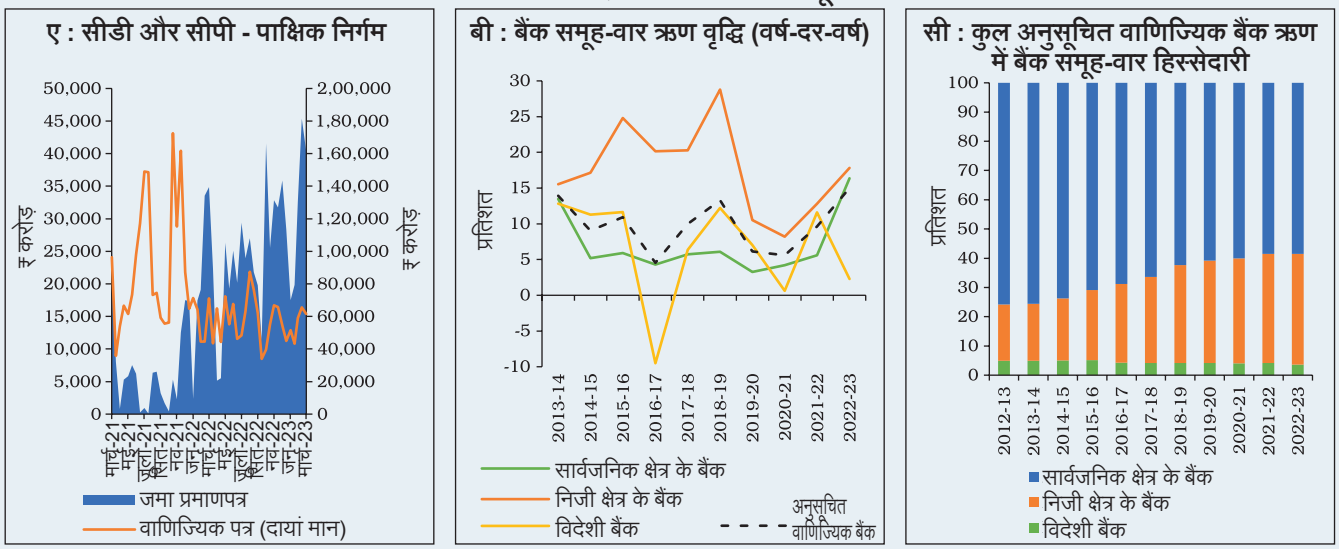

स्रोत : आरबीआई

चार्ट II.4.17: क्षेत्रवार एससीबी का खाद्येतर ऋण

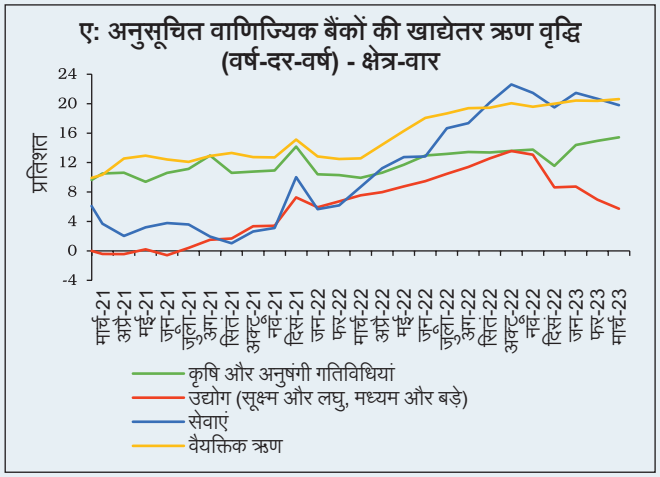

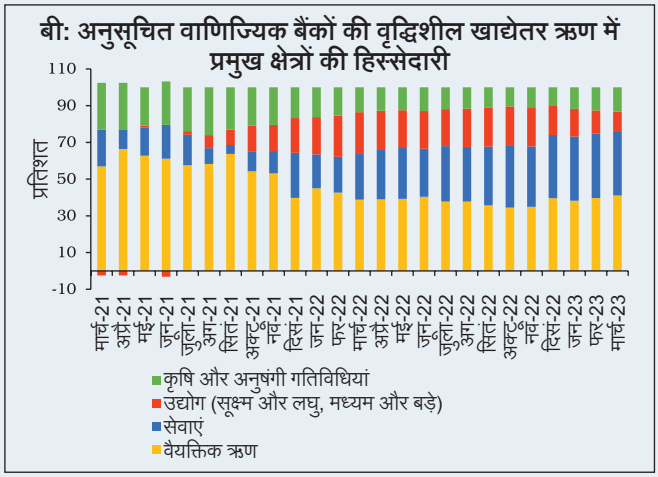

स्रोत : आरबीआई

II.4.20 बैंक ऋण[26] क्षेत्रवार अभिनियोजन के आकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र के ऋण वृद्धि विस्तार को सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों द्वारा समर्थित किया गया। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत गारंटी कवर से सूक्ष्म और लघु उद्योग/ मध्यम उद्योग को ऋण वृद्धि लाभ हुआ। वर्ष के दौरान पूंजी-प्रधान उद्योग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े उद्योगों में ऋण वृद्धि दर्ज की गई, यह सरकार के उच्च पूंजीगत व्यय द्वारा समर्थित रहा। हालांकि, वर्ष के अंत में इसमें कमी आई। इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण वृद्धि सड़क क्षेत्र के कारण हुई, जिसने उच्च आधार पर अच्छी ऋण वृद्धि जारी रखी । वर्ष के दौरान पण्य-प्रधान उद्योगों जैसे - धातु में सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, 2022-23 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण संवर्धित ऋण उठाव (ऑफटेक) के साथ समेकित

चार्ट II.4.18ए: ऋण-जीडीपी अंतर

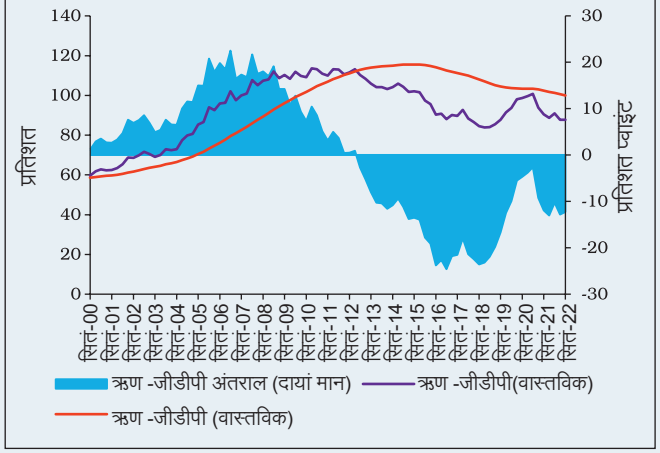

चार्ट II.4.18बी: विनिर्माण का क्षमता उपयोग और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि

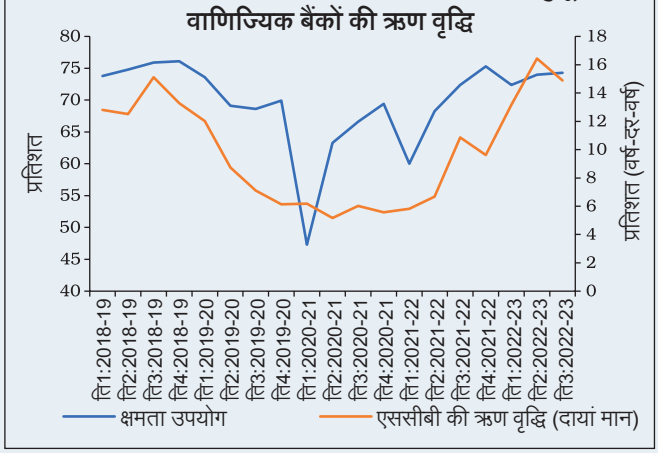

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) और आरबीआई।

[26] खाद्येतर ऋण पाक्षिक आधार पर खंड 42 विवरणी पर आधारित हैं जिसमें सभी एससीबी शामिल हैं, जबकि क्षेत्रगत खाद्येतर ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी एससीबी द्वारा कुल खाद्येतर ऋण विस्तार में से 93 प्रतिशत चुनिंदा बैंकों का है और माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

सारणी II.4.2: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि - एससीबी

(प्रतिशत वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	2020-21*	2021-22#	2022-23											
			अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
खाद्येतर ऋण	**5.5**	**9.7**	**11.4**	**12.7**	**13.7**	**15.1**	**16.0**	**16.9**	**18.3**	**17.6**	**15.3**	**16.7**	**15.9**	**15.4**
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	**10.5**	**9.9**	**10.6**	**11.7**	**13.0**	**13.2**	**13.4**	**13.4**	**13.6**	**13.8**	**11.5**	**14.4**	**14.9**	**15.4**
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम) और बड़े)	**-0.4**	**7.5**	**8.0**	**8.8**	**9.5**	**10.5**	**11.4**	**12.6**	**13.6**	**13.1**	**8.6**	**8.7**	**7.0**	**5.7**
II.1. सूक्ष्म और लघु	7.5	23.0	30.0	33.0	29.6	28.3	28.2	27.1	20.4	19.6	13.7	15.2	13.2	12.3
II.2. मध्यम	31.4	54.4	53.7	49.3	47.4	36.8	35.6	36.2	31.0	29.7	15.4	18.1	13.5	19.6
II.3. बड़े	-3.1	2.0	1.3	2.0	3.3	5.2	6.4	7.9	10.9	10.5	6.9	6.5	5.0	3.0
II.3.1 इंफ्रास्ट्रक्चर	1.1	9.1	9.7	9.8	9.5	11.1	11.0	10.9	10.9	10.5	5.3	2.3	0.6	-0.7
II.3.1.1 ऊर्जा	-1.1	7.1	8.1	9.3	8.7	9.7	9.4	8.1	7.5	7.7	2.4	2.8	0.6	-1.1
II.3.1.2 दूरसंचार	-21.9	13.4	13.8	12.8	13.1	11.4	17.2	16.3	18.4	22.9	5.3	-12.8	-11.8	-14.6
II.3.1.3 सड़कें	24.7	19.5	17.3	17.6	17.8	16.4	15.3	13.4	13.8	13.4	12.5	8.7	6.8	5.3
II.3.2 मूल धातु और धातु उत्पाद	-8.8	-5.5	-4.4	-2.3	0.6	5.6	5.7	10.6	14.1	15.3	19.1	22.0	19.7	19.1
II.3.3 रसायन और रसायनिक उत्पाद	-7.0	6.2	10.4	15.6	15.1	20.2	23.5	22.5	25.1	19.1	15.8	17.6	15.2	10.2
II.3.4 वस्त्र	6.0	9.3	7.1	5.1	5.3	3.8	4.0	4.9	4.4	3.0	0.4	0.8	0.3	1.7
II.3.5 सभी इंजीनियरिंग	-5.7	9.4	9.7	9.1	11.1	11.3	11.3	13.8	13.8	11.1	8.4	6.2	6.7	4.3
II.3.6 खाद्य प्रसंस्करण	8.5	10.7	10.7	11.5	14.0	9.8	9.5	8.0	6.9	7.4	4.1	4.7	5.8	5.6
III. सेवाएं	**3.7**	**8.7**	**11.2**	**12.7**	**12.8**	**16.7**	**17.4**	**20.2**	**22.6**	**21.5**	**19.5**	**21.5**	**20.7**	**19.8**
III.1. व्यापार	12.8	10.8	13.2	13.2	16.7	14.2	16.9	21.3	17.0	16.0	13.9	16.8	16.7	17.8
III.2. एनबीएफसी	-0.2	7.8	14.7	17.8	18.1	24.6	25.5	29.3	34.9	33.0	34.5	31.0	32.4	30.2
IV. वैयक्तिक ऋण	**10.3**	**12.6**	**14.4**	**16.3**	**18.1**	**18.7**	**19.4**	**19.4**	**20.1**	**19.6**	**20.0**	**20.4**	**20.4**	**20.6**
IV.1. आवास	9.6	12.9	13.7	13.6	15.1	16.2	16.4	16.0	16.2	16.2	16.1	15.4	15.0	15.0
IV.2. वाहन ऋण	8.5	9.3	11.4	14.1	17.7	19.2	19.5	19.9	22.1	22.5	24.7	25.5	23.4	24.9

संकुचन ← → विस्तार

*: मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021। #: मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022।

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. 3 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2022 की बैंक ऋण संवृद्धि को चुनिंदा अनुसूचित वाणिजिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई त्रुटियों के लिए समायोजित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

हुआ, जबकि व्यापार क्षेत्र की ऋण वृद्धि ने व्यावसायिक गतिविधियों में सकारात्मक उत्साह में कमी दर्शाई। आवास और वाहन ऋणों के कारण खुदरा ऋणों ने निरंतर वृद्धि दर्ज करते हुए समग्र ऋण वृद्धि में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा, वृद्धिशील खाद्येतर ऋण में व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष के दौरान धीरे-धीरे बढ़ी, जो इन क्षेत्रों में ऋण मांग की स्थिति में सुधार का संकेत देता है (चार्ट II.4.17 और सारणी II.4.2)।

II.4.21 ऋण-जीडीपी अंतर अपने पिछले उच्चतम स्तर से काफी कम हो गया, जो विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती क्षमता उपयोग की तुलना में अर्थव्यवस्था में बेहतर ऋण मांग को दर्शाता है (चार्ट II.4.18ए और चार्ट II.4.18बी)।

5. निष्कर्ष

II.4.22 कुल प्रमुख मौद्रिक और ऋण राशियां, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख और अर्थव्यवस्था में कुल मांग की स्थिति के अनुरूप रहीं। वर्ष के दौरान उपभोक्ता आशावाद की वापसी और कारोबार दृष्टिकोण में सुधार से आगे ऋण वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालांकि बैंकों को पूरी प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी के माहौल में जमा संग्रहण प्रयासों को तेज करना पड़ सकता है।

II.5 वित्तीय बाजार

II.5.1 भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक संवृद्धि एवं व्यापार परिदृश्य में गिरावट, मुद्रास्फीति में वैश्विक संवृद्धि और मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने के बाद अनिश्चितता बढ़ने के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में साल के अधिकांश समय उथल-पुथल देखी गई। 2022 की चौथी तिमाही तक बाजार में स्थिरता का आभास दिखाई देने लगा था, जब ऐसा लगा था कि मुद्रास्फीति चरम पर है, वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों में और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी आई है। हालांकि, 2023 में वैश्विक विकास की कम संभावना और अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग में हुई उथल-पुथल के बाद वित्तीय स्थिरता से संबन्धित मुद्दों के कारण वैश्विक वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन 2023 की पहली तिमाही के दौरान अस्थिर रहा।

II.5.2 अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के सामान्य दरों से कम पर बेचने के चलते ईएमई ने अपने सामान्य शेयर और मुद्रा बाजारों में अस्थिरता का अनुभव किया। यूक्रेन में युद्ध के बाद आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के कारण अधिकांश वस्तुओं और कच्चे तेल की कीमतें 2022 की दूसरी तिमाही में काफी बढ़ गईं। वैश्विक मांग की स्थिति कमजोर होने के बाद कीमतों में गिरावट आई, यहां तक कि चीन को शून्य-कोविड नीति समाप्त करने के बाद फिर से खोलने से नए सिरे से दबाव बढ़ गया।

II.5.3 वैश्विक स्पिलओवर के लगातार प्रभाव के बावजूद भारतीय वित्तीय बाजार आघात-सह बने रहे। भारत के शेयर बाजारों ने 2022-23 में समष्टि आर्थिक मूल-तत्वों और अनुकूल विकास संभावनाओं के बल पर अपने अधिकांश ईएमई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में अस्थिर बाजार स्थिति के चलते अनुदान संचयन में कमी देखी गई। हालांकि मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति के लिए बदलते परिदृश्य के चलते 10 साल की सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल सीमित दायरे में बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर में नरमी के चलते रुपया 2022-23 की तीसरी तिमाही में अपने निचले स्तर से नीचे आ गया और चौथी तिमाही में काफी हद तक सीमित दायरे में व्यापार कर रहा था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उच्च लाभप्रदता, उनकी बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी स्तर और चलनिधि बफर से बैंक ऋण की बढ़ती मांग और निवेश में सुधार के शुरुआती संकेतों को लाभ हुआ।

II.5.4 इस पृष्ठभूमि में मुद्रा बाजार के विकास को उप-खंड 2 में विस्तृत किया गया है। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल पर उप- खंड 3 में चर्चा की गई है। उप- खंड 4 कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में विकास को दर्शाती है। उप-खंड 5 घरेलू इक्विटी बाजार में विकास को रेखांकित करती है और उप-खंड 6 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। अंतिम उप-खंड कुछ अग्रगामी दृष्टिकोणों के साथ समापन टिप्पणियों को दर्शाता है।

2. मुद्रा बाजार

II.5.5 2022-23 के दौरान मुद्रा बाजार की रुझान प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी, ऋण मांग में उछाल और नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि के बाद वित्तीय बाजार की स्थिति को मजबूत करने को दर्शाते हैं।

II.5.6 भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – नीतिगत कॉरिडोर के तल से धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ा [अर्थात, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर] पॉलिसी रेपो दर की ओर दर वृद्धि चक्र और मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप नीति रेपो दर की ओर बढ़ गया। जैसे-जैसे ऋण वृद्धि धीरे-धीरे जमा वृद्धि से ऊपर बढ़ी, मुद्रा बाजार की दरें मजबूत हुईं।

चार्ट II.5.1 मुद्रा बाजार दरें और नीतिगत कॉरीडोर

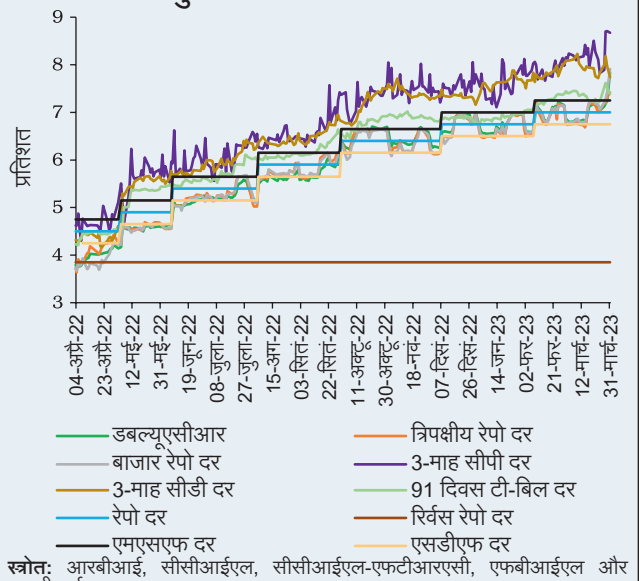

स्त्रोत: आरबीआई, सीसीआईएल, सीसीआईएल-एफटीआरएसी, एफबीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा

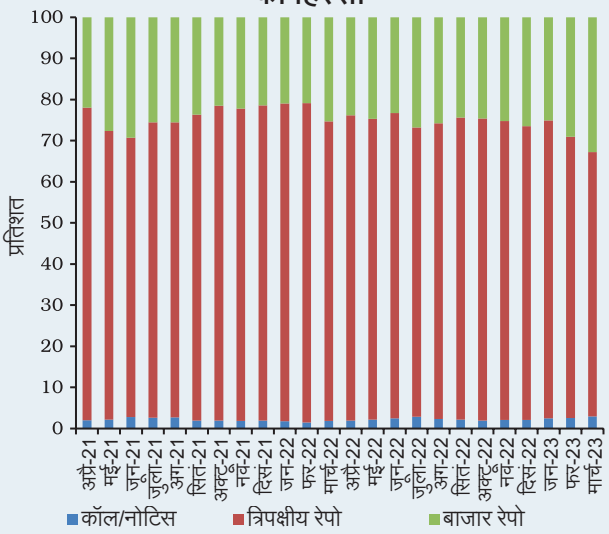

स्त्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रिज़र्व बैंक[27] के चलनिधि निकासी रुख के अनुसार नीतिगत दर के सापेक्ष डब्ल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड 2021-22 में (-)75 आधार अंक से घटकर 2022-23 में (-)12 आधार अंक रह गया। 2022-23 की चौथी तिमाही में स्प्रेड (-)1 बीपीएस तक कम हो गया [चार्ट II.5.1]।

II.5.7 डब्ल्यूएसीआर के बदलाव के गुणांक से मापे जाने वाले मांग मुद्रा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव[28] जो पिछले वर्ष 4.1 था, 2022-23 में बढ़कर 18.1 हो गया ।

II.5.8 मुद्रा बाजार[29] में औसत दैनिक मात्रा जो 2021-22 में ₹4,55,224 करोड़ थी, 2022-23 के दौरान 18 प्रतिशत बढ़कर ₹5,36,456 करोड़ हो गई। कुल मुद्रा बाजार की मात्रा में त्रिपक्षीय रेपो की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल के 74 प्रतिशत से घटकर 72 प्रतिशत हो गई, जबकि बाजार रेपो में मात्रा पिछले साल के 24 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई; दूसरी ओर, असंपार्श्विक मांग मुद्रा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत पर बनी रही। मांग मुद्रा क्षेत्र में औसत दैनिक मात्रा (शनिवार को छोड़कर) वर्ष के दौरान 37 प्रतिशत बढ़कर ₹12,432 करोड़ (2021-22 के दौरान ₹9,060 करोड़ से) हो गई जो कि आंशिक रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 4.0 प्रतिशत से मई 2022 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि और सिस्टम में अधिशेष चलनिधि में आई क्रमिक गिरावट दर्शाती है (चार्ट II.5.2)।

II.5.9 अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे 91-दिवसीय खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर ब्याज दरें आम तौर पर एक दिवसीय बाजार दर(कॉल, त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो) के साथ तालमेल में चलती हैं और 4 मई 2022 को पहली दर वृद्धि तक ज्यादातर रेपो दर के आसपास व्यापार करती हैं; वे उसके बाद भी रेपो दर से ऊपर बनी रहीं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान टी-बिल दरों पर सीडी दरों और सीपी दरों (एनबीएफसी और गैर-एनबीएफसी द्वारा जारी) के औसत दैनिक स्प्रेड में काफी वृद्धि हुई (चार्ट II.5.3)। 2022-23 की चौथी तिमाही में दरें रेपो दर

[27] चलनिधि प्रबंधन प्रचालनों से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

[28] भिन्नता के गुणांक को मानक विचलन के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

[29] शनिवार को छोड़कर, मुद्रा मांग, त्रिपक्षीय रेपो और एक दिवसीय और टर्म दोनों क्षेत्र के बाजार रेपो।

चार्ट II.5.3: 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड

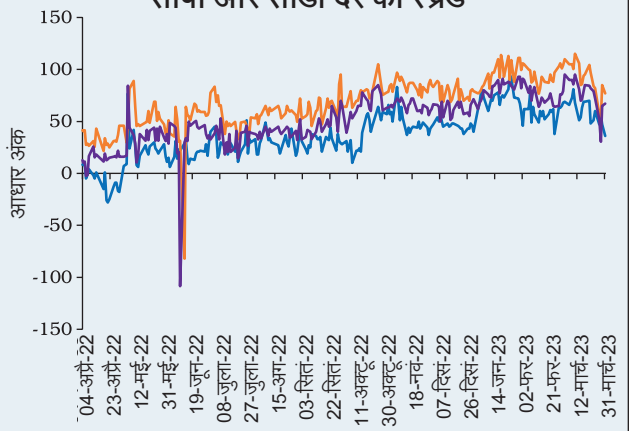

स्त्रोत: ब्लूमबर्ग, एफबीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5.4: 10-वर्षीय जी-सेक सामान्य प्रतिफल

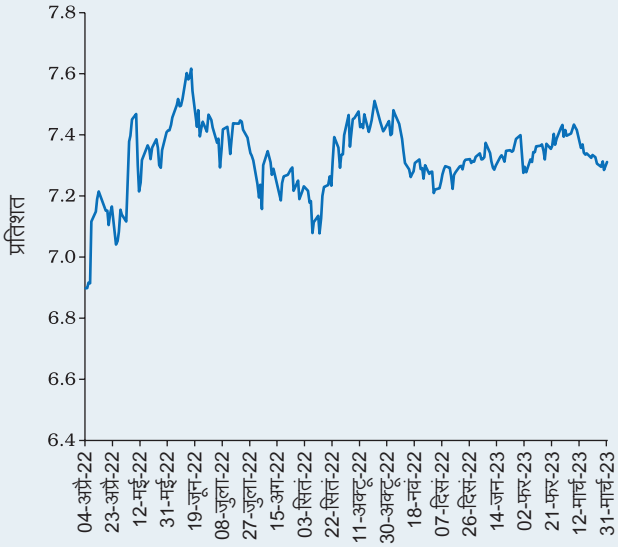

स्त्रोत: ब्लूमबर्ग

से ऊपर बढ़ गईं, जो अधिशेष चलनिधि में कमी के साथ-साथ जोखिम प्रीमियम में वृद्धि को दर्शाती हैं।

II.5.10 प्राथमिक बाजार में सीडी जारी करने की नई राशि 2021-22 में ₹2.33 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान बढ़कर ₹6.73 लाख करोड़ हो गई क्योंकि बैंकों ने मीयादी जमा दरों में काफी वृद्धि के बाद भी ऋण मांग को पीछे छोड़ते हुए जमा जुटाने में सीडी का सहारा लिया। हालांकि, प्राथमिक बाजार में सीपी जारी करने की नई राशि 2021-22 में ₹20.19 लाख करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹13.73 लाख करोड़ रह गई।

3. जी-सेक बाजार

II.5.11 केंद्र और राज्यों के संयुक्त उधार कार्यक्रम के आकार के बारे में प्रारंभिक बाजार चिंताओं के बावजूद एक सीमाबद्ध अवधि के विस्तार के साथ उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया था (विवरण के लिए कृपया अध्याय VII देखें)। हालांकि, वर्ष के दौरान घरेलू और वैश्विक विकास दोनों ने प्रतिफल के विकास को प्रभावित किया। 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान एलएएफ कॉरिडोर को 50 बीपीएस तक सामान्य करने और एसडीएफ को पॉलिसी कॉरिडोर की नई मंजिल के रूप में पेश करने की घोषणा के कारण जी-सेक प्रतिफल बढ़ा। लगातार उच्च घरेलू सीपीआई प्रिंट की पृष्ठभूमि में मई 2022 में आयोजित ऑफ-साइकिल मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में सीआरआर को 4.50 प्रतिशत तक बढ़ाया और रेपो दर में 40 बीपीएस की बढ़ोतरी ने प्रतिफल वृद्धि में योगदान दिया। 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 16 जून 2022 को 7.62 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई और अप्रैल-जून 2022 तिमाही 7.45 प्रतिशत (चार्ट II.5.4) पर समाप्त हुई।

II.5.12 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने की बाजार की उम्मीदों के कारण दीर्घकालिक प्रतिफल में नरमी आई। हालांकि, तिमाही के अंत में वैश्विक प्रतिफल में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीति लगातार महीनों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन बैंड से ऊपर बने रहने के कारण प्रतिफल में वृद्धि शुरू हुई। तिमाही के दौरान घरेलू प्रतिफल में गिरावट देखी गई क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अल्पकालिक प्रतिफल दीर्घावधि प्रतिफल से अधिक बढ़ा। तिमाही के दौरान 10 साल का सामान्य प्रतिफल 7.40 फीसदी पर समाप्त हुआ। वैश्विक मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने

के बाजार आकलन और अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की कम गति की आशंकाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक प्रतिफल को देखते हुए 2022-23 की तीसरी तिमाही में प्रतिफल में नरमी आई। 2022-23 की चौथी तिमाही के शुरूआत में जी-सेक प्रतिफल ने श्रेणीबद्ध व्यापार किया। हालांकि, बाद में वैश्विक प्रतिफल उम्मीद से अधिक सीपीआई और एमपीसी के कथित आक्रामक रुख के कारण प्रतिफल में वृद्धि हुई। वैश्विक प्रतिफल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के कारण 2022-23 के अंत तक प्रतिफल में नरमी आई। 2022-23 में 10 साल का सामान्य प्रतिफल 7.31 प्रतिशत पर समाप्त हुआ।

II.5.13 1 अप्रैल 2020 से पूर्ण पहुँच मार्ग (एफएआर)[30] की शुरुआत के साथ एफपीआई के पास जी-सेक में निवेश करने के लिए तीन मार्ग हैं, *अर्थात्* मध्यम अवधि के ढांचे (एमटीएफ), स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और एफएआर के तहत निर्धारित निवेश सीमाओं के साथ सामान्य मार्ग। वर्ष 2022-23 के लिए एमटीएफ के तहत जी-सेक में एफपीआई निवेश की सीमा ₹4,04,780 करोड़ निर्धारित की गई थी। एफएआर योजना के तहत शामिल प्रतिभूतियों की संख्या 17 प्रतिभूतियों (1 अप्रैल 2022 को ₹17,58,043 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) से बढ़कर 26 प्रतिभूतियां (31 मार्च 2023 तक ₹27,96,589 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) हो गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एफपीआई ने सामान्य मार्ग के तहत जी-सेक में ₹22,641 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज की। एफपीआई ने वीआरआर के तहत जी-सेक में ₹1,980 करोड़ का आहरण किया जिसमें जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉण्ड के लिए संयुक्त निवेश सीमा ₹2,50,000 करोड़ है। हालांकि, एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान एफएआर मार्ग के तहत ₹31,129 करोड़ का निवेश किया। एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों[31] (एसजीएस) की निवल राशि बेची और 2022-23 के दौरान एमटीएफ, एफएआर और वीआरआर क्षेत्रों में जी-सेक और एसजीएस में कुल ₹6,408 करोड़ वापस लिए।

4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार

II.5.14 बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि और ऋण स्प्रेड के बढ़ने से 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल मार्च 2023 में 193 बीपीएस तक बढ़ गया जबकि एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स पर क्रमशः 215 बीपीएस और 220 बीपीएस की वृद्धि हुई। एएए रेटिंग वाले 3 साल के बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल मार्च 2023 में पीएसयू, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए 7.75 प्रतिशत; एनबीएफसी के लिए 8.12 प्रतिशत और कॉर्पोरेट्स के लिए 8.07 प्रतिशत था।

II.5.15 2022-23 के दौरान एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड (3-वर्षीय जी-सेक से अधिक) पर मासिक औसत जोखिम प्रीमियम या स्प्रेड पीएसयू, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए 21 बीपीएस से बढ़कर 36 बीपीएस हो गया; एनबीएफसी के लिए 35 बीपीएस से 73 बीपीएस और कॉर्पोरेट्स के लिए 25 बीपीएस से 68 बीपीएस तक बढ़ा। कॉरपोरेट बॉण्ड के कार्यकाल और रेटिंग क्षेत्र में स्प्रेड का विस्तार दिखाई दिया। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक द्वितीयक बाजार व्यापार पिछले वर्ष के दौरान ₹5,430 करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹5,549 करोड़ हो गया (चार्ट II.5.5)। भविष्य के समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनजर वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने या जोखिम-बंद की भावना को व्यापक बनाने, निवेश में अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजे के रूप में उच्च अपेक्षित प्रतिलाभ का संकेत देता है (बॉक्स II.5.1)।

[30] एफएआर के तहत घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होने के अलावा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियां बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोली गई थीं।

[31] जैसा कि 7 जुलाई 2022 को आयोजित राज्यों के वित्त सचिवों के 32[वें] सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, 'राज्य विकास ऋण (एसडीएल)' का नामकरण बदलकर 'राज्य सरकार सुरक्षा (एसजीएस)' कर दिया गया है।

चार्ट II.5.5: कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में एएए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार

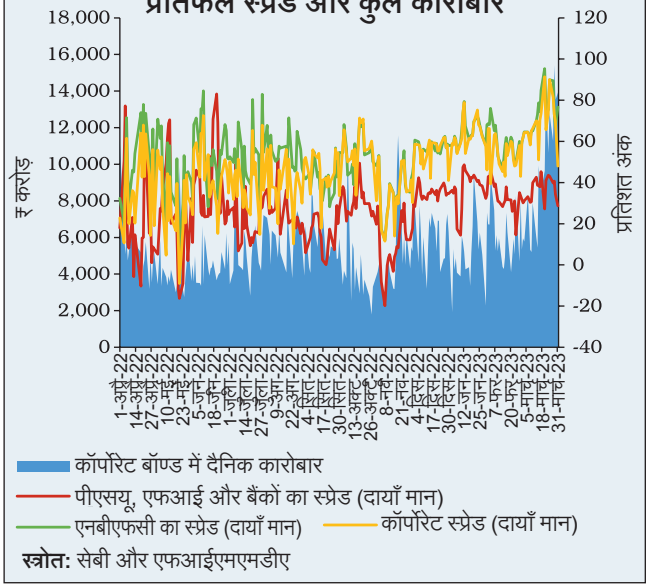

स्रोत: सेबी और एफआईएमएमडीए

II.5.16 2022-23 में घरेलू बाजार में प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने में वृद्धि हुई, जबकि विदेशी बॉण्ड जारी करने में कमी आई। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई घरेलू कॉरपोरेट बॉण्ड ₹6.0 लाख करोड़ थी, जो 2022-23 में बढ़कर ₹7.6 लाख करोड़ हो गई। कॉर्पोरेट्स के लिए निजी नियोजन पसंदीदा चैनल बना रहा, जो बॉण्ड बाजार के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 98.8 प्रतिशत रहा। बकाया कॉर्पोरेट बॉण्ड का आकार सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2023 के अंत तक ₹42 लाख करोड़ (यानी जीडीपी का 15.4 प्रतिशत) हो गया। कॉरपोरेट बॉण्ड के बकाया स्टॉक में एफपीआई का निवेश मार्च 2023 के अंत में घटकर ₹1.04 लाख करोड़ रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में ₹1.21 लाख करोड़ था। फलस्वरूप, एफपीआई द्वारा अनुमोदित सीमा का उपयोग मार्च 2023 के अंत

बॉक्स II.5.1 - वित्तीय बाजारों में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम के चालक

प्रतिफल वक्र या मीयादी प्रीमियम की प्रवणता (स्लोप) को दीर्घकालिक बॉण्ड और अल्पकालिक बॉण्ड के बीच प्रतिफल में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। मीयादी प्रीमियम को विकास, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति (कोप, 2018) के अपेक्षित भविष्य के मार्ग के प्रति संवेदनशील माना जाता है। वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के आधार पर अलग-अलग मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम में समय-समय पर उतार-चढ़ाव, भविष्य के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण और भविष्य की ब्याज दरों के बारे में बाजार की उम्मीदों के बारे में जानकारी रखते उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम को प्रतिलोमत: संबंधित माना जाता है क्योंकि मीयादी प्रीमियम में कमी एक धीमी अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकती है जो क्रेडिट स्प्रेड में वृद्धि में बदल सकती है (लेपोन *एट अल*, 2009; कोलिन *एट अल,* 2001)।

भारत में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम के प्रमुख चालकों और उनके अंतर-संबंधों की पहचान करने के लिए एक अनुभवजन्य अभ्यास किया जाता है। बोर्ड प्रॉक्सी के रूप में अभ्यास के लिए, मीयादी प्रीमियम को 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल और 3 महीने के ट्रेजरी बिल प्रतिफल के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। मार्च 2022 के बाद से भारत में प्रतिफल वक्र सपाट हो गया है; हालांकि, यह 2022-23 (चार्ट 1) के दौरान ऊपर की ओर ढलान पर बना हुआ है।

एक फॉरवर्ड स्टेपवाइज सिलेक्शन (एफएसएस) रिग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है जो फिट या आर^2 की अच्छाई में उनके वृद्धिशील योगदान के आधार पर चर का चयन और रैंक करता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि अतिरिक्त चर जोड़ने से आर^2 मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है।

चार्ट 1: मीयादी प्रीमियम

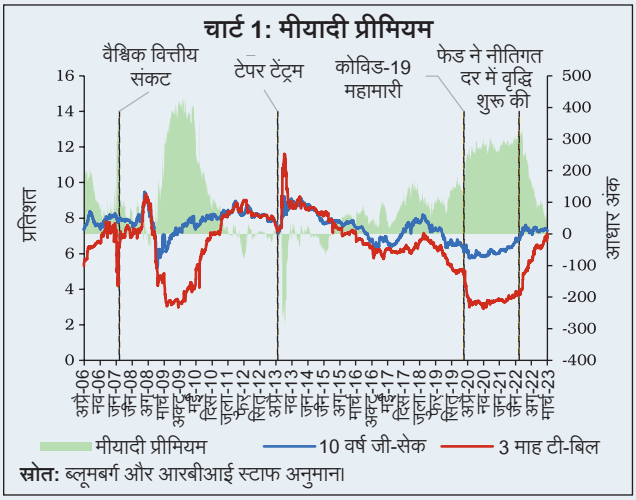

स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति, जी-सेक कारोबार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता को भारत में मीयादी प्रीमियम के महत्वपूर्ण चालकों के रूप में पहचाना जाता है। घाटे की चलनिधि की स्थिति अल्पावधि बॉण्ड प्रतिफल को बढ़ाती है जिससे मीयादी प्रीमियम में गिरावट आती है, जबकि उच्च जी-सेक कारोबार में जी-सेक की उच्च मांग और कम दीर्घकालिक प्रतिफल शामिल होता है जिससे मीयादी प्रीमियम में गिरावट आती है (सारणी 1)। कड़ी आईआईपी वृद्धि से प्रतिफल वक्र ढलान तेज हो जाता है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि से मीयादी प्रीमियम बढ़ जाता है।

(जारी)

सारणी 1: मीयादी प्रीमियम के चालक

रैंकिंग	चर	संकेत
1	निवल एलएएफ (प्रणालीगत चलनिधि)	-
2	जी-सेक टर्नओवर (जी-सेक बाजार चलनिधि)	-
3	आईआईपी वृद्धि (आर्थिक गतिविधि)	+
4	वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक	+

नोट: उपर्युक्त सभी रिपोर्ट किए गए चर 5 प्रतिशत महत्व के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। एफएसएस रिग्रेशन में उपयोग किए जाने वाले अन्य चर में सीपीआई मुद्रास्फीति (चक्र घटक), ऋण बाजार में निवल एफपीआई प्रवाह, भारत सरकार की निवल बाजार उधारी और यूएसडी / आईएनआर विनिमय दर शामिल थी, लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाए गए। नमूने में नवंबर 2012 से सितंबर 2022 तक की अवधि शामिल है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मीयादी प्रीमियम को जोखिम प्रीमियम के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जोखिम प्रीमियम एएए-रेटेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड और समान परिपक्वता जी-सेक प्रतिफल (चार्ट 2) पर प्रतिफल के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। जोखिम प्रीमियम और मीयादी प्रीमियम के बीच सहसंबंध -0.58 निकला, जो हालांकि कम था लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था।

एफएसएस प्रतिगमन का उपयोग करने वाले अनुमानों से पता चलता है कि उच्च मीयादी प्रीमियम जोखिम प्रीमियम को कम करता है। मीयादी प्रीमियम के अलावा, एफएसएस प्रतिगमन में उपयोग किए जाने वाले चर जोखिम प्रीमियम के चालकों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, *यानी,* इंडिया VIX, मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों में बदलाव, निवल एलएएफ, यूएस क्रेडिट स्प्रेड और विनिमय दर अस्थिरता (1 महीना), सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाए जाते हैं।

चार्ट 2: जोखिम प्रीमियम और मीयादी प्रीमियम

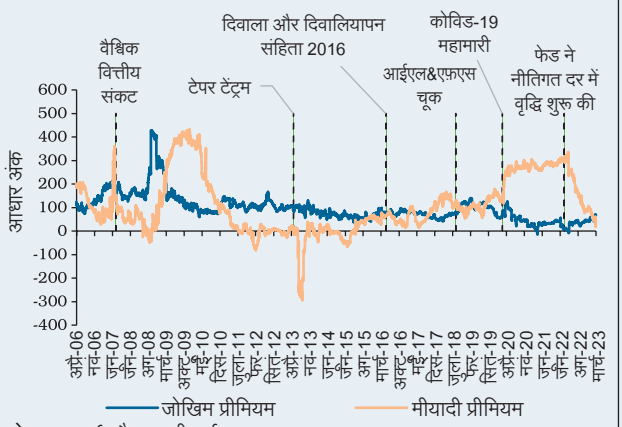

स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. कोलिन-डुफ्रेसन, पी., गोल्डस्टीन, आर.एस., और मार्टिन, जे.एस. (2001), 'डा डिटरमीनंट्स ऑफ क्रेडिट स्प्रेड चेंजेस', द जर्नल ऑफ फाइनेंस, 56 (6), 2177-2207।
2. कोप, ई. और विलियम्स, पी. डी. (2018), के लिए 'ए मैक्रोइकॉनॉमिक अप्रोच टू दा टर्म प्रीमियम', अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग पेपर, संख्या 2018/140।
3. लेपोन, ए. और वोंग, बी. (2009), 'डिटरमीनंट्स ऑफ क्रेडिट स्प्रेड चेंजेस: एविडंस फ्रोम दा ऑस्ट्रेलियन बॉण्ड मार्केट', ऑस्ट्रेलियाई लेखा, व्यापार और वित्त जर्नल, 3 (2), 26-35

में घटकर 15.52 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में 19.94 प्रतिशत था।

5. इक्विटी बाजार

II.5.17 भारतीय इक्विटी बाजार ने 2022-23 के दौरान बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं वाले परिवेश के बावजूद भी आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया। वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकांश ईएमई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीएसई सेंसेक्स 0.7 प्रतिशत बढ़कर 58,992 पर और निफ्टी-50 0.6 प्रतिशत गिरकर 17,360 पर बंद हुआ (चार्ट II.5.6ए और चार्ट II.5.6बी)। निफ्टी 50 की अल्पकालिक अस्थिरता को दर्ज करने वाला इंडिया VIX, 2021-22 के दौरान 17.8 के औसत की तुलना में 2022-23 के दौरान औसतन 17.5 था।

II.5.18 बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति, अमेरिका में मौद्रिक नीति में सख्ती और चीन में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन की चिंताओं के बीच भारतीय इक्विटी बाजार ने 2022-23 की पहली तिमाही में नुकसान दर्ज किया। यूएस फेड की आक्रामक टिप्पणियों से जोखिम के स्तर में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ। यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति के निरंतर दबाव ने वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ा दी, जिससे जून 2022 में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई और बाजारों में बिकवाली शुरू हो गई।

II.5.19 जुलाई 2022 में बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी आई क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतों में गिरावट और मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी ने जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट आई और इक्विटी कीमतों में

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार

ए. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव

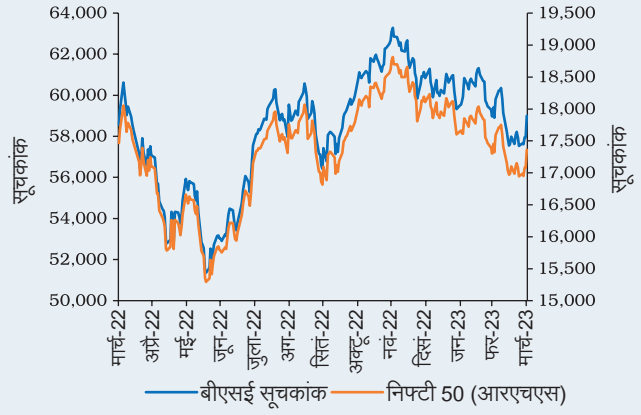

बी. 2022-23 के दौरान वैश्विक इक्विटी सूचकांकों पर प्रतिलाभ

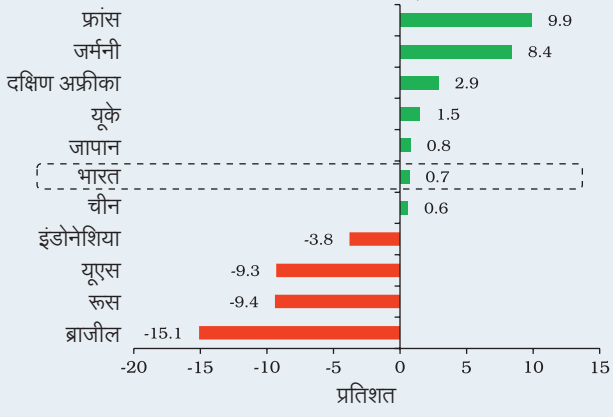

स्रोत : बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

वृद्धि हुई। इसके अलावा, भारतीय कॉर्पोरेट्स के 2022-23 की पहली तिमाही के नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बहाल किया है। एफपीआई नौ महीने के अंतराल के बाद जुलाई 2022 में भारतीय इक्विटी बाजार में निवल खरीदार बने। वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के बावजूद, भारतीय इक्विटी में अगस्त 2022 में मजबूत समष्टि आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और घरेलू मुद्रास्फीति के शिखर से नरम होने से और तेजी आई।

II.5.20 हालांकि, सितंबर 2022 में यूएस फेड और प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दर में वृद्धि के कारण वैश्विक इक्विटी बाजारों में बिकवाली का एक और दौर शुरू हुआ, जिसमें भारतीय इक्विटी में एफपीआई प्रवाह महीने के दौरान नकारात्मक हो गया। हालांकि, भारतीय इक्विटी सूचकांकों में गिरावट अन्य वैश्विक इक्विटी बाजारों के सापेक्ष कम थी।

II.5.21 सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और एफपीआई के भारतीय इक्विटी बाजार में निवल खरीदार बनने से वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता में सुधार के कारण अक्तूबर 2022 में भारतीय इक्विटि बाजार में तेजी आई। इसके अलावा, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कॉर्पोरेट्स के 2022-23 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों ने बाजार के रुख को तेजी प्रदान किया। वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति में नरमी के बीच जोखिम के रुख में सुधार तथा अमेरिकी संघीय खुला बाजार समिति (एफओएमसी) के कम आक्रामक कार्यवृत्त के कारण नवंबर 2022 के दौरान बेंचमार्क भारतीय इक्विटि सूचकांक नए शिखर पर पहुंच गए।

II.5.22 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स ने 1 दिसंबर 2022 को 63,284 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया, लेकिन बाद में वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के कारण इसमें गिरावट आई। चीन में कोविड-19 के मामलों के फिर से बढ़ने के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त करने के संकेतों के कारण जोखिम वहन क्षमता कम हो गई।

II.5.23 जनवरी 2023 के पूर्वार्ध में सीमित रहने के बाद, प्रारंभ के दूसरी छमाही में सकारात्मक कॉर्पोरेट आय जारी करने और कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कमी के कारण घरेलू इक्विटी बाजार ऊपर की ओर गया। हालांकि, एक व्यावसायिक समूह के स्टॉक्स में असामान्य कीमत उतार-चढ़ाव के बाद महीने के अंत में रुख नकारात्मक हो गई।

II.5.24 केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि और चुनिंदा प्रत्यक्ष कर राहतों से संबंधित घोषणाओं, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा घरेलू वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थितियों

की मजबूती की फिर से पुष्टि करने वाले बयानों ने फरवरी की शुरुआत में बाजार की रुख को बढ़ावा देने में मदद की। हालांकि, कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दूसरी छमाही में बाजार दबाव में आ गया। संघीय खुला बाजार समिति (एफओएमसी) की बैठक के आक्रामक कार्यवृत जारी होने के बाद जोखिम वहन क्षमता प्रभावित हुई, जिसमें बढ़ी हुई मुद्रास्फीति पर चिंता व्यक्त की गई थी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी, जिसके कारण अमेरिकी राजकोष प्रतिफल में तेज वृद्धि हुई।

II.5.25 सकारात्मक घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से मार्च 2023 की शुरुआत में घरेलू इक्विटी में तेजी आई। इसके बाद, अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल के बीच तेजी से मौद्रिक नीति सख्त होने के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता पर चिंताएं सामने आईं। हालांकि, वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति के बारे में कई हितधारकों और नियामकों के आश्वासन के बाद संक्रमण की आशंका कम होने से महीने के अंत तक बाजार में सुधार हुआ।

II.5.26 क्षेत्रवार आधार पर 2022-23 की अवधि के दौरान औद्योगिक, पूंजीगत सामान, शीघ्र विक्रेय/ खपत वाली उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटो और बैंकिंग की कंपनियों ने दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट II.5.7.ए)।

II.5.27 वर्ष के दौरान एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहा। एफपीआई ने 2022-23 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में ₹43,943 करोड़ की निवल बिक्री की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में निवल बिक्री ₹1.3 लाख करोड़ थी। हालांकि, म्यूचुअल फंड से प्रवाह को समर्थन मिला। म्यूचुअल फंड ने 2022-23 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ₹1.7 लाख करोड़ की निवल खरीदारी की (चार्ट II.5.7.बी)। भारतीय इक्विटी में एफपीआई का स्वामित्व मार्च 2015 में 23.3 प्रतिशत के शीर्ष शेयर से घटकर मार्च 2023 के अंत तक 20.6 प्रतिशत हो गया है क्योंकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) अंतर्वाह ने एफपीआई अंतर्वाह को पीछे छोड़ दिया है (चार्ट 2.5.7.सी)।

II.5.28 भारतीय इक्विटी (एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों) के बाजार पूंजीकरण में घरेलू संस्थागत निवेशकों (घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड सहित) की हिस्सेदारी मार्च

चार्ट II.5.7: इक्विटी मार्केट में क्षेत्रीय प्रदर्शन और संस्थागत निवेश

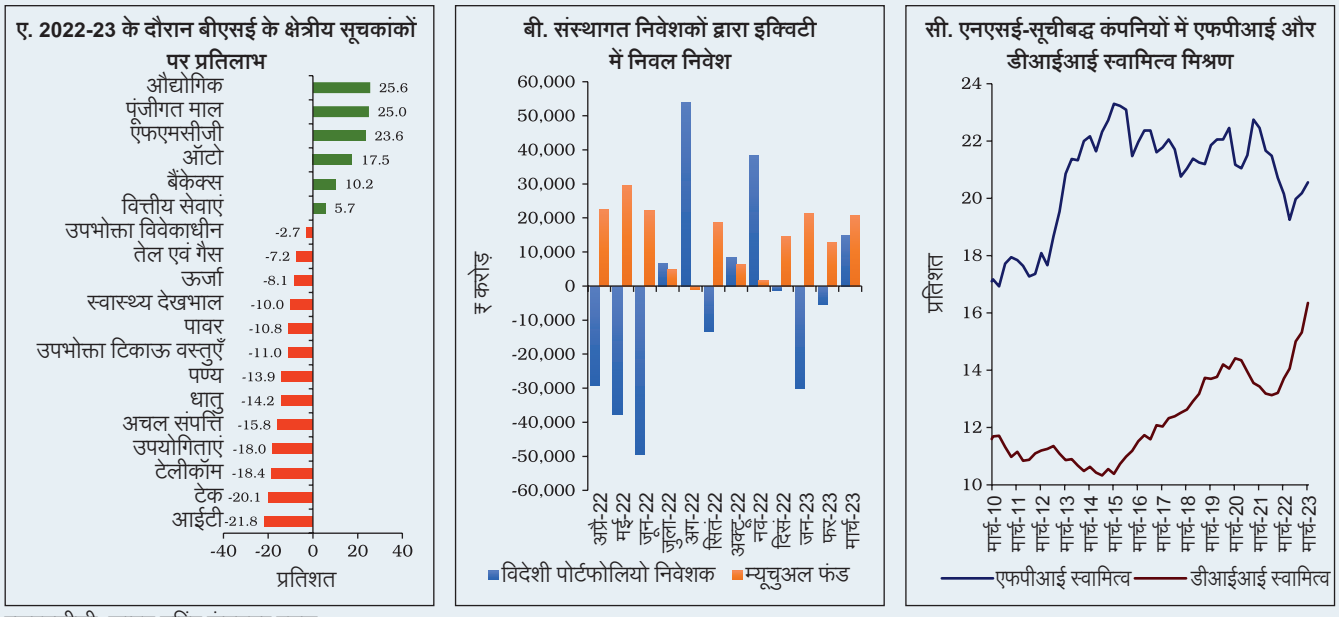

एफएमसीजी: फास्ट मूविंग कंज्यूमर गूड्स
नोट: टेक में मीडिया और प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र शामिल हैं।
स्रोत: एनएसडीएल, सीडीएसएल, प्राइम डाटाबेस और सेबी।

2022 के अंत में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 16.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, भारतीय इक्विटी (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों) में खुदरा और उच्च मालियत व्यक्तियों की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में घटकर 9.4 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में 9.6 प्रतिशत थी।

प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

II.5.29 अस्थिर बाजार स्थितियों के बीच इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में 2022-23 के दौरान निधि जुटाने में कमी देखी गई। 2022-23 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना 50 प्रतिशत से अधिक घटकर ₹0.66 लाख करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹1.39 लाख करोड़ जुटाया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान 165 आईपीओ/एफपीओ निर्गमों के जरिये ₹59,072 करोड़ जुटाए गए, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आईपीओ के जरिए ₹20,557 करोड़ जुटाना भी शामिल है। बीएसई और एनएसई के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) खंड द्वारा 2022-23 में महत्वपूर्ण कर्षण देखा गया, जिसमें 125 एसएमई आईपीओ निर्गमों द्वारा ₹2,333 करोड़ जुटाया गया, जबकि 2021-22 के दौरान 70 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों द्वारा ₹958 करोड़ जुटाया गया था। पिछले वर्ष के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना ₹26,327 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान घटकर ₹6,751 करोड़ रह गया। तरजीही आवंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधन जुटाना 2021-22 के दौरान ₹92,135 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹92,044 करोड़ रह गया (चार्ट II.5.8.ए)।

II.5.30 म्युचुअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए ₹2.47 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान 69.1 प्रतिशत घटकर ₹0.76 लाख करोड़ हो गए। इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं से 2022-23 में ₹1,44,775 करोड़ का निवल संग्रहण हुआ, जबकि पिछले वर्ष में ₹1,54,094 करोड़ का निवल संग्रहण हुआ था। सुनिवेशित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में औसत मासिक योगदान 2022-23 में बढ़कर ₹12,998 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹10,381 करोड़ था। इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड के प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2023 के अंत में 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹15.2 लाख करोड़ हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में ₹13.7 लाख करोड़ थी। हालांकि, ऋण-उन्मुख योजनाओं में निवेशकों द्वारा बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि के बीच कीमत जोखिम से बचने के लिए निकासी के कारण 2022-23 के दौरान ₹2.1 लाख करोड़ का निवल मोचन देखा गया (चार्ट 2.5.8.बी)।

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना

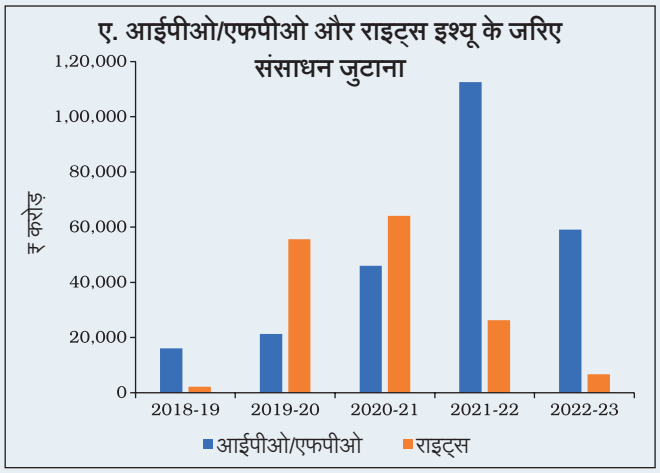

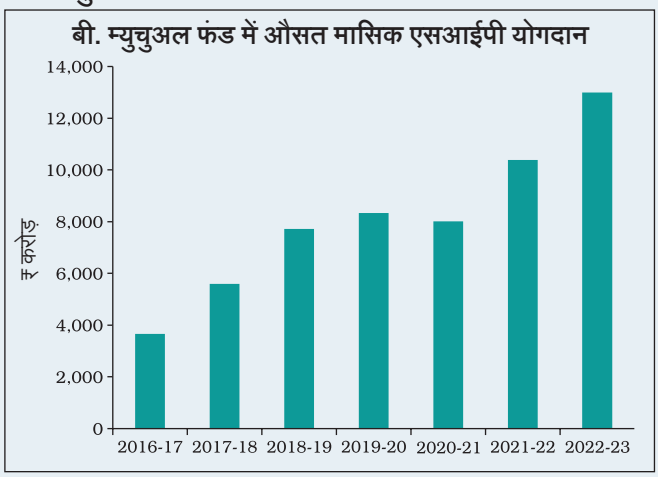

स्रोत: सेबी और एएमएफआई।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.31 विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में अंतर बैंक और व्यापारी क्षेत्र दोनों में कुल कारोबार में वृद्धि हुई।

II.5.32 यूएस फेड द्वारा अपनी मौद्रिक सख्ती को बढ़ाने और जून 2022 में अपनी तुलन-पत्र को कम करना शुरू किये जाने के कारण पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव और यूएस डॉलर के मजबूत होने से उत्पन्न जोखिम रुख के बीच भारतीय रुपया 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान दबाव में रहा। जून 2022 में, यूएस फेड ने 1994 के बाद पहली बार अपनी बेंचमार्क दर में 75 बीपीएस की वृद्धि की। यूएस राजकोष प्रतिफल कई साल के उच्च स्तर पर पहुंचने, इक्विटी में गिरावट और सुरक्षित आश्रय मांग के कारण यूएस डॉलर के बढ़ने से अमेरिकी वित्तीय स्थितियां सख्त हो गईं। इस तिमाही के दौरान यूएस डॉलर सूचकांक में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2016 के बाद से इसकी सबसे अच्छी तिमाही है। तिमाही के दौरान ब्रेंट कच्चा तेल यूएस $112 प्रति बैरल के औसत के साथ ऊंचा और अस्थिर रहा, जिसके कारण भारतीय रुपया दबाव में रहा। इस तिमाही के दौरान एफपीआई द्वारा लगभग यूएस $14 बिलियन की निकासी की, जिसका भारतीय रुपये पर भी प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर, तिमाही के दौरान भारतीय रुपया 4.0 प्रतिशत कमजोर हुआ।

II.5.33 यूएस फेड ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में अवरुद्ध और लगातार उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों में वृद्धि के साथ मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रखा, जिससे आस्ति वर्गों में अस्थिरता बढ़ गई। यूरोप में बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और जैक्सन होल सिम्पोजियम में यूएस फेड की आक्रामक टिप्पणी के बीच यूएस डॉलर ने मजबूत प्रगति की। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करों में भारी कटौती के कारण यूनाइटेड किंगडम की आस्तियों में भारी बिकवाली से ब्रिटिश पाउंड रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया, जबकि यूएस डॉलर सूचकांक 28 सितंबर 2022 को सुरक्षित आश्रय मांग के बीच दो दशक के नए उच्च स्तर 114.78 पर पहुंच गया। भारत के बढ़ते व्यापार घाटे ने रुपये पर और दबाव डाला। हालांकि, इस तिमाही में इक्विटी से संबंधित एफपीआई बहिर्वाह (अक्तूबर 2021 से जून 2022) के लगातार नौ महीनों में ठहराव और कुछ हद तक उलटफेर देखा गया। 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 23.0 प्रतिशत की कमी से रुपये को समर्थन मिला। हालांकि, सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान रुपया 2.9 प्रतिशत कमजोर हुआ।

II.5.34 अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों के आघात सह आंकड़ों और चीन में शून्य-कोविड-19 नीतियों को जारी रखने के बीच 2022-23 की तीसरी छमाही के दौरान यूएस डॉलर की मजबूती जारी रही। मोटे तौर पर अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं के अनुरूप भारतीय रुपया दबाव में आ गया और 20 अक्तूबर 2022 को ₹83.29 प्रति यूएस डालर के नए अंतर्दिवसीय निचले स्तर को छू गया। एमएससीआई उभरती बाजार मुद्रा सूचकांक जून 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, अमेरिका में मुद्रास्फीति ने चरम पर पहुंचने के संकेत दिए जिससे नवंबर 2022 में यूएस डॉलर का मूल्यह्रास हुआ, जिसके कारण फेड पाइवोट की बातचीत तेज हो गई। सीपीआई आंकड़े जारी होने के बाद अमेरिका की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, यूएस फेड ने लगातार चार 75 बीपीएस वृद्धि के बाद दिसंबर 2022 में 50 बीपीएस तक की वृद्धि की अपनी गति को कम कर दिया जिसके कारण जोखिम आस्तियों को राहत मिली। चीन को फिर से खोलने के साथ ही कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण 2022 में किए गए लाभ को छोड़ने से मांग की चिंताएं प्रभावित हुईं जिससे दिसंबर में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आई। रुपया अपने निचले स्तर से उबर गया और शेष तिमाही के लिए काफी हद तक सीमित दायरे में व्यापार किया और 1.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ (चार्ट II.5.9)।

II.5.35 यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि की गति धीमी पड़ने के बाद रुख में सुधार के बीच 2022-23 की चौथी तिमाही में यूएस डॉलर सूचकांक में नरमी जारी रही और यह 2 फरवरी 2023 को 100.82 के निचले स्तर तक पहुँच गया। हालांकि, सख्त श्रम बाजार की स्थिति और मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से अधिक स्थिर रहने एवं दरों में वृद्धि पर फिर

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव

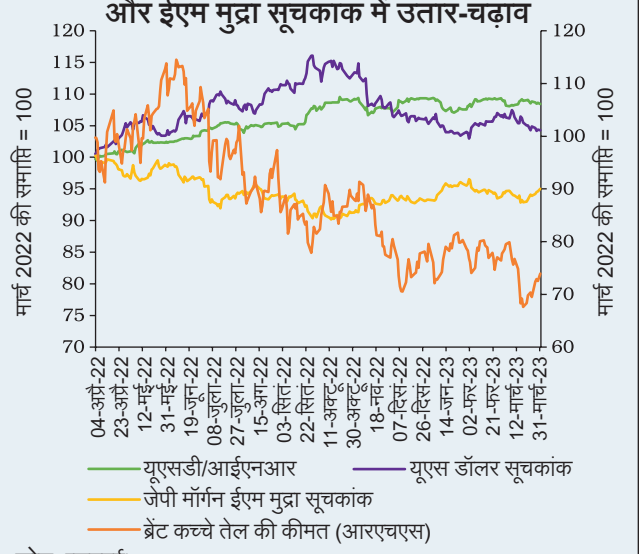

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

से चिंता के कारण यूएस डॉलर सूचकांक मजबूत हुआ। हालांकि, चालू खाते के घाटे में सुधार और ब्रेंट क्रूड की कीमतें सीमित दायरे में रहने से भारतीय रुपये को समर्थन मिला। तिमाही के दौरान, भारतीय रुपया 0.7 प्रतिशत मजबूत हुआ।

II.5.36 2022-23 के दौरान यूएस फेड द्वारा आक्रामक दर वृद्धि के बीच भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों के अंतर को कम करने के कारण वायदा प्रीमियम में गिरावट आई है। 2022-23 के दौरान यूएस फेड द्वारा आक्रामक दर वृद्धि के बीच भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर कम होने के कारण फॉरवर्ड प्रीमियम कम हो गया है। यूएस फेड ने इस अवधि के दौरान दरों में 450 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जबकि रिज़र्व बैंक ने 250 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जिसके कारण वर्ष 2022-23 के दौरान नीतिगत दरों के बीच का अंतर 200 बीपीएस तक कम हो गया।

II.5.37 भारतीय रुपये की सांकेतिक विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के साथ, 40-मुद्रा सांकेतिक/ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर/आरईईआर) 2022-23 के दौरान मूल्यह्रास पूर्वाग्रह के साथ चली गई। औसत आधार पर, वर्ष के दौरान 40-मुद्रा एनईईआर और आरईईआर में क्रमश: 2.0 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

7. निष्कर्ष

II.5.38 वर्ष के दौरान वैश्विक प्रभाव विस्तार के निरंतर प्रभाव के बावजूद घरेलू वित्तीय बाजार का उतार-चढ़ाव व्यवस्थित बना रहा। यूएस डॉलर के लगातार मजबूत होने और यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त किए जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह प्रभावित हुआ, जैसा कि अन्य ईएमई में होता है। घरेलू संस्थागत निवेशकों से निरंतर घरेलू समर्थन के कारण भारतीय इक्विटी बाजार ने अलग होने के संकेत प्रदर्शित किए; आईएनआर ने कई अन्य ईएमई के सापेक्ष कम अस्थिरता के साथ व्यवस्थित समायोजन का प्रदर्शन किया। नीतिगत दरों में संचयी रूप से 250 बीपीएस की सख्ती और समायोजन को वापस लेने की दिशा में नीतिगत रुख में बदलाव के साथ मुद्रा बाजार के रुझान संरेखित हुए। केंद्र और राज्यों के संयुक्त उधारी कार्यक्रम के आकार को लेकर शुरुआती चिंताओं के बावजूद जी-सेक बाजार में प्रतिफल के उतार-चढ़ाव सीमित स्तर पर बने रहे। आने वाले समय में वित्तीय बाजार घरेलू समष्टिआर्थिक परिदृश्य के साथ-साथ अमेरिकी मौद्रिक नीति के भविष्य के मार्ग और यूएस डॉलर की मजबूती से प्रभावित होंगे।

II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद भू-राजनीतिक संघर्ष के बढ़ने से खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसने दुनिया भर की सरकारों को ऊर्जा कर में कटौती, कीमत सब्सिडी और नकद अंतरण सहित लक्षित उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि घरों और व्यवसायों पर जीवन-यापन की लागत संबंधी संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। हालाँकि, 2022 में अधिकांश जी-20 देशों में वित्तीय घाटा और ऋण कम हो गया, जो महामारी से संबंधित उपायों के प्रभाव को दर्शाता है (आईएमएफ, अक्तूबर 2022) [चार्ट II.6.1]। भारत में, 2022-23 के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक लक्षित वित्तीय उपाय किए गए, जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और विकास और निवेश गतिविधि का समर्थन करने के उद्देश्य से, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में बड़ी वृद्धि की गई।

चार्ट II.6.1: जी20 देशों में राजकोषीय शेष और सकल ऋण

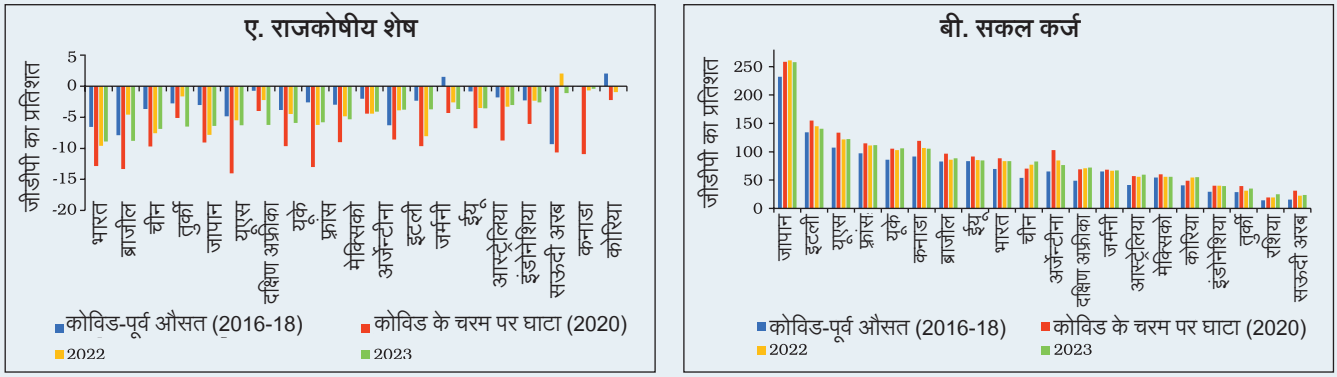

यूएस: संयुक्त राज्य अमेरिका यूके: यूनाइटेड किंगडम ईयू: यूरोपियन संघ

नोट: अन्य देशों के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए डेटा विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ़ से प्राप्त किया गया है। हालांकि, यह केंद्रीय बजट दस्तावेजों या रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि आईएमएफ भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा पद्धतियों और परंपराओं की तुलना में विभिन्न लेखा पद्धतियों और परंपराओं का पालन करता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2023, आईएमएफ।

II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 और 3 में क्रमशः 2022-23 और 2023-24 में केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति प्रस्तुत की गई है। उप-खंड 4 और 5 में 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के वित्त में विकास की प्रगति की रूपरेखा दी गई है। उप-खंड 6 में सामान्य सरकारी वित्त पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणी दी गई है।

2. 2022-23 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.3 केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2021-22 में जीडीपी के 6.75 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के संशोधित अनुमानों (आरई)[32] में जीडीपी का 6.45 प्रतिशत हो गया, जो 6.44 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य के अनुरूप है। तथापि, उनके बजटीय स्तरों से राजस्व और व्यय में काफी अंतर था (चार्ट II.6.2)।

II.6.4 कच्चे तेल और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से बचाने के लिए अप्रैल-मई 2022 के दौरान कई उपायों की घोषणा की- अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी स्वीकृत की गई; पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क क्रमशः ₹8 और ₹6 प्रति लीटर घटाया गया; *प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना* (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर ₹200 की एलपीजी सब्सिडी की

चार्ट II.6.2: 2022-23 में बीई की तुलना में आरई में राजकोषीय विचलन में योगदान

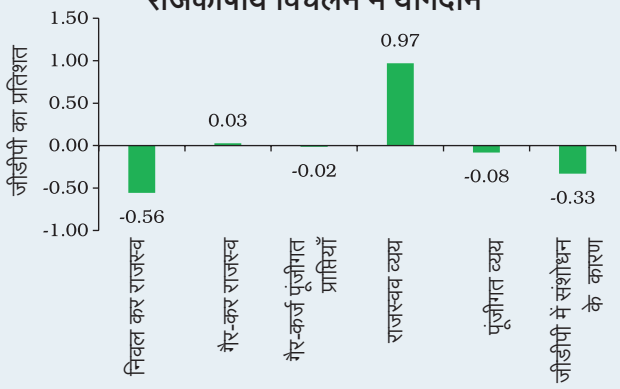

बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।

नोट: ऋणात्मक योगदान, प्राप्तियों में वृद्धि या व्यय में कटौती या जीडीपी में बीई से आरई तक ऊर्ध्वगामी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, धनात्मक योगदान, कम प्राप्तियों या बीई से आरई तक उच्च व्यय को दर्शाता है, क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से गिरावट में योगदान करते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[32] इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 1 का संदर्भ लें।

घोषणा की गई; और प्लास्टिक, लोहा और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में बदलाव किया गया।[33] इसके अलावा, *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* का विस्तार किया गया- चरण VI (अप्रैल-सितंबर 2022) और चरण VII (अक्तूबर-दिसंबर 2022) जबकि 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा की गई। परिणामस्वरूप, सब्सिडी व्यय बजट अनुमानों से ₹2.1 लाख करोड़ अधिक हो गया (खाद्य सब्सिडी ₹0.8 लाख करोड़ बढ़ गई और उर्वरक सब्सिडी ₹1.2 लाख करोड़ बढ़ गई), जिससे 2022-23 (आरई) में राजस्व व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत (₹2.6 लाख करोड़) की वृद्धि हुई।[34]

II.6.5 इस बीच, सरकार पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिबद्ध रही, और इसके परिणामस्वरूप पूंजी परिव्यय (ऋण और अग्रिम घटाकर पूंजीगत व्यय) बजट अनुमानों से लगभग ₹10,000 करोड़ अधिक हो गया। हालांकि, ऋण और अग्रिमों में लगभग ₹32,000 करोड़ की कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के कुल पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत (लगभग ₹22,000 करोड़) की मामूली कमी हुई।

II.6.6 प्राप्तियों के पक्ष में, कर राजस्व मजबूत रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत (₹1.5 लाख करोड़) से बीई को पार कर गया क्योंकि निगम कर, आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह में वृद्धि, कम उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अधिक थी। रिज़र्व बैंक द्वारा कम लाभांश अंतरण के कारण 2022-23 (आरई) में गैर-कर प्राप्तियां बजटीय लक्ष्यों से कम रहीं, लेकिन इस कमी को उच्च ब्याज प्राप्तियों, स्पेक्ट्रम

चार्ट II.6.3: स्पेक्ट्रम राजस्व: वास्तविक बनाम बजट

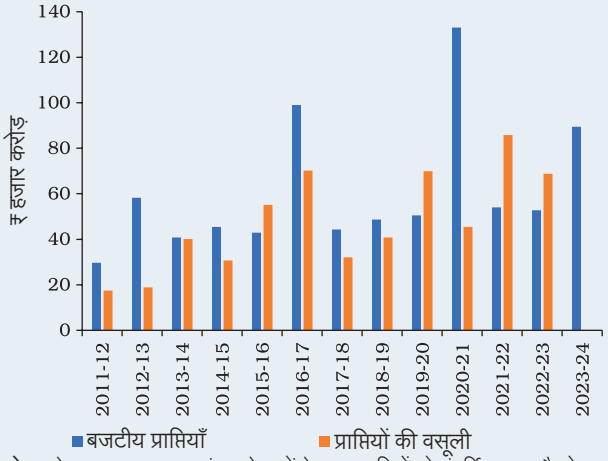

नोट: स्पेक्ट्रम राजस्व 'अन्य संचार सेवाओं' के तहत प्राप्तियों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियों से संबंधित हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

राजस्व और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश अंतरण के कारण जीडीपी के 0.03 प्रतिशत (₹7,900 करोड़) पर सीमित कर दिया गया (चार्ट II.6.3)। 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ₹65,000 करोड़ के बजटीय लक्ष्य की तुलना में विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान ₹50,000 करोड़ है।

3. 2023-24 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.7 2023-24 के लिए, केंद्रीय बजट ने, व्यापक समष्टि-आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए, विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी है। 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, सरकार ने 2023-24 में जीएफडी का बजट जीडीपी[35] का 5.9 प्रतिशत रखा है,

[33] कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाने के साथ-साथ, लौह अयस्क और सान्द्रों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि करते हुए, इस्पात और प्लास्टिक उद्योग के लिए प्रमुख कच्चे माल और निविष्टियों पर आयात शुल्क घटाया गया।

[34] वित्तीय वर्ष 2022-23 (13 मार्च, 2023 को प्रस्तावित) के लिए अनुदान की पूरक मांग के दूसरे बैच में ₹1.48 लाख करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल है (जिसमें से राजस्व व्यय ₹1.44 लाख करोड़ है और पूंजीगत व्यय ₹3,755 करोड़ है।)

[35] 2023-24 (बीई) के लिए सांकेतिक जीडीपी, पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए, ₹3,01,75,065 करोड़ अनुमानित की गई है (अर्थात, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2023 को जारी 2022-23 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार ₹2,73,07,751 करोड़)।

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन

जीडीपी का प्रतिशत

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर-कर्ज प्राप्तियाँ	11.0	9.7	9.5	9.1	9.4	9.1	8.8	8.7	8.5	9.4	8.9	8.9	9.0
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.6	11.1	11.2	11.0	10.0	10.2	11.5	10.7	11.2	11.1
ए) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.4	5.5	5.9	6.0	5.2	4.8	6.0	5.5	6.1	6.0
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	5.2	5.6	5.4	5.0	4.8	5.5	5.5	5.2	5.1	5.1
III. निवल कर राजस्व	7.9	7.6	7.3	6.9	7.2	7.3	7.0	6.7	7.2	7.7	7.5	7.7	7.7
IV. गैर-कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.9	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
VI. कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.0	12.8	12.5	12.2	13.4	17.7	16.2	15.3	15.4	14.9
VII. राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.2	11.0	11.0	10.6	11.7	15.5	13.6	12.4	12.7	11.6
VIII. पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	2.1	2.5	2.9	2.7	3.3
IX. राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	7.3	4.4	3.8	4.1	2.9
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	9.2	6.8	6.4	6.5	5.9

बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।

नोट: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, 2022-23 (आरई) के लिए नॉमिनल जीडीपी 28 फरवरी, 2023 को जारी एसएई के अनुसार है। इसके मद्देनजर, इस खंड में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिये गए राजकोषीय संकेतक, केंद्रीय बजट दस्तावेजों में दी गई रिपोर्ट से भिन्न हो सकते हैं। कृपया इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 1 का संदर्भ भी लें।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

जो 2022-23 (आरई) से 53 आधार अंकों का सुदृढ़ीकरण है। यह सुदृढ़ीकरण राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत पर नियंत्रित करके प्राप्त करने का इरादा है, तथापि पूंजीगत व्यय का बजट, 2010-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है (सारणी II.6.1)।

II.6.8 व्यय के मोर्चे पर, 2023-24 में यूरिया की कीमतों में नरमी और महामारी से संबंधित खाद्य सब्सिडी को कम करने के कारण, सब्सिडी पर खर्च को वापस लेने की परिकल्पना की गई है। 2023-24 (बीई) में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में क्रमशः 31.3 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है, जिससे राजस्व व्यय वृद्धि 1.2 प्रतिशत पर सीमित हो जाएगी। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सड़क और रेलवे मंत्रालयों का बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट II.6.4)। पूंजीगत व्यय के तहत, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को ₹1.3 लाख करोड़ के बढ़े हुए आबंटन के साथ, 2023-24 (बीई) तक बढ़ा दिया गया है। ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय, यानी पूंजी परिव्यय 2023-24 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जो उदारीकरण के बाद की अवधि में सबसे

चार्ट II.6.4: 2023-24 में पूंजीगत व्यय का मंत्रालय-वार विभाजन (कुल का प्रतिशत)

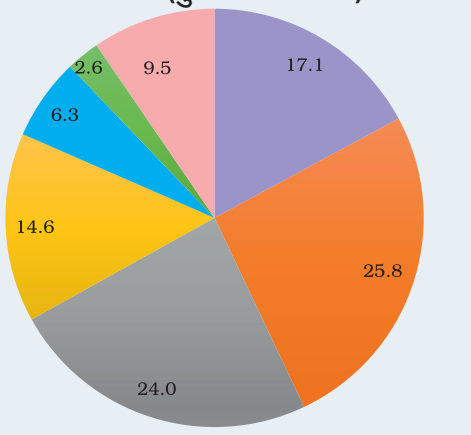

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज

चार्ट II.6.5: व्यय की गुणवत्ता

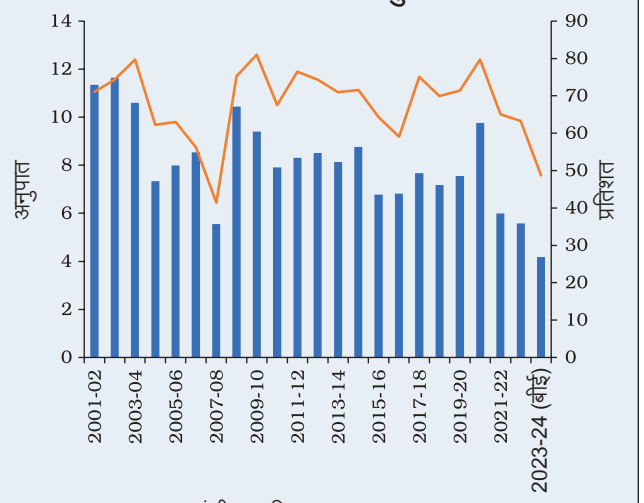

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज

अधिक है, और यह खर्च की गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दर्शाता है (चार्ट) II.6.5)।

II.6.9 प्राप्तियों के पक्ष में, सकल कर राजस्व में 0.96 की बजटीय उछाल के साथ, 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जो प्रवृत्ति स्तर (2010-11 से 2018-19 तक औसत द्वारा अनुमानित) के करीब है [सारणी II.6.2]। अनुपालन में सुधार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है और 2023-24 में इसे जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर बजटीकृत किया गया है, जो जीएसटी की शुरुआत के बाद से उच्चतम है (चार्ट II.6.6)। गैर-कर प्राप्तियों में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि विनिवेश लक्ष्य ₹51,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।

II.6.10 केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रतिबंधित बाजार उधार की परिकल्पना की गई है, जो निजी निवेश के लिए जगह खोलेगा। 2023-24 के लिए सकल बाजार उधार ₹15.43 लाख करोड़ (जीडीपी का 5.1 प्रतिशत) आंका गया है, जबकि 2022-23 आरई में यह ₹14.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 5.2 प्रतिशत) था। 2023-24 (बीई) में जीएफडी (66.1 प्रतिशत) के वित्तपोषण

सारणी II.6.2 : कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 to 2018-19)	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	0.86	0.77	0.96
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.22	1.08	0.96
(i) कॉर्पोरेशन कर	0.92	1.20	1.09	0.96
(ii) आय कर	1.27	1.28	1.09	0.96
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.51	0.44	0.95
(i) जीएसटी	-	1.40	1.40	1.10
(ii) सीमा शुल्क	0.31	1.14	0.32	1.01
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	-1.34	-1.19	0.54

-: अनुपलब्ध जीएसटी : वस्तु एवं सेवा कर

नोट: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। 2022-23 (बीई) की गणना 2021-22 (आरई) के आधार पर की गयी है।

स्रोत: विभिन्न वर्षों के यूनियन बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणना

का मुख्य स्रोत बाजार उधार (निवल) हैं, इसके बाद छोटी बचत (26.4 प्रतिशत) का स्थान आता है [चार्ट II.6.7]। इसके अलावा, नकद शेष राशियों का एक कोष बजटीकृत किया गया है, जो भारत सरकार को एक वित्तपोषण बफर प्रदान करता है।

चार्ट II.6.6: जीएसटी संग्रह

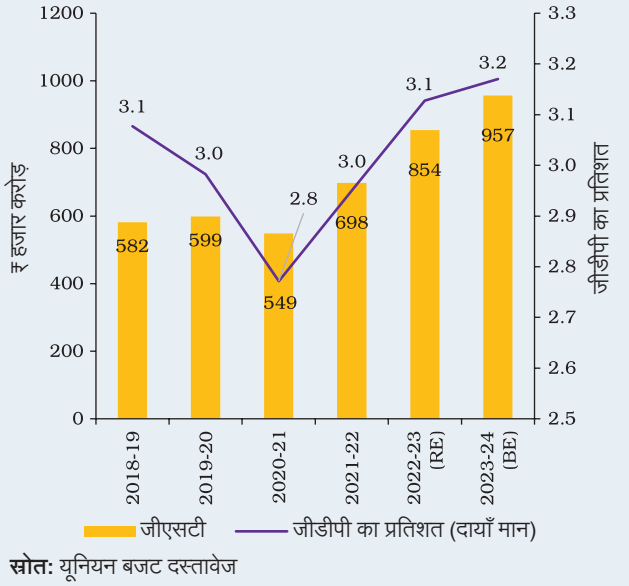

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज

चार्ट II.6.7: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

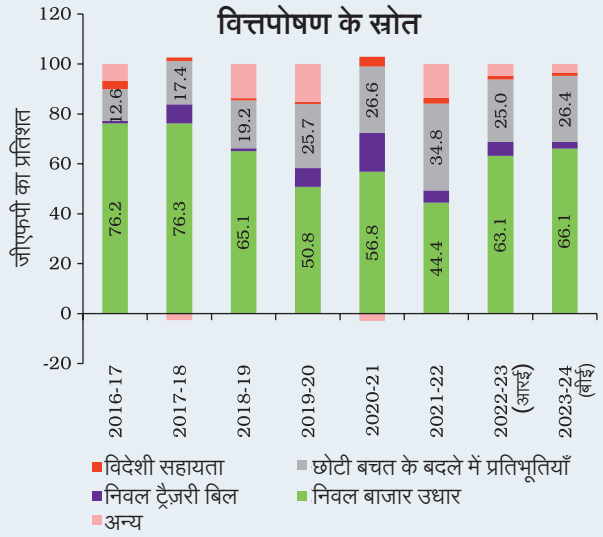

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज

4. 2022-23 में राज्य वित्त

II.6.11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत के समेकित जीएफडी के लिए बजट रखा है (सारणी II.6.3)। यह अनुपात 2021-22 (आरई) के अनुपात से कम है और केंद्र द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य के भीतर है। राज्यों ने मुख्य रूप से राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी), उत्पाद शुल्क और बिक्री कर/वैट में उच्च राजस्व संग्रह के लिए बजट योजना तैयार की है। राज्यों के राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय में भी वृद्धि की बजट योजना है।

II.6.12 फरवरी 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान राज्यों का जीएफडी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा अधिक था। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों ने 14.1 प्रतिशत की सुदृढ़ वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से मजबूत कर संग्रह द्वारा संचालित थी। नवंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने ₹0.58 लाख करोड़ के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले ₹1.16 लाख करोड़ की कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं। केंद्र ने अप्रैल-जून 2022 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ₹0.17 लाख करोड़ भी जारी किए। कुल मिलाकर, यद्यपि

सारणी II.6.3: राज्यों/यूटी की राजकोषीय स्थिति

(₹ लाख करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	26.2 (13.9)	26.7 (13.3)	25.9 (13.1)	33.5 (14.2)	38.6 (14.9)
II. पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.42 (0.2)	0.57 (0.3)	0.23 (0.1)	0.27 (0.1)	0.2 (0.1)
III. राजस्व व्यय	26.4 (14.0)	27.9 (13.9)	29.6 (14.9)	35.7 (15.1)	39.4 (15.3)
IV. पूंजीगत व्यय	4.9 (2.6)	4.6 (2.3)	4.6 (2.3)	6.9 (2.9)	8.2 (3.2)
ए. पूंजीगत परिव्यय	4.4 (2.3)	4.2 (2.1)	4.1 (2.1)	6.3 (2.7)	7.5 (2.9)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.5 (0.2)	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.6 (0.3)	0.6 (0.3)
V. राजकोषीय घाटा	4.6 (2.4)	5.2 (2.6)	8.0 (4.1)	8.8 (3.7)	8.8 (3.4)
VI. राजस्व घाटा	0.2 (0.1)	1.2 (0.6)	3.7 (1.9)	2.2 (0.9)	0.8 (0.3)

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी के बजट दस्तावेज

अप्रैल-फरवरी, 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि एक साल पहले की तुलना में अधिक थी, तथापि केंद्र द्वारा राज्यों के संसाधनों में 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि के बावजूद, कैपेक्स में वृद्धि कम है।

5. 2023-24 में राज्य वित्त

II.6.13 केंद्र ने 2023-24 के लिए राज्यों के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा है। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2023-24 के लिए सकल राजकोषीय घाटा उनके संचयी जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो केंद्र के लक्ष्य के भीतर ही है (सारणी II.6.4)। मुख्य रूप से कर हस्तांतरण में वृद्धि और कैपेक्स के लिए राज्यों को विशेष सहायता (ऋण के रूप में) के आबंटन में वृद्धि के कारण, 2023-24 (बीई) में राज्यों को सकल अंतरण बढ़ने का अनुमान है। मुख्य रूप से हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटा अनुदानों के तहत कम अंतरणों के कारण, वित्त आयोग के अनुदानों में 2023-24

सारणी II.6.4: राज्य सरकार वित्त 2023-43*: प्रमुख संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.4	0.6	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	3.5	3.2
प्राथमिक घाटा	0.5	1.4	1.1

*डेटा छब्बीस राज्यों/यूटी से संबन्धित है जिन्होंने 2023-24 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

में गिरावट आने की उम्मीद है, जबकि स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानांतरण में तेज वृद्धि देखी गई है।

II.6.14 बुनियादी ढांचे में राज्यों के निवेश को बढ़ाने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र ने, ₹1.3 लाख करोड़ के बढ़े हुए आबंटन के साथ, राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है। कर्ज की पूरी राशि 2023-24 में खर्च करनी होगी। इन ऋणों का एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर निर्भर होगा। परिव्यय का एक हिस्सा पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने, शहरी नियोजन सुधारों और कार्यों, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधारों, पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मॉल[36], बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालयों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए भी आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से, शहरों को नगरपालिका बॉण्डों के लिए अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण में कमी के माध्यम से की जाएगी। फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.6.15 वर्ष 2022-23 (बीई) में, सामान्य सरकारी घाटा और कर्ज क्रमश: जीडीपी के 9.4 प्रतिशत और 86.5 प्रतिशत पर आ गए, जो 2020-21 में क्रमश: 13.1 प्रतिशत और 89.4 प्रतिशत के चरम स्तर से थे (परिशिष्ट सारणी 7)।

7. निष्कर्ष

II.6.16 विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध होते हुए, सरकार ने संवर्धित पूंजीगत व्यय के माध्यम से निवेश चक्र में पुनरुद्धार को आगे बढ़ाया है, क्योंकि सरकार ने निजी निवेश जुटाने (क्राउडिंग-इन) और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने में इसके गुणक प्रभावों को पहचाना है। भविष्य में, नीतिगत बफर के पुनर्निर्माण और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। डिजिटीकरण पर निरंतर जोर अर्थव्यवस्था के अधिक सुदृढ़ीकरण और इस प्रकार उच्च कर आधार बनाने में सहायता कर सकता है और विकासात्मक व्यय करने के लिए आवश्यक संसाधनों का सृजन कर सकता है।

II.7 बाह्य क्षेत्र

II.7.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद बिगड़ती वैश्विक समष्टि वित्तीय स्थिति ने व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रभावित किया जिससे भारत का बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। घरेलू आर्थिक सुधार ने आयात मांग को उच्च बनाए रखा लेकिन वैश्विक मांग में मंदी ने भारत के निर्यात को प्रभावित किया। इन दोनों ने रिकॉर्ड उच्च वैश्विक पण्य कीमतों से जुड़े प्रतिकूल निवल व्यापार की शर्तों के आघातों के साथ वर्ष के दौरान भारत के पण्य व्यापार घाटे में वृद्धि की। सेवा निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि और उच्च विप्रेषण प्राप्तियों के बावजूद माल व्यापार घाटे के बढ़ने और प्राथमिक आय लेखे

[36] यह राज्य के 'एक जिला, एक उत्पाद', भौगोलिक संकेतक उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह और अन्य राज्यों के समान उत्पादों के लिए स्थान भी उपलब्ध कराएगा और इनको बढ़ावा भी देगा।

पर अधिक खर्च के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष के दौरान बढ़ गया, जो दूसरी तिमाही में चरम पर पहुंच गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बैंकिंग पूंजी के वर्चस्व वाले निवल पूंजी अंतर्वाह ने चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण किया, लेकिन वर्ष के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार को कम करना पड़ा। मुख्य रूप से गैर-डॉलर आरक्षित मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती वृद्धि के कारण मूल्यांकन हानि, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का एक प्रमुख हिस्सा थी। फिर भी, बाह्य क्षेत्र ने वैश्विक प्रभाव-विस्तार के समक्ष आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया एवं भारत के सुभेद्यता संकेतक अपने समकक्ष उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।

II.7.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है जिसके कारण बाहरी संतुलन में ये बदलाव हुए। इसके बाद उप-खंड 3 और 4 में क्रमशः पण्य व्यापार और अदृश्य मदों पर चर्चा की गई है। उप- खंड 5 पूंजी प्रवाह का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बाहरी सुभेद्यता संकेतकों का मूल्यांकन उप- खंड 6 में दिया गया है जिसके बाद निष्कर्ष टिप्पणियाँ दी गई हैं।

2. वैश्विक आर्थिक स्थिति

II.7.3 यूक्रेन में युद्ध शुरूआती अनुमान से अधिक समय तक जारी रहने और अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ, 2022-23 के दौरान वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। परिणामस्वरूप, आईएमएफ ने अक्तूबर 2021 और अक्तूबर 2022 के बीच लगातार दौर में 2022 के लिए अपने वैश्विक जीडीपी और व्यापार वृद्धि अनुमानों को संशोधित किया (चार्ट II.7.1ए)। वैश्विक वित्तीय स्थिति सख्त होती गई, जो वैश्विक प्रभाव विस्तार और देश-विशिष्ट कारकों के माहौल में जोखिमों के पुनर्मूल्यांकन के बीच बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की सख्ती को दर्शाती है, जिससे सुरक्षित निवेश के लिए होड़ शुरू हो गई है और अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती आई है। आसन्न वैश्विक मंदी की शुरुआती आशंकाओं और हार्ड लैंडिंग की संभावना के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, जिसके कारण आईएमएफ ने जनवरी 2023 में अपने वैश्विक विकास अनुमान को 3.4 प्रतिशत तक संशोधित किया, जो बाद में अपरिवर्तित रहा। इसी तरह, आईएमएफ द्वारा वैश्विक व्यापार वृद्धि के अनुमान को भी अक्तूबर 2022 में 4.3 प्रतिशत से अप्रैल 2023 में 5.1 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था (चार्ट II.7.1बी)।

चार्ट II.7.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार* मात्रा वृद्धि

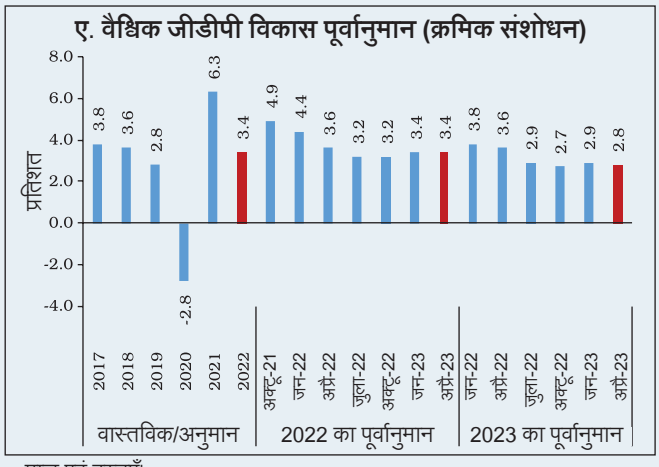

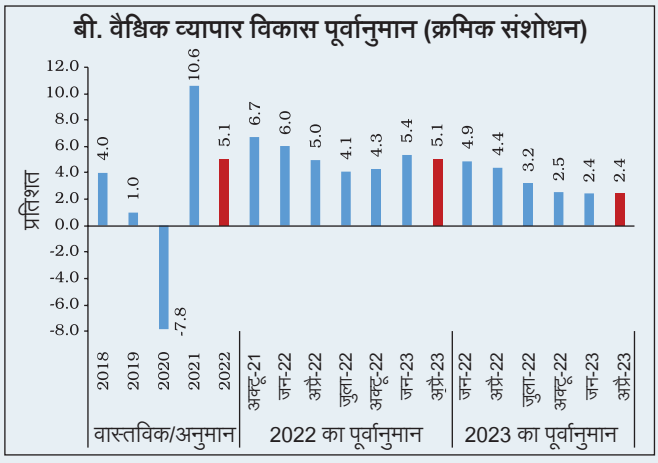

*: माल एवं वस्तुएँ।
स्त्रोत: आईएमएफ।

चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह

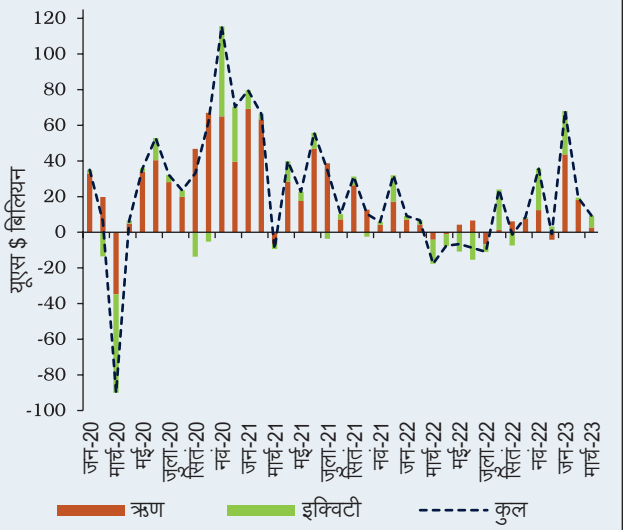

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान।

चार्ट II.7.3: वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन*

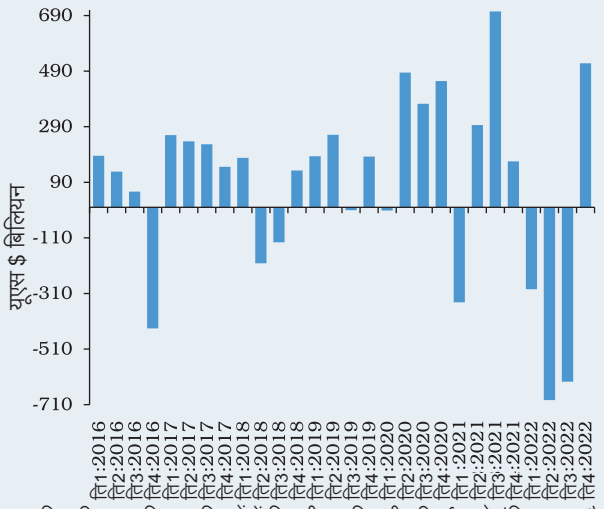

*: आधिकारिक आरक्षित आस्तियों में तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन को इंगित करता है।

स्रोत: आईएमएफ।

II.7.4 बाजारों पर जोखिम-विमुख रुख हावी होने के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो बहिर्वाह का अनुभव किया (चार्ट II.7.2)। विश्व विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई, जो विदेशी मुद्रा बाजार पर केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेपों के प्रभाव के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर, प्रमुख आरक्षित मुद्रा की वृद्धि के कारण मूल्यांकन हानि को दर्शाता है (चार्ट II.7.3)।

3. पण्य व्यापार

II.7.5 वैश्विक मंदी ने भारत के व्यापारिक निर्यात को कम कर दिया है। फिर भी, 2022-23 में 450.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष के दौरान दर्ज 44.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान 714.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के पण्य वस्तु आयात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी II.7.1)।

II.7.6 2022-23 में गैर-तेल निर्यात में मामूली गिरावट आने के कारण निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक पेट्रोलियम उत्पाद थे। गैर-तेल उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने निर्यात को बढ़ावा दिया जबकि इंजीनियरिंग सामान, सूती धागे / कपड़े, प्लास्टिक और लिनोलियम, लौह अयस्क, रत्न और आभूषण ने समग्र निर्यात प्रदर्शन को कम किया (चार्ट II.7.4)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य व्यापार

	यूएस $ बिलियन में मूल्य				विकास दर (वर्ष-दर-वर्ष)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	80.9	51.5	95.5	121.0	-1.4	-36.4	85.7	26.6
ति2	78.3	74.2	102.7	110.7	-3.9	-5.2	38.5	7.8
ति3	79.1	75.8	106.8	104.6	-1.9	-4.2	41.0	-2.1
ति4	75.1	90.4	117.0	114.1	-12.7	20.4	29.3	-2.4
वार्षिक	313.4	291.8	422.0	450.4	-5.1	-6.9	44.6	6.7
आयात								
ति1	130.1	61.3	127.0	183.5	1.1	-52.9	107.2	44.5
ति2	118.0	90.7	147.5	189.0	-11.3	-23.1	62.7	28.1
ति3	116.1	110.8	167.0	176.1	-11.2	-4.6	50.7	5.4
ति4	110.5	131.7	171.6	165.4	-9.2	19.1	30.3	-3.6
वार्षिक	474.7	394.4	613.1	714.0	-7.7	-16.9	55.4	16.5
व्यापार शेष								
ति1	-49.2	-9.8	-31.4	-62.6				
ति2	-39.7	-16.5	-44.8	-78.3				
ति3	-37.0	-35.1	-60.2	-71.5				
ति4	-35.4	-41.2	-54.6	-51.3				
वार्षिक	-161.3	-102.6	-191.0	-263.6				

स्रोत: डीजीसीआई&एस और पीआईबी।

II.7.7 मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम निर्यात में 2022-23 के दौरान 44.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि निर्यात की मात्रा में 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण निर्यातकों के लाभ को दर्शाता है (चार्ट II.7.5ए)। रिफ़ाइंड तेल निर्यात आय में विशेष रूप से यूरोपीय बाजार से वृद्धि हुई (चार्ट II.7.5बी)। चूंकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण निर्यात तेजी से लाभकारी हो गया, सरकार ने घरेलू सकल मांग की स्थिति में सुधार को देखते हुए, घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर उपकर लगाया। इसकी पाक्षिक समीक्षा की गई है और 19 अप्रैल 2023 से प्रभावी नवीनतम संशोधन के अनुसार, किसी भी रिफ़ाइंड उत्पाद पर कोई निर्यात उपकर नहीं है।

II.7.8 2022-23 के दौरान भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 107.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि लोहा और इस्पात को छोड़कर, इंजीनियरिंग निर्यात में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.7.6ए)। पण्य-वार, अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी और मई 2022 में इस्पात पर निर्यात शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप 2022-23 के दौरान लोहा और इस्पात (जो कुल इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा है) में 41.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इस्पात पर यह निर्यात शुल्क नवंबर 2022 में हटा दिया गया था।

चार्ट II.7.4: निर्यात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2021-22 की तुलना में 2022-23)

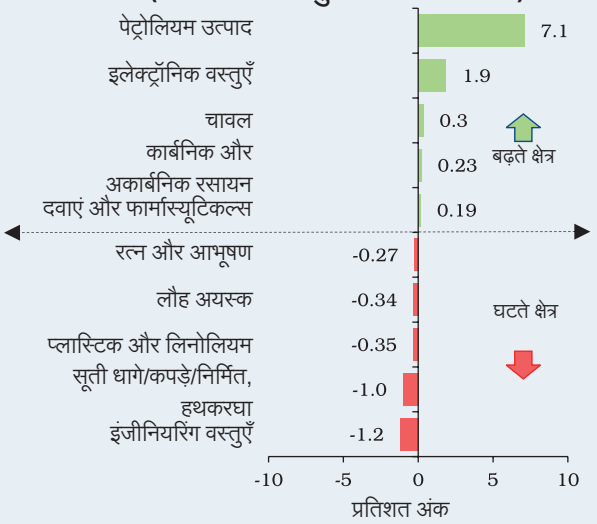

स्रोत: डीजीसीआई&एस

II.7.9 भारत से इंजीनियरिंग निर्यात के प्रमुख बाजारों में अमेरिका, चीन, यूएई, इटली और जर्मनी शामिल हैं। वैश्विक मांग में कमी ने इनमें से कुछ देशों में भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित किया (चार्ट II.7.6बी)। मजबूत अमेरिकी डॉलर और इंजीनियरिंग वस्तुओं की उच्च आयात सामग्री ने भी गिरावट में योगदान दिया।

चार्ट II.7.5 : भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

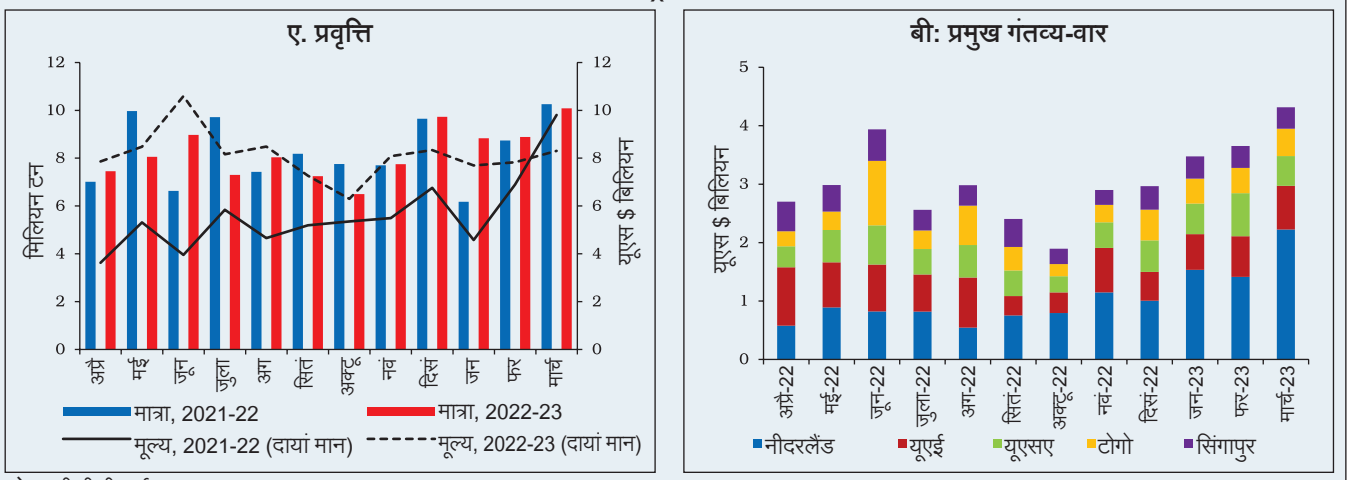

स्रोत: डीजीसीआई&एस

चार्ट II.7.6: भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

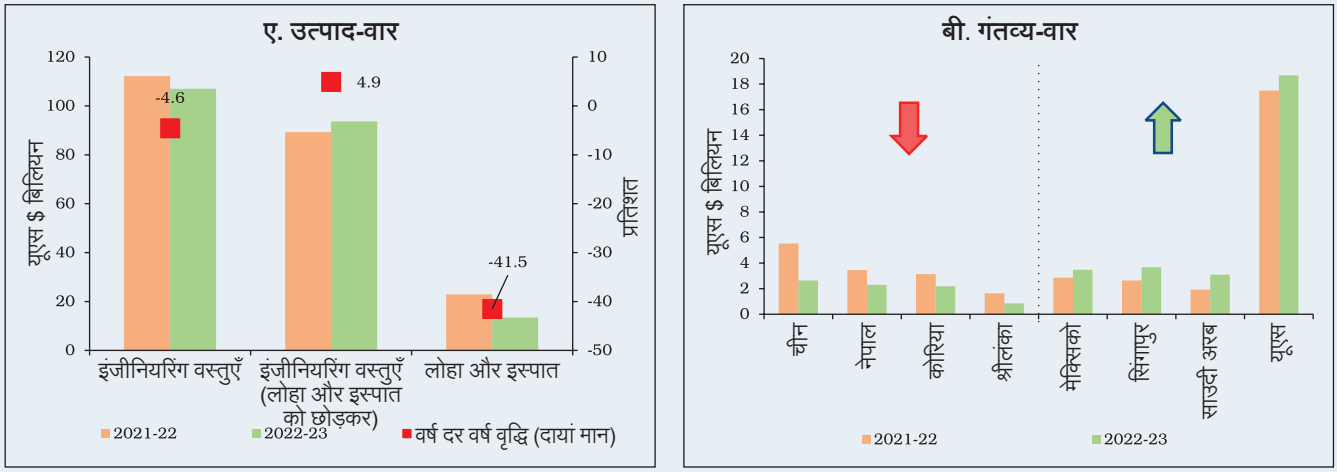

स्रोत: डीजीसीआई&एस

II.7.10 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, वैश्विक इस्पात मांग 2023 में 2.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2022 में इसमें 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। भारत में स्टील की मांग 7.3 फीसदी और चीन में 2.0 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है और यूरो एरिया और यूके में 0.4 फीसदी की गिरावट की उम्मीद है।[37] निर्यातित उत्पाद (आरओडीटीईपी) योजना पर शुल्कों और करों की छूट का विस्तार, लोहे और इस्पात की वस्तुओं के साथ-साथ, फार्मास्यूटिकल्स और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के लिए भी कर देने से, ये उत्पाद भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।

II.7.11 2022-23 के दौरान बढ़ती इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत के चलते जैविक और अकार्बनिक रासायनिक निर्यात 3.3 प्रतिशत बढ़कर 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय रसायन उद्योग में, उद्योगकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही चीन प्लस वन कार्यनीति से लाभ उठाने की क्षमता है।

II.7.12 2022-23 के दौरान 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 50.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा इसी अवधि के दौरान दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में 74.2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था (चार्ट II.7.7)। मोबाइल विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने स्मार्टफोन आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत में स्थानांतरण में मदद की है, स्थानीय मूल्य वर्धन में वृद्धि की है और वैश्विक निर्माताओं को सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 2020-21 से स्मार्टफोन पर

चार्ट II.7.7: भारत के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात की संरचना

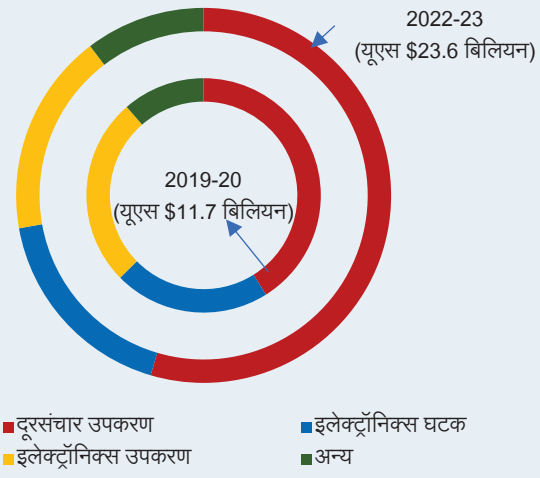

स्रोत: डीजीसीआई&एस

[37] शॉर्ट रेंज आउटलुक, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, अप्रैल 2023।

चार्ट II.7.8: सूती धागे/कपड़ों/मेड-अप्स आदि का निर्यात

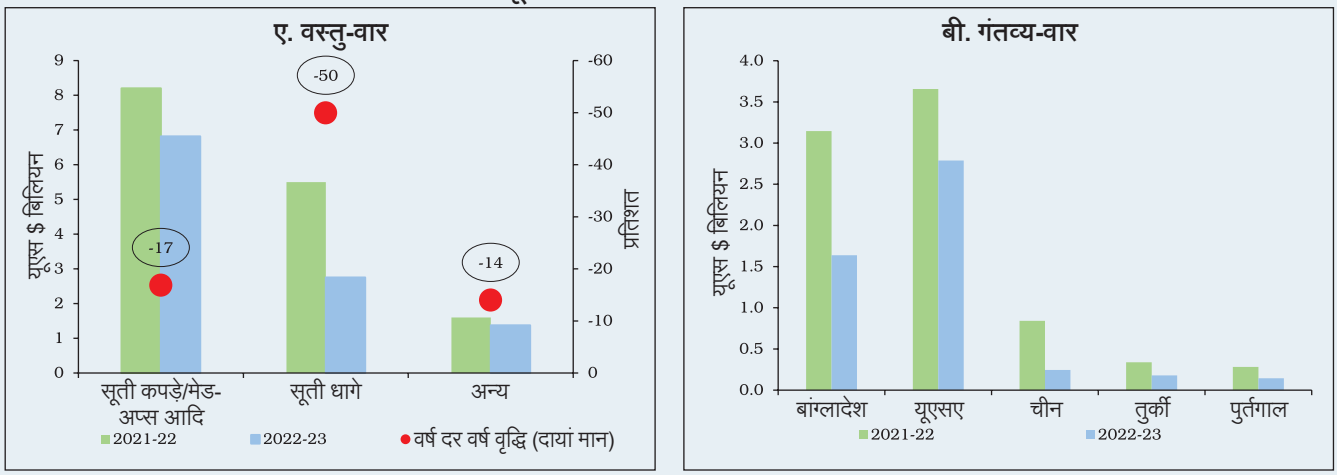

स्रोत: डीजीसीआई&एस

22.0 प्रतिशत का आयात शुल्क और अन्य घटकों पर टैरिफ लगाया गया है।

II.7.13 2022-23 के दौरान सूती धागे/कपड़े आदि के निर्यात में 28.4 प्रतिशत की गिरावट आई। वस्तु-वार, सूती धागे का निर्यात एक साल पहले के आईआर स्तर से घटकर लगभग आधा रह गया (चार्ट II.7.8ए)। बांग्लादेश को सूती धागे/कपड़े *आदि* का निर्यात, जो अकेले 2021-22 में भारत के सूती धागे के निर्यात का 42.0 प्रतिशत था, 2022-23 में लगभग आधा रह गया। मजबूत डॉलर और बिजली संकट के चलते क्षमता में कमी और कपड़ा निर्माताओं द्वारा पुराने धागे के भंडारण के कारण बांग्लादेश, जो निवल कपास आयातक है, में कपास के आयात पर असर पड़ा। कोविड-19 लॉकडाउन और वस्त्र मांग में कमी के कारण, चीन के निर्यात में भी काफी गिरावट आई (चार्ट II.7.8बी)। इसके अलावा, सस्ते घरेलू कच्चे माल की कमी के बीच, आयातित कपास पर 11.0 प्रतिशत के शुल्क ने बुनकरों और निर्माताओं के मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे सूती कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई।

II.7.14 द्विपक्षीय/क्षेत्रीय स्तर पर भारत के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, 2022-23 के दौरान यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार समझौते लागू हुए। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा और गल्फ़ कोआपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के साथ समझौतों के लिए बातचीत चल रही है। 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे। अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था (बॉक्स II.7.1)।

बॉक्स II.7.1
प्रतिकूल वैश्विक परिवेश में भारत का निर्यात

वैश्विक व्यापार के भविष्य के लिए दो प्रमुख खतरे बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और संरक्षणवादी नीतियां (आईएमएफ, 2023) हैं। विखंडन और संरक्षणवाद की ओर बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति ने बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और व्यापार नीति अनिश्चितता में योगदान दिया है (कैलडारा और लाको-विएलो, 2022) [चार्ट 1]।

वैश्विक व्यापार पर भू-राजनीतिक जोखिमों और व्यापार नीति अनिश्चितताओं के प्रभाव का विश्लेषण 43 देशों के एक पैनल का उपयोग करके किया जाता है जिसके लिए सूचकांक उपलब्ध हैं। प्रतिदर्श अवधि 2010 की दूसरी तिमाही से 2022 की दूसरी तिमाही के लिए निम्नलिखित रिग्रेशन का अनुमान लगाया गया है:

$$\log(Export)_{it} = \alpha_i + \beta * GPRI_{it} + \gamma * log(TPU)_t + \theta * log(Global\ GDP)_t + \delta_{1-4} + \epsilon_{it}$$

(जारी)

चार्ट 1: वैश्विक व्यापार के प्रति जोखिम

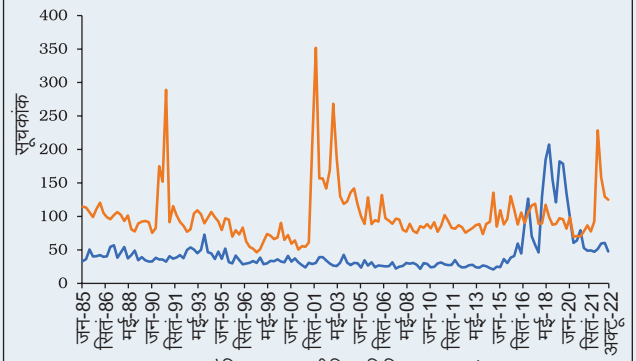

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट 2: भारत की पण्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में रुझान*

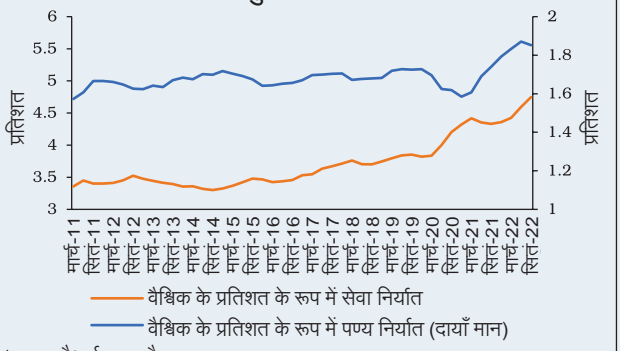

*: चार चौथाई चल औसत।
^: वैश्विक सेवा निर्यात 96 देशों का कुल सेवा निर्यात है, जिसके लिए आंकड़े पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है।
स्रोत : डबल्यूटीओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जहां $Export_{it}$ तिमाही t में i देश की सेवा/वस्तु/कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं (सीबीएस)[38] का निर्यात है; $GPRI_{it}$ तिमाही t में i देश की देश-विशिष्ट त्रैमासिक भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक है; और त्रैमासिक वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक है। वैश्विक जीडीपी और तिमाही निश्चित प्रभाव भी नियंत्रण चर के रूप में जोड़े जाते हैं।

परिणाम बताते हैं कि व्यापार नीति अनिश्चितता का पण्य व्यापार पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन समग्र सेवा व्यापार और सीबीएस निर्यात पर भी सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (सारणी 1)। चर में से किसी पर भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

इस अभ्यास से मिले अनुभवजन्य निष्कर्ष, भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में देखे जा रहे विरोधाभासी पैटर्न का समर्थन करते हैं। जहां एक ओर, वैश्विक व्यापार के प्रतिशत के रूप में भारत का पण्य निर्यात पिछले एक दशक में कमोबेश स्थिर रहा है, वहीं दूसरी ओर, इसका सेवा निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जो ज्यादातर सीबीएस निर्यात से प्रेरित है (चार्ट 2)।

सारणी 1: निर्यात पर भू-राजनीतिक और व्यापार अनिश्चितता का प्रभाव

(आश्रित चर: देश-स्तरीय निर्यात)

विवरणात्मक चर	सेवा निर्यात समग्र	कम्प्यूटर और कारोबार सेवा निर्यात	पण्य निर्यात
1	2	3	4
भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक ($GPRI_{it}$)	0.025 (0.042)	0.036 (0.029)	-0.041 (0.034)
व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक ($लॉग\ TPU_t$)	0.039** (0.019)	0.034** (0.015)	-0.085*** (0.018)
वैश्विक जीडीपी ($लॉग\ ग्लोबल\ GDP_t$)	0.448** (0.166)	1.632*** (0.168)	0.922*** (0.110)
प्रेक्षणों की संख्या	2074	1950	2107

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्ता स्तर दर्शाते हैं।
नोट : कोष्ठक में क्लस्टर रोबस्ट मानक त्रुटियाँ दी गई हैं। मॉडल तिमाही-नियत प्रभावों और देश-नियत प्रभावों का नियंत्रण करते हैं।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. कल्डरा, डी., और लाकोविल्लो, एम. (2022), 'मेजरिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क', अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, अप्रैल, 1194-1225
2. कल्डरा, डी., लाकोविल्लो, एम. मोल्लिगो, पी., प्रेस्टीपिनो, ए., और राफ्फो, ए. (2020), 'द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेन्टी', जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 109
3. आईएमएफ (2023), 'जियो-इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म', *स्टाफ डिस्कशन नोट एसडीएन/2023/001*, जनवरी, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी।

[38] कंप्यूटर और व्यापार सेवा श्रेणी के लिए निर्यात के आंकड़े डब्ल्यूटीओ सेवा व्यापार डेटाबेस के तहत निम्नलिखित दो उप-श्रेणियों को जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं: ए) दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं; और बी) अन्य व्यावसायिक सेवाएं।

चार्ट II.7.9: भारत का व्यापारिक आयात

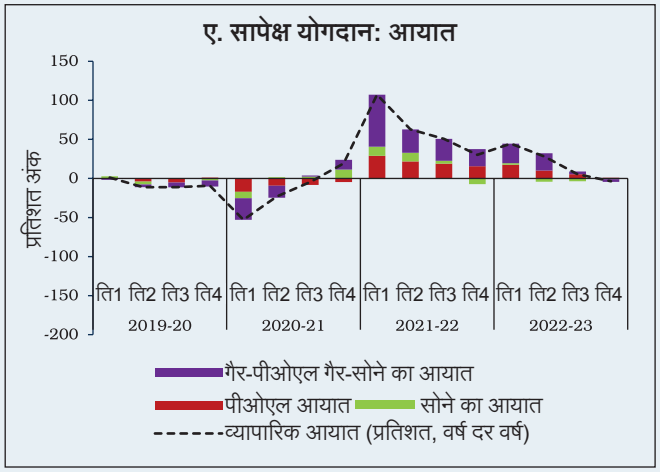

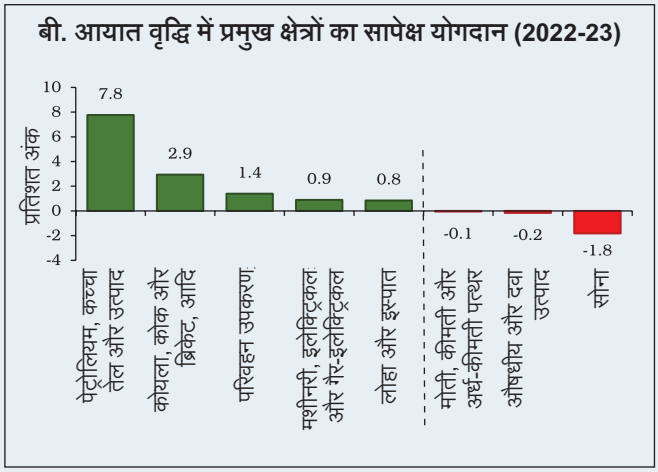

स्रोत: डीजीसीआई&एस

II.7.15 आयात पक्ष को देखें तो, 2022-23 में 714.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे भारत के व्यापारिक आयात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पण्य की कीमतों में कमी के कारण दूसरी छमाही में गिरावट देखी गई। अलग-अलग स्तर पर, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) आयात के प्रमुख चालक थे, इसके बाद कोयला, परिवहन उपकरण, मशीनरी और लोहा और इस्पात का स्थान था। दूसरी ओर, सोने ने आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट II.7.9)।

II.7.16 भारत के पीओएल आयात ने भारत की आयात बास्केट में सबसे बड़ी मद के रूप में योगदान किया, जो 2022-23 में कुल आयात का लगभग 29.3 प्रतिशत था। पीओएल आयात मूल्य के संदर्भ में 29.4 प्रतिशत और मात्रा के संदर्भ में 7.0 प्रतिशत बढ़ा, जो उच्च कीमतों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट II.7.10ए)।

II.7.17 2022-23 में भारत के कच्चे तेल के आयात के स्रोतों में परिवर्तन हुआ। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी एक साल पहले के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 19.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.7.10बी)।

II.7.18 2022-23 में सोने का आयात, 35.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहते हुए, लगभग 24.2 प्रतिशत घट गया।

चार्ट II.7.10: भारत का पेट्रोलियम निर्यात

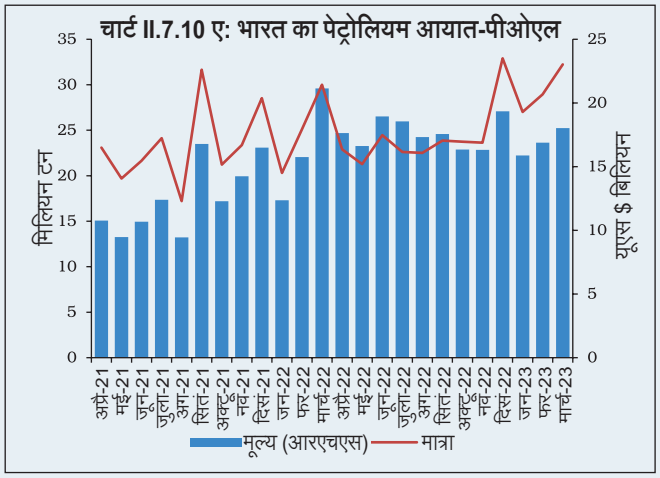

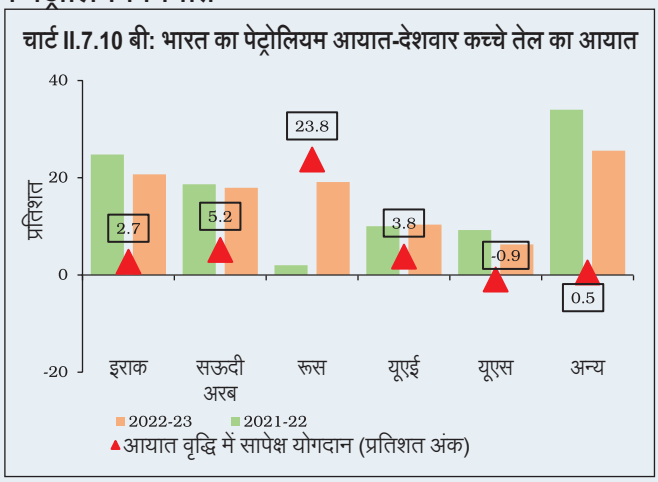

स्रोत: डीजीसीआई&एस

मांग को कम करने और व्यापार घाटे पर दबाव कम करने के लिए, भारत ने जुलाई 2022 में सोने पर मूल आयात शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया, जिसे बाद में फरवरी 2023 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने की उच्चतर कीमत के कारण खुदरा मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

II.7.19 2022-23 में कोयले का आयात मूल्य के संदर्भ में, 57.1 प्रतिशत बढ़ गया, जो उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों और बिजली क्षेत्र से गैर-कोकिंग कोयले की उच्च मांग से प्रेरित था। बिजली की बढ़ती मांग के कारण भारी कमी के मद्देनजर, सरकार ने मई 2022 में बिजली संयंत्रों को कोयले की अपनी आवश्यकता का 10.0 प्रतिशत आयात करने और इसे घरेलू आपूर्ति के साथ मिलाने की अनुमति दे दी। अगस्त में इस आपातकालीन आदेश को वापस ले लिया गया क्योंकि घरेलू कोयले की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ। भारत ने 2022-23 में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से कोयले का आयात किया (चार्ट II.7.11)।

II.7.20 2022-23 में भारत का उर्वरक आयात, जो वार्षिक घरेलू उर्वरक खपत का लगभग एक-तिहाई है, मूल्य के संदर्भ में लगभग 21.4 प्रतिशत बढ़कर, 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 46.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ जटिल उर्वरकों (जैसे डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)) ने उर्वरक आयात की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया (चार्ट II.7.12)। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार की अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए, भारत ने उर्वरक आयात के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और एक दीर्घकालिक कार्यनीति के रूप में वैश्विक कंपनियों से इसमें निवेश की मांग कर रहा है। इसके अलावा, यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार वाणिज्यिक यूरिया के विकल्प के रूप में किसानों के बीच नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

II.7.21 भारत वैश्विक स्तर पर वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, वनस्पति तेल पर भारत का आयात बिल 2022-23 में बढ़कर 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। घटक-वार देखें तो, इस आयात में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो भारत में कुल खाद्य तेल आयात का लगभग 63 प्रतिशत है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार, तेल वर्ष के दौरान अब तक (नवंबर 2022 से मार्च 2023) मात्रा के संदर्भ में भारत का खाद्य तेल आयात 70.6 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि है।

चार्ट II.7.11: भारत का कोयला आयात (2021-22 की तुलना में 2022-23)

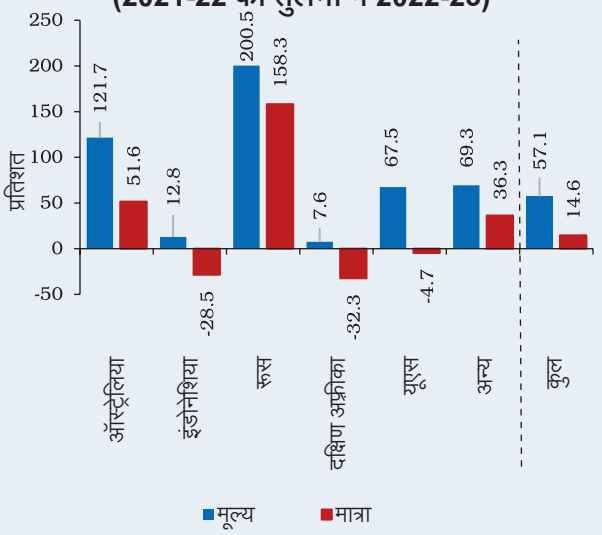

स्रोत: डीजीसीआई&एस

चार्ट II.7.12: भारत का उर्वरक आयात

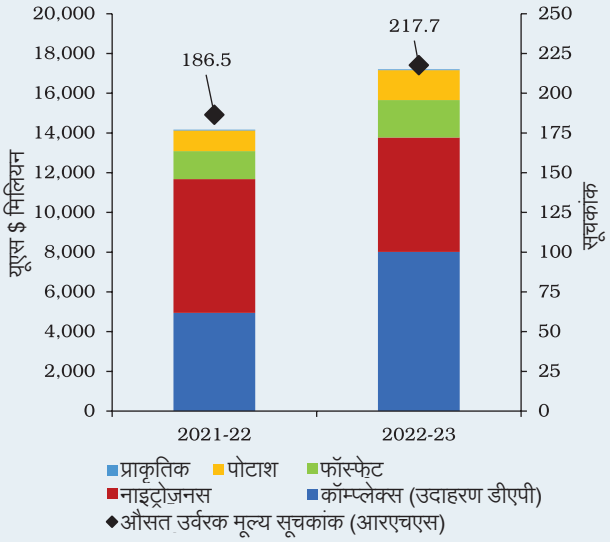

स्रोत: डीजीसीआई&एस और विश्व बैंक

चार्ट II.7.13 : इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात

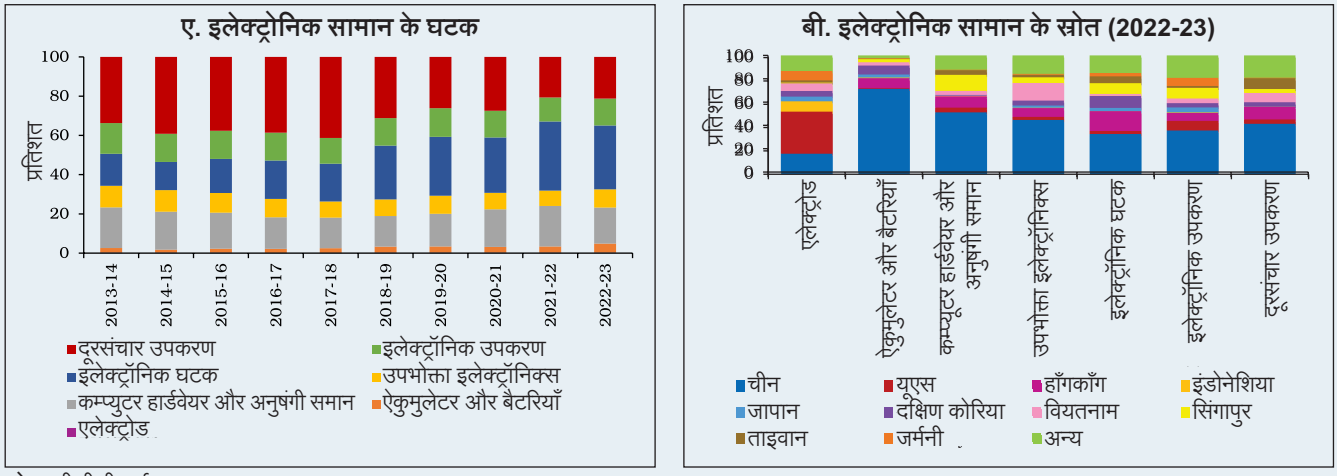

स्रोत: डीजीसीआई&एस

II.7.22 इलेक्ट्रॉनिक सामान, 2022-23 में लगभग 10.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, भारत की आयात बास्केट में दूसरा सबसे बड़ी आयात मद है। इसका आयात पिछले वर्ष की तुलना में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 77.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात की संरचना इलेक्ट्रॉनिक घटकों की ओर स्थानांतरित हो गई है, जो 2022-23 में कुल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात का लगभग 32.5 प्रतिशत था (चार्ट II.7.13ए)। आयात में दूरसंचार उपकरणों की हिस्सेदारी, 2017-18 में 41.3 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंचने के बाद, 2022-23 में गिरकर 21.2 प्रतिशत हो गई, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल से घरेलू विनिर्माण में वृद्धि हुई है।[39] चीन सभी घटकों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है (चार्ट II.7.13बी)।

चार्ट II.7.14 : भारत का पण्य व्यापार घाटा

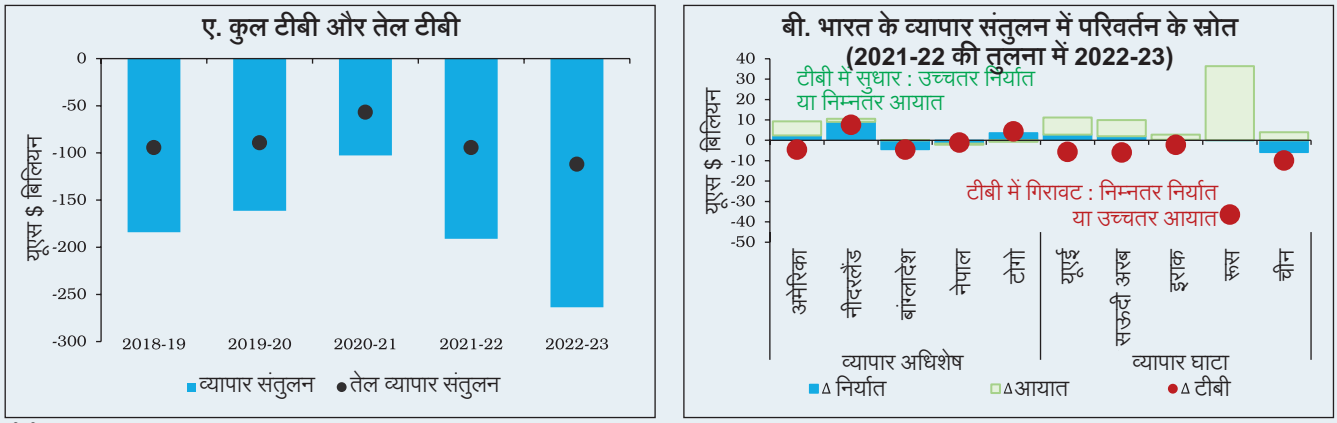

टीबी : व्यापार संतुलन
नोट : एक सकारात्मक Δ आयात का अर्थ कम आयात है और यह विलोमत: भी सही है।
स्रोत : डीजीसीआई&एस और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ

[39] इनमें से कुछ योजनाओं में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (2019), इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शामिल हैं।

II.7.23 चूंकि निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ा, व्यापार घाटा 2022-23 में 263.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 38.0 प्रतिशत अधिक था। तेल घाटा कुल घाटे का लगभग 42.5 प्रतिशत था (चार्ट II.7.14ए)। द्विपक्षीय आधार पर, प्रमुख भागीदार देशों के साथ घाटा बढ़ा (चार्ट II.7.14बी)।

4. अदृश्य मदें

II.7.24 सेवाओं, आय और हस्तांतरण में सीमा पार लेन-देन को दर्शाती अदृश्य मदों से निवल प्राप्तियों ने अप्रैल-दिसंबर 2022-23 के दौरान आघात-सहनीयता प्रदर्शित की। जहां एक ओर, सॉफ्टवेयर और कारोबार सेवाओं के निर्यात की मांग, जो भारत के सेवा निर्यात का लगभग 70.0 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान और साथ ही साथ पिछले वर्ष की तुलना में क्रमिक रूप से बढ़ती गई (चार्ट II.7.15), वहीं विप्रेषण प्राप्तियां भी सुदृढ़ रहीं। इस बीच, निवल निवेश आय बहिर्वाह में वृद्धि के बाद, वर्ष के दौरान प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में वृद्धि हुई।

II.7.25 2021-22 में उल्लेखनीय बहाली के बाद, अमेरिका और भारत को छोड़कर, सेवाओं का निर्यात करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक सेवा व्यापार 2022-23 के दौरान कुछ कमजोर हुआ (चार्ट II.7.16)। 2022 में, वैश्विक वाणिज्यिक

चार्ट II.7.15 : भारत के सेवा निर्यात की संरचना

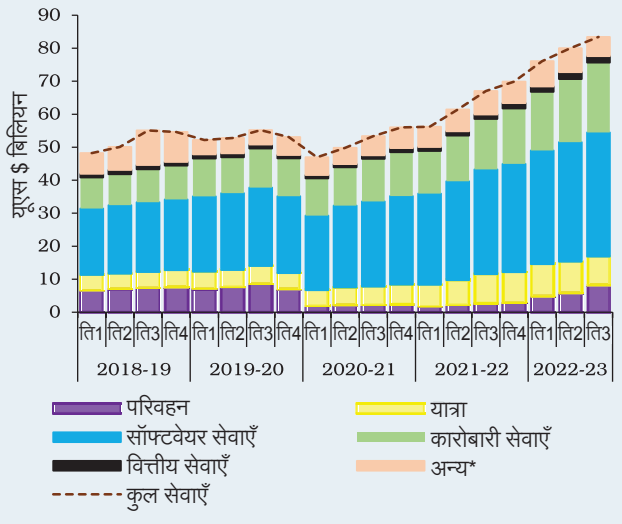

*इसमें संचार सेवाएँ और सरकार शामिल हैं, जिन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत : आरबीआई

चार्ट II.7.16 : सेवाओं के देश-वार निर्यात में वृद्धि

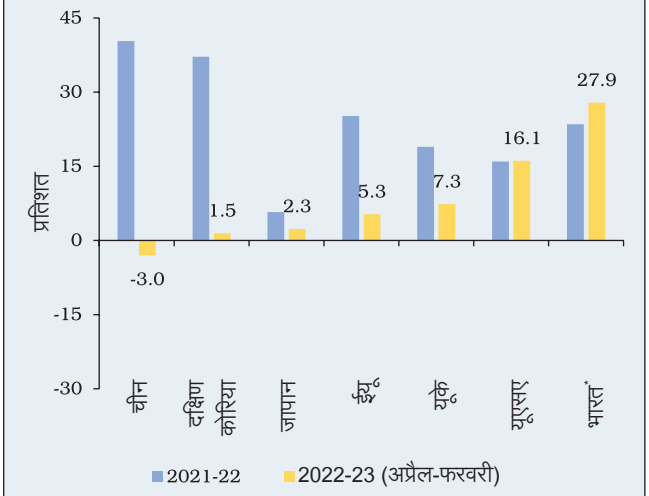

* डेटा (अनंतिम) अप्रैल-मार्च से संबंधित है।
स्रोत : डबल्यूटीओ और आरबीआई

सेवाओं के व्यापार का मूल्य 15.0 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (2021 में 17.0 प्रतिशत) बढ़ा, जो सभी क्षेत्रों और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित सभी प्रान्तों में व्यापक था। गार्टनर द्वारा प्रदत्त वैश्विक आईटी व्यय पूर्वानुमान के अनुसार, आईटी खर्च 2022 में रहे 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है, जो आगे चलकर भारत के सेवा निर्यात के लिए अच्छा संकेत है। बहरहाल, मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय संघ में मंदी की आशंकाओं के कारण अधोगामी जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत के सेवा निर्यात के लिए ये प्रमुख गंतव्य हैं।

II.7.26 कंप्यूटर, व्यापार और सूचना सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ, यात्रा और परिवहन प्राप्तियों में वृद्धि ने 2022 में विश्व स्तर पर सेवाओं के निर्यात को आघात-सहनीयता प्रदान की (चार्ट II.7.17ए और II.7.17बी)। गतिशीलता पर महामारी संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, 2022 में विश्व परिवहन और यात्रा सेवाओं में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 25.0 प्रतिशत और 79.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.7.27 2021-22 की पहली छमाही तक महामारी-पूर्व स्तरों पर पूरी तरह से बहाल हो जाने के बाद, भारत में आवक विप्रेषण में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई और अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के

चार्ट II.7.17ए : प्रमुख यात्रा गंतव्यों में यात्रा प्राप्तियां

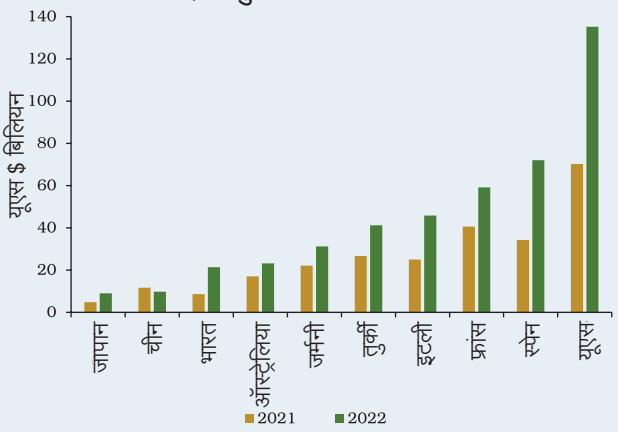

चार्ट II.7.17बी : प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्राप्तियाँ

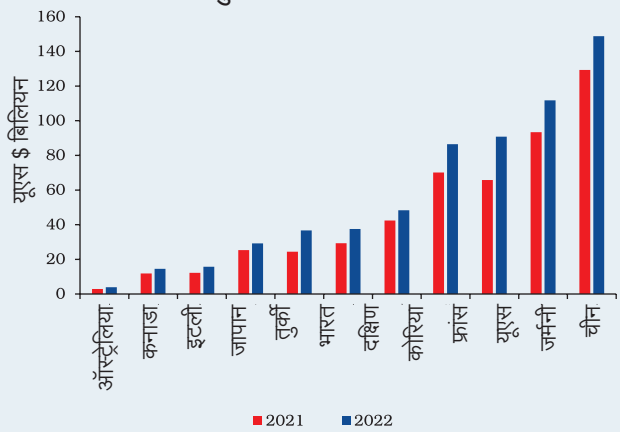

स्रोत : आरबीआई और विश्व बैंक

दौरान यह 83.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान यह 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट II.7.18ए)। 2022 में, भारत की आवक विप्रेषण प्राप्तियां, 2021 में रही 86.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर, 107.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं (चार्ट II.7.18बी)। भारत के विप्रेषण में वृद्धि कई कारकों से प्रेरित थी, जिसमें कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में भारतीय प्रवासियों को लाभान्वित करने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज और महामारी के बाद वेतन वृद्धि शामिल थी। इसके अलावा, टीकाकरण अभियान और यात्रा प्रतिबंधों में ढील ने मध्य-पूर्व में भारतीय प्रवासियों को अपने कार्यस्थलों पर लौटने और 2022 में काम फिर से शुरू करने में मदद की, जिसने भारत में विप्रेषण प्रवाह को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण भेजने की औसत लागत, 2020 की चौथी तिमाही में रही 5.5 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से सबसे अधिक) से घटकर, 2022 की तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत हो गई।

II.7.28 आय खाते के तहत, जो सीमापार निवेश और कर्मचारियों के मुआवजे पर आय से संबंधित है जो घरेलू निवासी

चार्ट II.7.18ए : यूएस $ 200 के विप्रेषण प्राप्त करने की लागत की तुलना में भारत में आवक विप्रेषण

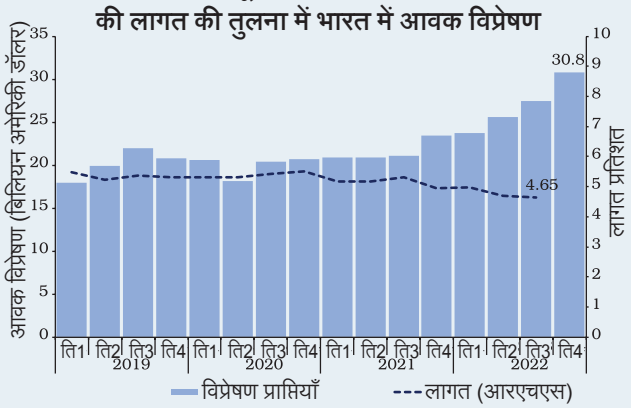

चार्ट II.7.18बी : प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में आवक विप्रेषण

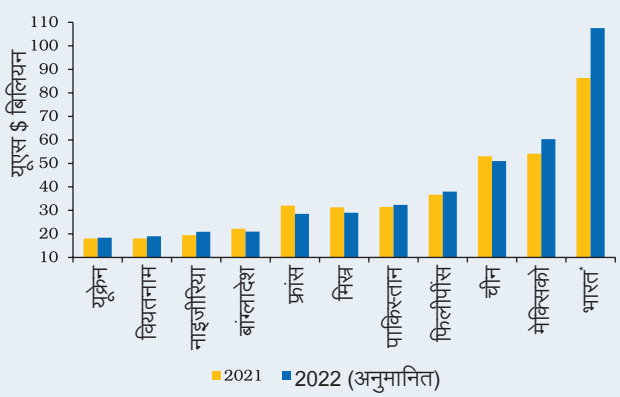

* भुगतान संतुलन (बीओपी) आधार

स्रोत : आरबीआई और विश्व बैंक

चार्ट II.7.19 ए : भारत के चालू खाता शेष की संरचना

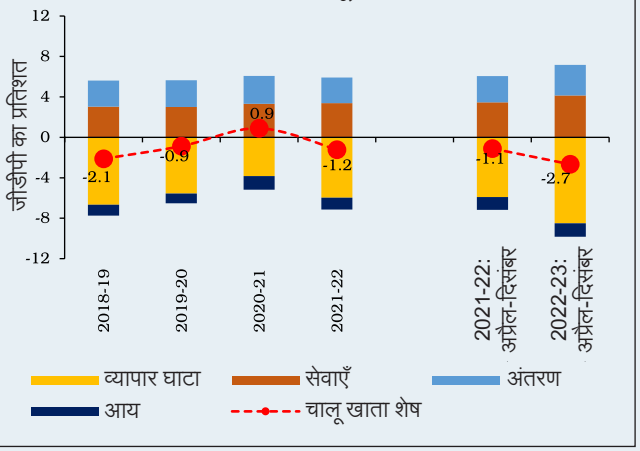

चार्ट II.7.19बी: वृद्धिशील चालू खाता शेष राशि के स्रोत

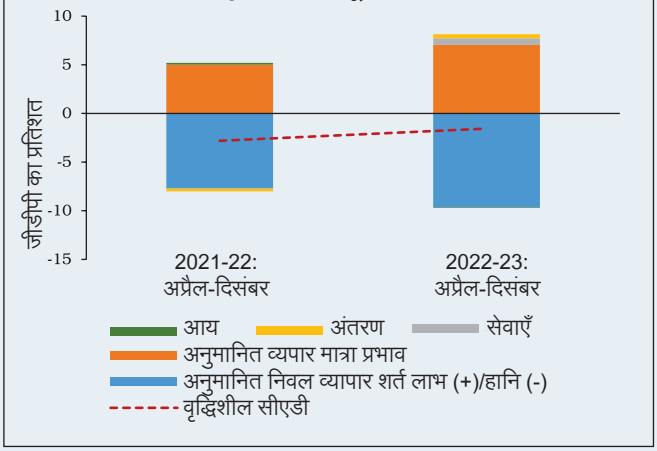

स्रोत : आरबीआई

संस्थाएं दुनिया के बाकी हिस्सों से कमाती हैं (या भुगतान करती हैं), अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि हुई। हालांकि, भुगतान एक साल पहले की तुलना में काफी अधिक था।

II.7.29 व्यापार घाटे में वृद्धि और प्राथमिक आय लेखा में निवल व्यय में वृद्धि ने भारत के चालू खाते में अनुक्रमिक वृद्धि को 2022-23 की पहली तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही तक, तीसरी तिमाही में कम होने से पहले, बढ़ा दिया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान चालू खाते का घाटा 2.7 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले के 1.1 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट II.7.19ए)। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण व्यापार की नकारात्मक निवल शर्तें और भारत के व्यापारिक भागीदारों में वृद्धि में मंदी की वजह से निर्यात में गिरावट के कारण व्यापार घाटे में बढ़ोतरी और घरेलू मांग में मजबूत सुधार के कारण उच्चतर आयात ने वर्ष के दौरान अब तक उच्चतर चालू खाते के घाटे में मुख्य रूप से योगदान दिया (चार्ट II.7.19बी)।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.7.30 अप्रैल-दिसंबर 2022-23 में, भारत के सीएडी में वृद्धि को देखते हुए, बाह्य वित्तपोषण की जरूरतों में काफी वृद्धि हुई। वित्तीय प्रवाह के प्रमुख घटकों में निवल एफडीआई मजबूत रहा, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया। इसके अलावा, अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के दौरान व्यापार ऋण और बैंकिंग पूंजी के रूप में ऋणों ने निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ने निवल बहिर्वाह दर्ज किया। वित्तीय लेखा में महत्वपूर्ण दबाव के कारण अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर (मूल्यांकन परिवर्तनों को छोड़कर) विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी $14.7 बिलियन की कमी आई थी [चार्ट II.7.20 और परिशिष्ट सारणी 8]।

चार्ट II.7.20: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

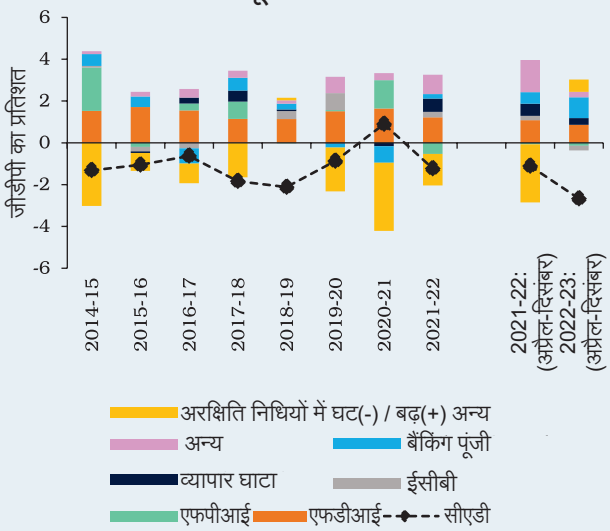

स्रोत : आरबीआई

सारणी II.7.2 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	43.0	44.0	38.6	28.0
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	56.0	54.9	56.2	41.6
1.1.1 सकल अंतर्वाह	74.4	82.0	84.8	71.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/ विनिवेश	18.4	27.0	28.6	29.3
1.2 निवल जावक एफडीआई	13.0	11.0	17.6	13.6

स्रोत : आरबीआई

चार्ट II.7.21 : एफडीआई (इक्विटी) का स्रोत देश-वार अंतर्वाह

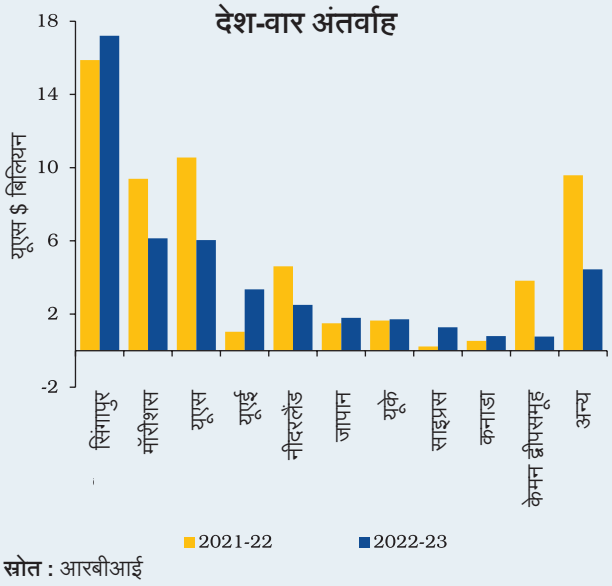

स्रोत : आरबीआई

II.7.31 पूंजी प्रवाह के भीतर, निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक *घटा* निवल जावक) 2022-23 के दौरान अमेरिकी $28.0 बिलियन (एक साल पहले अमेरिकी $38.6 बिलियन) पर रहते हुए मजबूत रहा। इस अवधि के दौरान भारत में एफडीआई के प्रत्यावर्तन/विनिवेश में वृद्धि हुई, जबकि भारत द्वारा जावक एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई (सारणी II.7.2)। यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट (जून 2022) के अनुसार, भारत 2021 में एफडीआई का 7$^{वां}$ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (2020 में 8$^{वां}$) था। विभिन्न सरकारी पहलों, जैसे पीएम *गति शक्ति*, पीएलआई योजना को और बढ़ाने और हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए एक मजबूत जोर के कारण विदेशी कंपनियों से अधिक एफडीआई आकर्षित होने की उम्मीद है। 2022-23 के दौरान, शीर्ष एफडीआई स्रोत देश सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड थे, जिन्होंने कुल एफडीआई इक्विटी में 76.5 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट II.7.21)। क्षेत्र-वार संरचना इंगित करती है कि इस अवधि के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा रहा, इसके बाद विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, बिजली और अन्य ऊर्जा, और शिक्षा, अनुसंधान और विकास का स्थान रहा (परिशिष्ट सारणी 9)।

II.7.32 भारत से जावक एफडीआई में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2022-23 के दौरान 22.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस भारत से बाहरी एफडीआई के प्रमुख गंतव्य थे। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार, और रेस्तरां और होटल इस अवधि के दौरान भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

II.7.33 उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक सख्ती किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत सहित प्रमुख ईएमई में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने 2022-23 में बहिर्वाह दर्ज किया। हालांकि, 2022-23 की पहली तिमाही में निवल विक्रेता होने के बाद, एफपीआई जुलाई 2022 से घरेलू बाजारों, विशेष रूप से इक्विटी में निवल खरीदार बन गए (चार्ट II.7.22)।

II.7.34 इक्विटी बाजार में एफपीआई प्रवाह मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, रसायन और विनिर्माण सामग्री क्षेत्रों में दर्ज किया गया था (चार्ट II.7.23)। 2022-23 के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई के लिए निवेश सीमा का कम उपयोग किया गया। मार्च 2023 के अंत तक, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में सीमा (सामान्य मार्ग) का केवल 18.9 प्रतिशत उपयोग किया गया था (मार्च 2022 के

चार्ट II.7.22 : भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह

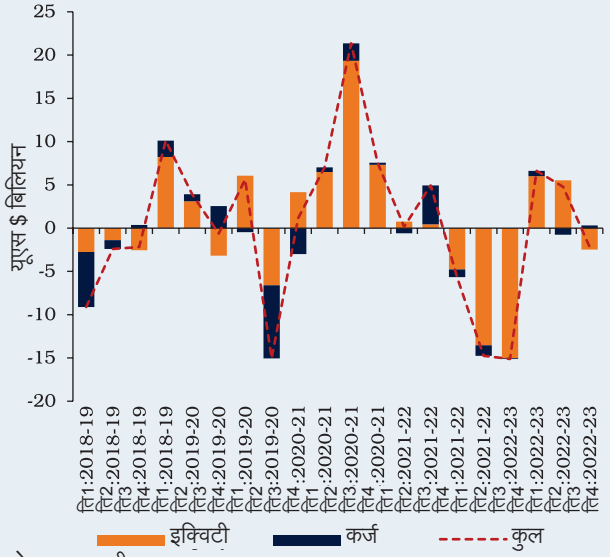

स्रोत : एनएसडीएल

चार्ट II.7.23 : इक्विटी बाजार में एफपीआई के एक्सपोजर में बदलाव

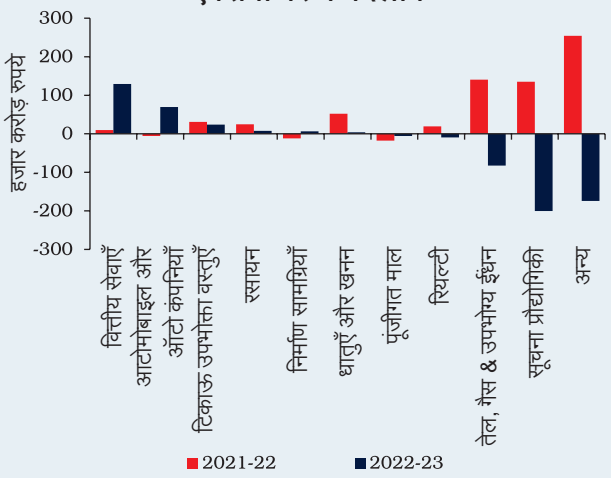

नोट : अन्य में तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, दूरसंचार और उपभोक्ता सेवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

स्रोत : एनएसडीएल

अंत में 26.3 प्रतिशत), जबकि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के लिए उपयोग दर एक प्रतिशत से नीचे रहते हुए बहुत ही कम रही। एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोली गई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के कुल मूल्य में से मार्च 2023 के अंत तक एफपीआई के पास 2.7 प्रतिशत (मार्च 2022 के अंत में 2.6 प्रतिशत) था। कॉरपोरेट बॉण्ड खंड में एफपीआई की रुचि, अन्य बातों के साथ-साथ अमेरिका में प्रतिफल दरों में वृद्धि के कारण कम रही (बॉक्स II.7.2)। मार्च 2023 के अंत तक कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई के लिए सीमा का केवल 15.5 प्रतिशत (पूर्ण रूप से) उपयोग किया गया था, जो मार्च 2022 के अंत में 19.9 प्रतिशत से कम था।

बॉक्स II.7.2
पूंजी प्रवाह की ब्याज दर संवेदनशीलता : भारतीय अनुभव

अमेरिका में मौद्रिक नीति में बदलाव ईएमई के लिए पूंजी प्रवाह के प्रमुख निर्धारकों में से एक रहा है (कोपके, 2019) । हालांकि, इसका असर ईएमई में उनकी घरेलू समष्टि आर्थिक नीतियों, विदेशी ऋण के स्तर, राजकोषीय घाटे और भंडार के आधार पर अलग-अलग होता है। यद्यपि, सैद्धांतिक रूप से ब्याज दर अंतर पूंजी अंतर्वाह का एक प्रमुख निर्धारक बना हुआ है, लेकिन व्यवहार में अनुभवजन्य निष्कर्ष अलग होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत के सकल पूंजी अंतर्वाह के विभिन्न घटकों की ब्याज दर संवेदनशीलता का एक अनुभवजन्य विश्लेषण किया जाता है, जिसमें 1999 की दूसरी तिमाही से 2022 की दूसरी तिमाही तक त्रैमासिक आंकड़ा शामिल होता है। निवल प्रवाह के बजाय सकल पूंजी अंतर्वाह का उपयोग विश्लेषण के लिए किया गया है क्योंकि किसी देश की निवल स्थिति अक्सर इसकी वित्तीय कमजोरियों का विश्वसनीय संकेतक नहीं हो सकती है।

ब्याज दर अंतर (आईआरडी) के लिए सकल पूंजी अंतर्वाह की संवेदनशीलता का पता लगाने के लिए, वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) मॉडल का अनुमान वर्मा और प्रकाश (2011) का अनुसरण करके लगाया जाता है, और आईएनआर-यूएसडी नाममात्र विनिमय दर में परिवर्तन, घरेलू वास्तविक जीडीपी वृद्धि और ओईसीडी जीडीपी वृद्धि द्वारा वैश्विक जीडीपी वृद्धि जैसे बहिर्जात चर को नियोजित किया जाता है। इसके अलावा, पूंजी प्रवाह के विभिन्न घटकों पर आईआरडी के प्रभाव की जांच करने में - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई), अल्पकालिक

(जारी)

सारणी 1: ब्याज दर अंतर में परिवर्तन के बीच कारण संबंध और सकल पूंजी अंतर्वाह में परिवर्तन

नल हाइपोथीसिस	*प्रतिदर्श अवधि*	*ची-वर्ग*	*संभाव्यता*
आईआरडी ग्रेंजर कॉज़ एफपीआई नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	4.89	0.09
एफपीआई ग्रेंजर कॉज़ आईआरडी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	1.47	0.48
आईआरडी ग्रेंजर कॉज़ एसटीसी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	6.72	0.03
एसटीसी ग्रेंजर कॉज़ आईआरडी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	0.34	0.84
आईआरडी ग्रेंजर कॉज़ ईसीबी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	7.09	0.03
ईसीबी ग्रेंजर कॉज़ आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	2.71	0.26
आईआरडी ग्रेंजर कॉज़ बीसी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	10.62	0.00
बीसी ग्रेंजर कॉज़ आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	1.42	0.49
आईआरडी ग्रेंजर कॉज़ एफडीआई नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	0.65	0.72
एफडीआई ग्रेंजर कॉज़ आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	5.51	0.06

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

व्यापार ऋण (एसटीसी), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बैंकिंग पूंजी (बीसी) प्रवाह और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) - आईआरडी के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि नियोजित किए गए हैं।[40] वीएआर ढांचे के आधार पर ग्रेंजर कार्य-कारण परीक्षणों के अनुसार पूंजी प्रवाह के विभिन्न घटकों के लिए आईआरडी से कार्य-कारण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया (सारणी 1)।[41]

चार्ट 1 : आईआरडी में परिवर्तन के लिए सकल पूंजी अंतर्वाह के विभिन्न घटकों की संवेदनशीलता

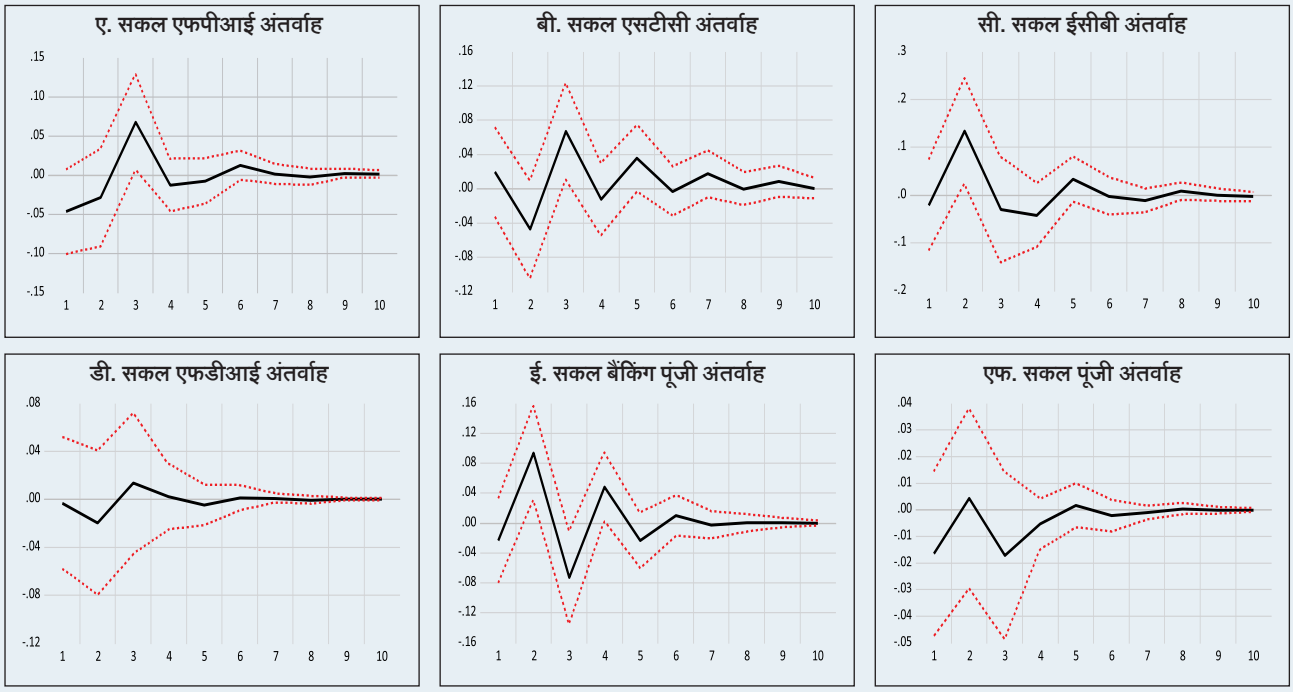

नोट: चार्ट वीएआर मॉडल के आधार पर सामान्यीकृत आईआरएफ (एक एसडी नवाचार ± 2 विश्लेषणात्मक अलाक्षणिक मानक त्रुटियां) का संकेत देते हैं; काली रेखाएं आईआरएफ का संकेत देती हैं; लाल बिंदीदार रेखाएं 95 प्रतिशत कॉन्फिडेंस इन्टर्वल का संकेत देती हैं।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

[40] विशेष रूप से, तिमाही औसत घरेलू नीति रेपो दर और अमेरिकी संघीय निधि दर के बीच अंतर का उपयोग एफपीआई और एसटीसी के मामले में आईआरडी के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया गया था। इसी तरह, 10-वर्षीय भारत सरकार बॉण्ड प्रतिफल और 10-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल के बीच के अंतर को ईसीबी के मामले में आईआरडी प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और 91-दिवसीय भारत सरकार ट्रेजरी बिल (टीबी) प्रतिफल और यूएस 3-महीने की टीबी उपज के बीच के अंतर को बीसी प्रवाह के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियोजित किया गया था। अंत में, एफडीआई, प्रकृति में दीर्घकालिक होने के नाते, 10 साल के भारत सरकार के बॉण्ड प्रतिफल और 10 साल के अमेरिकी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल के बीच का अंतर इस मामले के लिए आईआरडी माना गया था।

[41] माना जाने वाला द्विभिन्नरूपी वीएआर मॉडल निम्नानुसार है: {Δ (ब्याज दर अंतर$_t$), Δ(सकल पूंजी प्रवाह$_t$)}, जहां Δ तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन को इंगित करता है। उल्लिखित नियंत्रणों को प्रकृति में बहिर्जात माना जाता था। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2013-14 के टेपर टैंट्रम के लिए पीरियड डमी पर भी विचार किया गया था।

वीएआर मॉडल से सामान्यीकृत आवेग प्रतिक्रिया कार्य (आईआरएफ) इंगित करते हैं कि: (i) आईआरडी में परिवर्तन और सकल एफपीआई, एसटीसी, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी प्रवाह में वृद्धि के बीच 1-2 तिमाहियों के अंतराल के साथ सकारात्मक संबंध है (चार्ट 1); (ii) आईआरडी में परिवर्तन के लिए एक मानक विचलन (एसडी) आघात से सकल एफपीआई अंतर्वाहों में 0.07 प्रतिशत, सकल एसटीसी अंतर्वाह में 0.07 प्रतिशत, सकल ईसीबी अंतर्वाह में 0.13 प्रतिशत और सकल बैंकिंग पूंजी अंतर्वाह में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि होती है; (iii) सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह आईआरडी के प्रति संवेदनशील प्रतीत नहीं होते हैं; और (iv) आईआरडी में परिवर्तन का सकल पूंजी प्रवाह पर समग्र स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

संक्षेप में, विश्लेषण इंगित करता है कि ब्याज दर अंतर पोर्टफोलियो, व्यापार वित्तपोषण और ईसीबी प्रवाह को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन भारत में समग्र सकल पूंजी अंतर्वाह को यह प्रभावित नहीं करता है।

संदर्भ:

1. कोपके, आर. (2019), 'व्हाट ड्राइव्स कैपिटल फ्लोव्स टू ईमरजिंग मार्केट्स? ए सर्वे ऑफ द एम्पिरिकल लिटरेचर', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक सर्वेज, 33(2), 516-540.
2. वर्मा आर., एंड प्रकाश, A. (2011), 'सेंसिटिविटी ऑफ कैपिटल फ्लोव्स तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स: एन एम्पिरिकल असेसमेंट फॉर इंडिया', रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज़, मे 2011.

II.7.35 ईसीबी ने एक साल पहले की तुलना में 2022-23 के दौरान ईसीबी करारों की संख्या के साथ-साथ राशि के मामले में भी गिरावट दर्ज की। इसके अलावा, भारत में निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में 2022-23 में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ था (चार्ट II.7.24)। 6 जुलाई, 2022 को, रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को उदार बनाने के उपायों के तहत, ईसीबी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उधार सीमा 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई थी। इसके अलावा, ईसीबी ढांचे के तहत समग्र-लागत सीमा में भी 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो। ये उपाय 31 दिसंबर, 2022 तक प्रभावी थे।

II.7.36 ईसीबी संवितरण का उपयोग, बड़े पैमाने पर ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, नई परियोजनाओं, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं के लिए रुपये के व्यय के लिए, किया गया था (चार्ट II.7.25)। ईसीबी के भीतर, रुपये में अंकित ऋण और रुपया-मूल्य वाले बॉण्ड (आरडीबी), 2022-23 के दौरान कुल समझौते की राशि का 8.0 प्रतिशत था, जो एक साल पहले 8.4 प्रतिशत था। इसके अलावा, बचाव (हेज) किए गए विदेशी मुद्रा ऋण का हिस्सा वर्ष के दौरान 49.3 प्रतिशत था, जो 2021-22 के दौरान 51.6 प्रतिशत से अधिक था।

II.7.37 अप्रैल-दिसंबर 2022 में अल्पकालिक व्यापार ऋण का निवल अंतर्वाह 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि एक साल पहले 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ था। कच्चे तेल, सोने, कोयला और तांबे के आयात के लिए लगभग 36.0 प्रतिशत व्यापार ऋण जुटाया गया था।

II.7.38 अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमाराशियां, जो कुल बकाया अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों का लगभग 69.2 प्रतिशत थीं, में 2022-23 के दौरान 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह देखा गया, जो एक वर्ष पहले

चार्ट II.7.24: भारत की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (निवल)

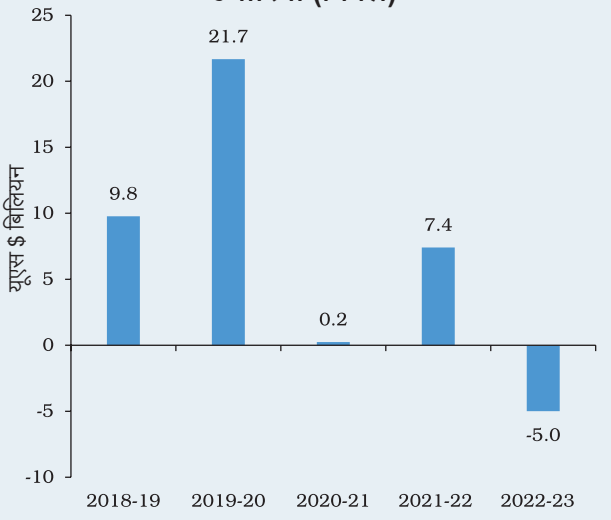

स्रोत : आरबीआई

चार्ट II.7.25: 2022-23 के दौरान ईसीबी का अंतिम उपयोग

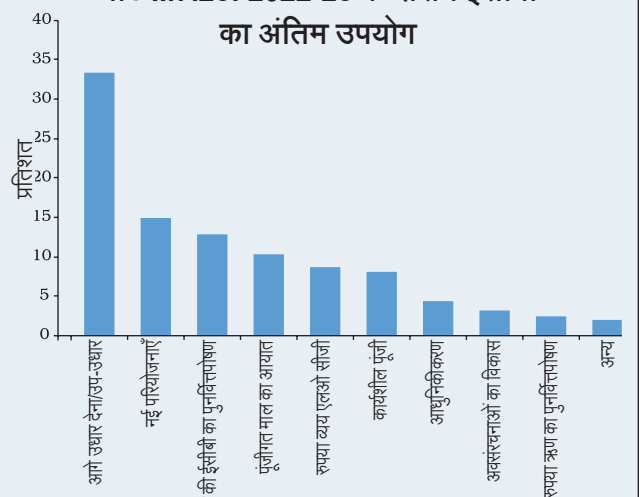

एलओ सीजी : स्थानीय पूंजीगत माल
स्रोत : आरबीआई

रहे 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है (सारणी II.7.3)। विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में निवल अंतर्वाह 2.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर था, जबकि एक साल पहले 3.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर का मोचन हुआ था। इसके अलावा, अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों ने भी वर्ष के दौरान मजबूत शुद्ध प्रवाह दर्ज किया। कुल मिलाकर, एनआरआई खातों ने एक साल पहले के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 के दौरान 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, ब्याज दरों के विनियमन और एफसीएनआर (बी) और एनआरई खातों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) रखरखाव से छूट से संबंधित एनआरआई खातों के संबंध में 6 जुलाई, 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए पूंजी अंतर्वाह उपायों ने भी इन खातों में उच्च निवल अंतर्वाह में सहायता की।

6. सुभेद्यता संकेतक

II.7.39 भारत के विदेशी ऋण में मार्च 2022 के अंत की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी, 1.0 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई; सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, यह इसी अवधि के दौरान 20.0 प्रतिशत से घटकर 19.1 प्रतिशत हो गया (सारणी II.7.4)। भारत का विदेशी ऋण (जीडीपी के अनुपात के रूप में) भी अधिकांश उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम रहा। वाणिज्यिक उधार 35.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद अनिवासी जमा (21.9 प्रतिशत) और अल्पकालिक व्यापार ऋण (20.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। बाहरी ऋण की क्षेत्र-वार संरचना इंगित करती है कि गैर-वित्तीय निगम 41.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ उधारकर्ताओं की सबसे बड़ी श्रेणी थे, इसके बाद केंद्रीय बैंक (25.1 प्रतिशत) और सामान्य सरकार (21.0 प्रतिशत) को छोड़कर, जमा लेने वाले निगम थे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी जोखिमों और प्रभाव-विस्तार को कम करने के लिए एक बफर भी प्रदान किया। दिसंबर-2022 के अंत में, विदेशी मुद्रा भंडार अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण के दो गुना से अधिक था और इसने 2022-23 के लिए अनुमानित 9.4 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

सारणी II.7.3 : अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	5.6	8.8	3.3	2.1
2. अनिवासी साधारण खाता	2.0	2.3	3.5	3.4
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.1	-3.8	-3.6	2.4
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	**8.6**	**7.4**	**3.2**	**8.0**

स्रोत : आरबीआई

सारणी II.7.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2021	2022	दिसंबर के अंत में 2022
1	2	3	4	5
1. जीडीपी में बाहरी कर्ज का अनुपात	22.4	21.2	20.0	19.1
2. कुल कर्ज में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	17.6	19.7	21.1
3. कुल कर्ज में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	44.1	43.2	44.5
4. कुल कर्ज में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	9.0	8.3	8.1
5. कुल कर्ज में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	100.6	98.1	91.8
6. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	17.5	20.0	23.0
7. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	43.8	44.0	48.5
8. आयात का रिजर्व कवर (महीनों में)*	7.0	17.4	11.8	9.3
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में)	5.9	8.2	5.2	5.3
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	573.7	619.1	613.1
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-355.1	-358.3	-374.5
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-13.2	-11.7	-11.8
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	0.9	-1.2	-2.7

*: बीओपी आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य आयातों पर आधारित।
#: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2022 से संबंधित है।
स्रोत : आरबीआई और भारत सरकार।

II.7.40 मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2022 के अंत से 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें से 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण थी।

7. निष्कर्ष

II.7.41 पूंजी अंतर्वाह को सुस्त करने वाले जोखिम-विमुख रुझान (रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट्स) के माहौल में बढ़ते चालू खाता घाटे के बारे में वर्ष की पहली छमाही में बाजारगत चिंताओं के बावजूद, भारत का चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में शीर्ष पर पहुंचने के बाद धारणीय स्तर के भीतर रहा और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव व्यवस्थित रहा। बाह्य सुभेद्यता संकेतकों ने आघात-सहनीयता प्रदर्शित किया और सुदृढ़ होते घरेलू समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों ने अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल वैश्विक समष्टि-वित्तीय आघातों से उत्पन्न प्रभाव-विस्तार का सामना करने में सहायता प्रदान की। हालांकि, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमई, विशेष रूप से भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में संवृद्धि में मंदी की संभावना, ऊर्जा की अब भी ऊंची कीमतों, यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति के भविष्यगत रुख और संघर्ष-ग्रस्त भू-राजनीतिक माहौल में आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के चलते, भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय अधोगामी जोखिम बने हुए हैं।